गुवाहाटी व जोरहाट से एक साथ प्रकाशित

सच से समझौता नहीं

प्रातः खबर

www.pratahkhabar.com

RNI NO. ASSHIN/2005/15049 PRATAH KHABAR, Guwahati, Thursday, 23 July, 2026 वर्ष 23 अंक 83, गुवाहाटी, गुरुवार 23 जुलाई, 2026, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष-9 मूल्य : दस रुपये पेज-12

वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड-10

मौनी संग डेटिंग की अफवाहों पर भड़के अर्जुन-12

सीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा शिवसागर के बेंतबाड़ी आलिमुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए, वहीं नाजिरा के राहत शिविर में आश्रय लिये लोगों से बात करते हुए।

- 35 मौत की हुई पुष्टि
- सौ के करीब लापता
- चार लाख के मुआवजे का एलान

गुवाहाटी, 22 जुलाई (भा)। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में आने से पिछले 24 घंटे में 24 और लोगों की मौत हो गयी, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गयी है। बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने गए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इसकी पुष्टि की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सौ के करीब लोग लापता है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। राज्य में बाढ़ से लगभग 5.65 लाख लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने असम के ऊपरी जिलों में विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने शिवसागर में संवाददाताओं से कहा कि बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। मैंने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया है कि वे इस संकट में अकेले नहीं हैं। हमारी सरकार पुनर्वास और आजीविका के पुनर्निर्माण के हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित लोगों के एक बड़े वर्ग द्वारा राहत सामग्री न मिलने की शिकायतों पर शर्मा ने कहा कि पानी में डूबे गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अब भी अपने घरों में हैं, उन तक पहुंचने के लिए कोई सड़क या संचार का कोई माध्यम नहीं बचा है। प्रशासन इस बात को स्वीकार करता है। हम कई जगहों पर नहीं पहुंच पाये हैं। जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होगा, हम उन इलाकों तक पहुंच सकेंगे। हम इस समय विमान से राहत सामग्री को भी नहीं गिरा सकते। हम लोगों की दिक्कतों को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा कि जो लोग राहत शिविरों तक पहुंच गये हैं, उनके लिए राहत सामग्री के वितरण में कोई कमी या समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक मृतक के रिश्तेदारों या परिवारों को तुरंत चार लाख रुपये की राहत राशि देंगे। मैं भविष्य में भी उनकी मदद करने का प्रयास करूंगा। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ में डूबने से कुल 24 लोगों की मौत हो गयी है। इनमें से शिवसागर जिले में चार महिलाओं और दो बच्चों समेत 14 लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गयी। इसके अलावा चराइदेव में दो बच्चों समेत छह, गोलाघाट में दो और जोरहाट में एक महिला की जान चली गयी। प्राधिकरण द्वारा कल मध्यरात्रि जारी दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार विश्वनाथ, चराईदेव, धेमाजी, डिब्रुगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कामरूप महानगर, कार्बी आंगलांग, नगांव, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों में 5,64,600 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर बाढ़ से सबसे अधिक शेष पृष्ठ आठ पर

असम में 60 वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ : पीयूष

सदन स्थगन प्रस्तावना नामंजूर

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। असम सरकार ने आज राज्य के पूर्वी जिलों में आयी बाढ़ को एक अभूतपूर्व आपदा करार देते हुए विधानसभा को बताया कि प्रभावित इलाकों में बीते छह दशकों से अधिक समय में ऐसी भीषण बाढ़ नहीं देखी गयी है। सदन में बाढ़ की स्थिति पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जैसे जिलों में, जहां आमतौर पर इस पैमाने पर बाढ़ नहीं आती, पड़ोसी राज्य नगालैंड में बादल फटने के बाद अचानक आए भारी जलप्रवाह से प्रशासन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह केवल एक शेष पृष्ठ आठ पर

अजमल ने की एक करोड़ बाढ़ राहत राशि की घोषणा

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। ऊपरी असम में बाढ़ से मची भारी तबाही के बीच एआईयूडीएफ सुप्रीमो और विधायक बदरुद्दीन अजमल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपये की आपातकालीन वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। विधानसभा में इस राहत राशि का ऐलान करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मदद अजमल फाउंडेशन के माध्यम से दी जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित इलाकों में लोगों को तुरंत राहत पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस राहत राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तक किया जाएगा। इस घोषणा के तुरंत बाद बदरुद्दीन अजमल खुद जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रवाना हो गये हैं। अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान वे जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव जिलों में जाकर प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और स्वयं राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए स्पष्ट किया कि संकट की इस घड़ी में बिना किसी भेदभाव के सभी प्रभावित हिंदू और मुस्लिम परिवारों को समान रूप से सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई व प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर तकरार

संसद परिसर के बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते विपक्षी सांसद।

दोनों सदन स्थगित

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भा)। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भी विपक्षी दलों के सदस्यों के संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। इस वजह से लोकसभा दो बार के स्थगन के बाद वहीं राज्यसभा तीन बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। हंगामे की वजह से आज भी दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सरकार ने कहा कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस सदस्य कल्याण बनर्जी को सदन में कुछ महिला सदस्यों से अभद्रता को लेकर चालू सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार शेष पृष्ठ आठ पर

राहुल की केंद्र से तीन डिमांड

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (एजें)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं और उनका पूरा समर्थन है। राहुल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नाकाम बताते हुए कहा कि हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। साथ ही साथ पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार सदन में चर्चा करे और छात्रों के साथ हुए बर्बरातपूर्ण रवैये को लेकर पीएम मोदी भी माफी मांगे। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। पेपर लीक की वजह से करोड़ों की संख्या में छात्रों और उनके परिवार को परेशानी उठानी पड़ी है। राहुल गांधी ने कहा शेष पृष्ठ आठ पर

छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना करेंगे आंदोलन, पीएम को लिखा पत्र

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (एजें)। नीट पेपर लीक को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर छात्र और विपक्ष अड़ा हुआ है। दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोज जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद चलो मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अहिल्यानगर के वाडिया पार्क स्थित गांधी स्मारक पर मौन आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में दमन नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाए। अन्ना हजारे ने कहा कि पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी चिंताजनक है। छात्रों के आंदोलन को कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि जनभावना का मुद्दा मानना चाहिए। सरकार छात्रों और आंदोलनकारियों के साथ सकारात्मक संवाद करे। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा अन्ना हजारे का कहना है कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लोकतंत्र में संवाद के बजाय दमन का रास्ता अपनाये जाने पर अन्ना हजारे ने चिंता व्यक्त की। अन्ना हजारे के आंदोलन स्थल को प्रतीकात्मक रूप से नगर का जंतर-मंतर नाम दिया जाएगा। करने की अपील की. जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। इसी बीच सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हमारा समय कीमती है और हम केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से तभी मुलाकात करेंगे, जब वे हमारी मांगों को शेष पृष्ठ आठ पर

सुप्रभातम्

दूसरों की प्रगति देखकर अपनी यात्रा को कम मत आंकें, हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है।

सिक्किम : सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए अभियान जारी

नामची, 22 जुलाई (भा)। सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी की तीस्ता चरण छह पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग ढहने से फंसे लोगों को निकालने के लिए खोज एवं बचाव अभियान बुधवार को फिर से शुरू कर दिया गया। सुरंग के अंदर कीचड़ और पानी भर जाने के कारण यह अभियान कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और आसनसोल बचाव दल के कर्मियों ने आज सुबह फिर से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया और उनका मुख्य ध्यान सुरंग से पानी बाहर निकालने पर है। दक्षिण शेष पृष्ठ आठ पर

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, पुलिसकर्मी की गयी जान

श्रीनगर, 22 जुलाई (भा)। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग शहर में आज आतंकवादियों के हमले में एक पुलिसकर्मी की जान चली गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गोलीबारी आज दोपहर करीब 12.30 बजे अनंतनाग के लाल चौक पर हुई। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात हवलदार आशिक हुसैन हमले में घायल हो गये और उन्हें अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने हुसैन को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों का पता लगाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है।

10 वर्षों में 2,089 विदेशी नागरिक भेजे गये स्वदेश

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। असम समझौता क्रियान्वयन विभाग के मंत्री अतुल बोरा ने सदन में बताया कि पिछले एक दशक में असम से विभिन्न देशों के 2,089 नागरिकों को उनके अपने देश वापस भेजा गया है, जिनमें बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या सबसे अधिक 2,023 है। आज असम विधानसभा में कांग्रेस विधायक अब्दुर रहीम अहमद के पूछे गये सवाल के लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2016 से 30 जून 2026 तक निर्वासित किये गये कुल 2,089 लोगों में बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के 39, नाइजीरिया के 18, अफगानिस्तान, यूक्रेन और माली के 2-2 नागरिक, जबकि पाकिस्तान, कीनिया और युगांडा के 1-1 नागरिक शामिल हैं। वर्ष 2016 में 13 और 2017 में 26 लोगों को वापस भेजा गया था। 2018 में यह संख्या बढ़कर 65 हुई, जिसमें बांग्लादेश के 52, म्यांमार के 9, अफगानिस्तान के 2 तथा पाकिस्तान और नाइजीरिया का 1-1 नागरिक शामिल था। इसके बाद 2019 में कुल 87 विदेशी नागरिकों को स्वदेश भेजा गया, जिनमें 78 बांग्लादेश और 9 म्यांमार से थे। वर्ष 2020 में भेजे गये 69 लोगों में 48 बांग्लादेशी और 21 म्यांमार के नागरिक थे, जबकि 2021 में वापस भेजे गये सभी 33 लोग बांग्लादेश के ही निवासी थे। आगे के वर्षों में 2022 के दौरान कुल 63 नागरिकों को वापस भेजा गया, जिनमें बांग्लादेश के 44, नाइजीरिया के 16, यूक्रेन के 2 और कीनिया का 1 नागरिक शामिल था। वर्ष 2023 में निर्वासित किये गये 51 लोगों में 50 बांग्लादेश के और 1 युगांडा का नागरिक था, वहीं 2024 में वापस भेजे गये सभी 8 लोग बांग्लादेशी थे। वर्ष 2025 में इस संख्या में अचानक भारी उछाल दर्ज किया गया, जब अकेले एक ही साल में 1,811 शेष पृष्ठ आठ पर

असम के किसान मखाना खेती के प्रशिक्षण के लिए जाएंगे बिहार

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। असम के किसान बिहार का दौरा कर मखाना उगाने की उन्नत तकनीक और पारंपरिक विधियां सीखेंगे। मखाना उत्पादन की विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद वे असम की बेकार पड़ी जमीन और प्राकृतिक जल निकायों में इसकी खेती शुरू करेंगे। कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने आज सदन में भाजपा विधायक पवित्र राभा के प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान राज्य के 9 जिलों कामरूप, दरंग, विश्वनाथ, डिब्रुगढ़, श्रीभूमि, मोरीगांव, धुबड़ी, बाक्सा एवं कामरूप महानगर में इसकी खेती हो रही है। राज्य में इसकी प्रचुर संभावनाएं हैं और यहां बारिश भी अच्छी होती है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सितंबर महीने में हम 50 किसानों को लेकर प्रशिक्षण के लिए बिहार जाएंगे। इसका उद्देश्य उन्हें बेहतर तरीके से इसकी उन्नत तकनीक उत्पादन प्रक्रिया रखरखाव और विपणन की बारीकियां के बारे में जानकारी हासिल करना है। वहां से लौटने के बाद वे उन्नत तरीके से मखाने की खेती कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस खेती से जुड़ने वाले किसानों को राज्य सरकार शेष पृष्ठ आठ पर

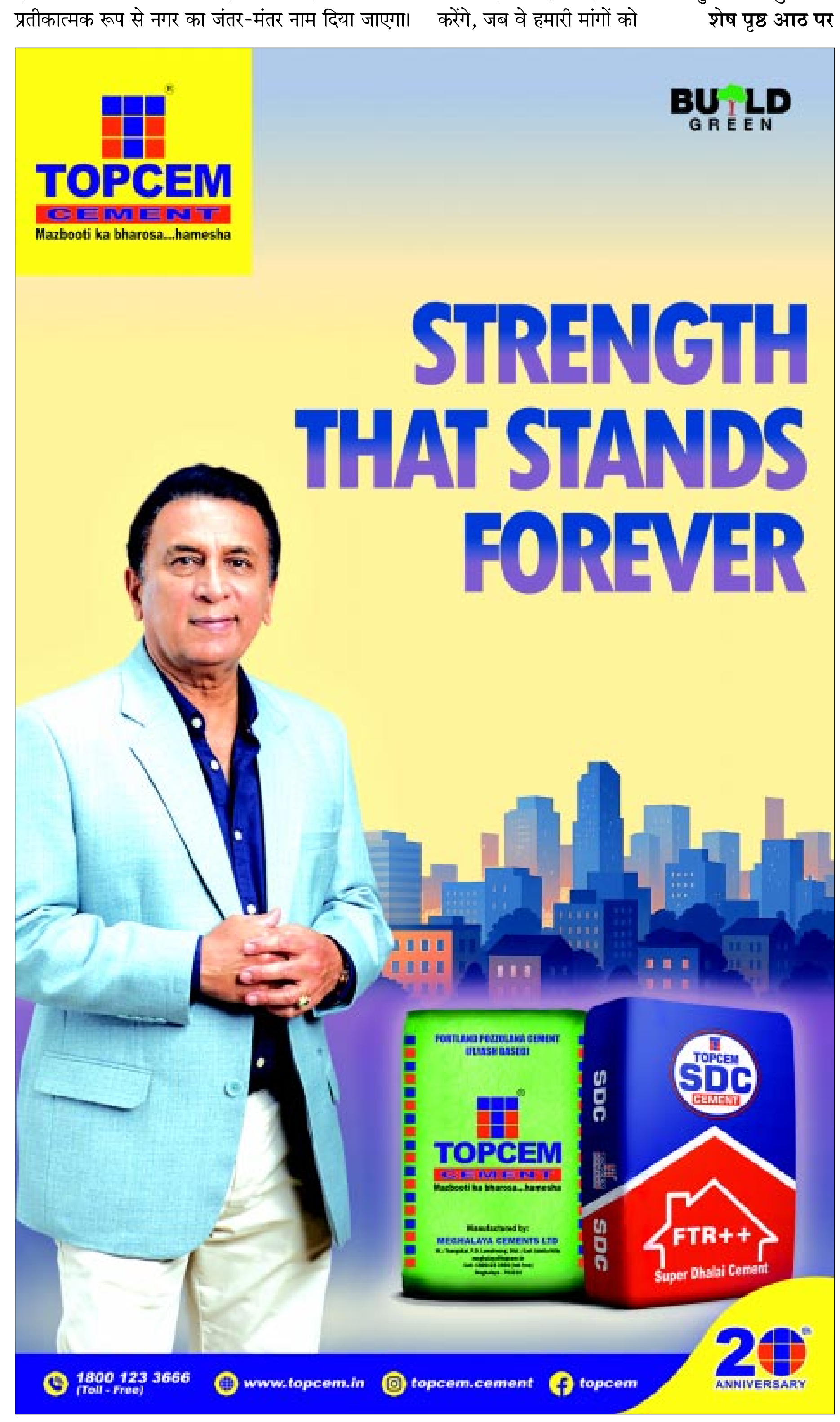

त्रिपुरा डीजीपी मौत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की होगी फॉरेंसिक जांच

अगरतला, 22 जुलाई (भा)। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ की मौत की जांच के तहत पुलिस उनके द्वारा इस्तेमाल किये गये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराएगी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। वर्ष 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी धनखड़ सोमवार को अगरतला में राज्य पुलिस मुख्यालय स्थित अपने आधिकारिक कक्ष के शौचालय में फंदे से लटके पाये गये थे। जांच अधिकारी शुभ्रजीत देब ने बताया कि अप्राकृतिक शेष पृष्ठ आठ पर

भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और आसियान की केंद्रीय भूमिका का किया आह्वान

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भा)। भारत ने दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रमता के बीच अपने क्वाड सहयोगियों के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की अपील की और इस क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका के आह्वान को दोहराया। फिलीपीन की राजधानी मनीला में बुधवार को हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल हुए। इससे पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मई के अंत में नयी दिल्ली में हुई थी, जब रुबियो भारत की शेष पृष्ठ आठ पर

पेज : 6 नये भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय

पेज : 8 भविष्य के युद्ध किसी एक सैन्य बल के दम पर नहीं लड़े जा सकते

पेज : 9 एआई से बीच वेडिंग तक वेडिंग इंडस्ट्री के नये ट्रेंड्स पर मंथन

प्रातः खबर
गुवाहाटी, गुरुवार, 23 जुलाई, 2026

प्रदेश भाजपा ने दिया वाजपेयी भवन में धरना

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में किये गये विरोध प्रदर्शन की कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी ने इसे किसी संवेदनशील मुद्दे पर रचनात्मक संवाद करने के बजाय उसका राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के इस रवैये और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश के खिलाफ पार्टी ने आज गुवाहाटी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी भवन में एक विरोध सभा का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस विरोध कार्यक्रम में मंत्री पीयूष हजारिका, अशोक सिंघल, नीलिमा देवी, विश्वजीत दैमारी, कौशिक राय और कृष्णेंदु पॉल सहित कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों भवेश कलिता, प्रसंत फुकन तथा राजदीप रॉय ने कहा कि हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल शासन में बाधा डालने या दलीय स्वार्थ साधने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने निकाली रैली, प्रधान के इस्तीफे की मांग

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.स.)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने आज परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर अपना विरोध तेज करते हुए गुवाहाटी में एक रैली निकाली और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। यह रैली दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध और कांग्रेस के नेतृत्व में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकली गयी। इसका नेतृत्व विपक्ष के नेता वाजेद अली चौधरी और विधायक जाकिर हुसैन सिकदर ने किया, जिसमें सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। पेपर लीक को बंद करो और भाजपा हाय हाय जैसे नारे लगाते हुए, प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को नयी दिल्ली में संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर और केस तुरंत वापस लेने और कथित बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिकदर ने कहा कि हमें जवाब चाहिए, और इसीलिए हमने वाजपेयी भवन तक यह मार्च निकाला है। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि उसकी सरकार देश पर बिना रहम के राज क्यों कर रही है और उसने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज का ऑर्डर क्यों दिया। राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वालों पर पुलिस की ज्यादती का आरोप लगाते हुए, चौधरी ने कथित नीट पेपर लीक पर पार्लियामेंट में बहस की पार्टी की मांग दोहराई। पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेनी चाहिए। इससे पहले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में भाग ले रहे स्टूडेंट्स और विपक्षी नेताओं के साथ एकजुटता दिखायी। हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद, असम कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी गुवाहाटी में राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें वे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। हालांकि, पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को राजभवन के बाहर खारघुली इलाके में रोक दिया और परिसर में घुसने नहीं दिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने नेताओं से एक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मना कर दिया और गवर्नर से व्यक्तिगत रूप से मिलने पर जोर दिया। राजभवन के बाहर भारी पुलिस तैनाती की आलोचना करते हुए, सिकदर ने कहा कि पार्टी को शांतिपूर्वक अपनी शिकायतें बताने से रोका जा रहा है। हम एक छोटे उन्होंने कहा कि यहां लोगों का एक ग्रुप है, जो गवर्नर से मिलने और अपनी शिकायतें रखने आया है। लेकिन पुलिस की बहुत ज्यादा तैनाती की गयी है। गवर्नर से मिलने से मना करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, सिकदर ने कहा कि पार्टी तब तक अपना आंदोलन जारी रखेगी जब तक स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि सरकार हमें रोकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हम तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक हमारे देश के स्टूडेंट्स और युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। असम विधानसभा का बजट सेशन 31 जुलाई तक चलने वाला है, इसलिए उम्मीद है कि कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर बार-बार इस मुद्दे को उठाएगी, जिससे कथित परीक्षा में गड़बड़ियों पर और राजनीतिक टकराव की स्थिति बन जाएगी।

अधिसूचना

रोजगार सूचना सं.: C1-Gaz/TS/2026 (CMP) दिनांक: 20-07-2026

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के तिनसुकिया मंडल में एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (जीडीएमओ) की नियुक्ति

[illegible] रेलवे के तिनसुकिया मंडल में इच्छुक और योग्य डॉक्टरों को "कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर (सीएमपी)" के तौर पर रखा जा [illegible] किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से प्रशासनिक [illegible] और संबंधित सीएमपी की इच्छा के आधार पर [illegible] के लागू होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है।

प्रवेश साक्षात्कार की तिथि: 03-08-2026 (सोमवार)

समय: 11.00 बजे।

स्थान/साक्षात्कार की जगह: मंडल रेलवे अस्पताल, डिब्रूगढ़

कुल रिक्तियों की संख्या:-

क्र. सं.	पदों के नाम	पदों की संख्या	तिनसुकिया मंडल में रिक्तियों का स्थान	खाली पदों के लिए आरक्षण
1	सीएमपी (जीडीएमओ)	01	डिब्रूगढ़ रेलवे अस्पताल (डीआरएच)-डीडीआरजी	यूआर 2
2	सीएमपी (जीडीएमओ)	01	लेडो (एलईडीओ) हेल्थ यूनिट	
	कुल	02		

नोट: 1. [illegible] जिन्हें जरूरत के हिसाब से [illegible] रखा जा सकता है।
2. प्रशासन के पास तिनसुकिया मंडल के क्षेत्राधिकार में कहीं भी नियुक्त [illegible] को तैनात करने का अधिकार सुरक्षित है।

शैक्षणिक योग्यता/पात्रता:

सीएमपी/जीडीएमओ के लिए – इनके लिए [illegible] मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से मान्यता प्राप्त संस्थान से **एमबीबीएस** की डिग्री और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन [illegible] अनिवार्य रोटेशनल इंटर्नशिप पूरी करने के बाद [illegible] किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना है।

उम्र: (i) 01-07-2026 को उम्र 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, मौजूदा नियमों के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जानी है।
(ii) रिटायर्ड रेलवे डॉक्टर और राज्य व केंद्र सरकार के रिटायर्ड सरकारी मेडिकल [illegible] भी इसके लिए पात्र हैं, बशर्ते **01-07-2026 तक उनकी** उम्र 65 वर्ष [illegible] और वे शारीरिक रूप से फिट हों।

पारिश्रमिक:

जनरल ड्यूटी (जीडीएमओ) के लिए (पूर्णकालिक)	₹95,000/ प्रति महीने	[illegible] सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। [illegible] आवास दिया जाता है, तो [illegible]

[illegible] पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर होगी और इसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, [illegible] जो भी पहले हो।

आवेदन कैसे करें: ऊपर बताई गई शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार **03-08-2026 (सोमवार) को सुबह 11.00 बजे मंडल रेलवे अस्पताल, डिब्रूगढ़, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, तिनसुकिया** में **प्रवेश साक्षात्कार** के लिए आ सकते हैं। उन्हें साथ में तय फॉर्मेट के अनुसार भरा और साइन किया हुआ आवेदन पत्र, सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट/टेस्टिमोनियल्स और उनकी अटेस्टेड कॉपी, और दो पासपोर्ट आकार फोटो लाने होंगे।

[illegible] ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सभी सर्टिफिकेट की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी [illegible] की जानकारी हो), चार पासपोर्ट आकार फोटो और पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर)/लर्निंग सर्टिफिकेट/लाइफ सर्टिफिकेट (रिटायर हो चुके डॉक्टरों के मामले में) दिखाने होंगे।

उम्मीदवार अन्य शर्तों और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए, वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in पर जा सकते हैं।

मंडल रेलवे प्रबंधक (पी), तिनसुकिया

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

राहुल का विरोध प्रदर्शन बचकाना : गुजरात भाजपा

अहमदाबाद, 22 जुलाई (भा)। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज राहुल गांधी के उस विरोध प्रदर्शन को बचकाना करार दिया, जो एक दिन पहले नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया था। पार्टी ने उनपर संसद का सत्र जारी रहने के बावजूद देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न करने का आरोप लगाया। भाजपा ने गांधी के प्रदर्शन की निंदा करने के लिए यहां एक विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पालडी इलाके में गुजरात कांग्रेस के मुख्यालय राजीव गांधी भवन के बाहर एकत्र हुए। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाये। भारी पुलिस तैनाती के बीच लगभग एक घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन का समापन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। जब विश्वकर्मा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रथम स्तर के पुलिस बैरिकेड को पार किया और कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन इमारत से लगभग 70 मीटर दूर दूसरे स्तर के बैरिकेड पर उन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी दूसरे स्तर के बैरिकेड पर करीब 40 से 45 मिनट तक डटे रहे।

विधानसभा के गलियारे से

बातचीत से सुलझ रहे हैं असम-पड़ोसी राज्य सीमा विवाद

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। राज्य के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने आज विधानसभा में जानकारी दी कि सरकार अपने पड़ोसी राज्यों के साथ दशकों पुराने अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को हल करने के लिए लगातार बातचीत की नीति पर काम कर रही है। बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष वाजिद अली चौधरी द्वारा असम की भूमि पर पड़ोसी राज्यों के कथित अतिक्रमण को लेकर उठाए गये सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम के साथ सीमा विवादों को दूर करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर क्षेत्रीय समितियां गठित की गयी हैं। मेघालय के साथ कुल 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है और शेष क्षेत्रों पर चर्चा जारी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ रही है, हालांकि नगालैंड के साथ वर्ष 1988 के एक पुराने अदालती मामले के कारण प्रक्रिया कुछ जटिल बनी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में तनाव और सुरक्षा स्थिति पर बोलते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि असम-मिजोरम सीमा पर वर्ष 2021 की हिंसक झड़प के बावजूद शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास जारी हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दूसरी रक्षा पंक्ति को लगातार मजबूत कर रही है, जिसके तहत 96 बॉर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) काम कर रहे हैं और नगालैंड सीमा के संवेदनशील इलाकों में 27 सीआरपीएफ बीओपी तैनात किये गये हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वर्ष 2020-21 के बाद केंद्र से फंड न मिलने की बात स्वीकार करते हुए उन्होंने बताया कि असम के 140 गांवों को केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, पेयजल और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने के साथ-साथ सीमा पार अपराधों पर रोक लगाना है।

राज्य में 3,500 से अधिक सिंचाई परियोजनाएं

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। जल सिंचाई मंत्री पीयूष हजारिका ने आज विधानसभा में बताया कि राज्य में सिंचाई विभाग के तहत कुल 3,510 छोटी, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से 882 योजनाएं पूरी तरह से कार्यशील हैं, जबकि 1,457 योजनाएं आंशिक रूप से चल रही हैं। इसके अलावा 937 योजनाएं वर्तमान में खराब स्थिति में हैं और 234 नयी योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विपक्ष के नेता वाजिद अली चौधरी के पूछे गये एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के हर खेत को पानी घटक के तहत राज्य में नलकूप और सतही जल सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की जा रही है।

बीते 10 वर्षों में 70 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन तक पहुंचा सिंचाई का पानी

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। राज्य के जल सिंचाई मंत्री पीयूष हजारिका ने आज सदन को बताया कि असम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कुल बोया गया क्षेत्र 40,87,734 हेक्टेयर और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 27,58,757 हेक्टेयर है। निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र में से सिंचाई विभाग के प्रयासों के चलते वर्तमान में 8.86 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचित क्षेत्र और 6.52 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिल रहा है, जबकि बीते 10 वर्षों में विभाग ने 70,835 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने में सफलता पाई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक रेकिबुद्दीन अहमद के एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि असम में सूखा जैसी स्थिति से निपटने और कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए जल संसाधन और सिंचाई विभाग लगातार प्रयासरत है। हालांकि राज्य की पूरी कृषि भूमि को अभी तक सिंचाई के दायरे में लाना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से वंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए कई बड़े कदम उठाये जा रहे हैं। कामरूप जिले में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीएमएफ) के माध्यम से समप वेल प्रणाली पर आधारित सूखा राहत परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के लिए कलियाबर और सरुपथार विधानसभा क्षेत्रों में भी सूखा राहत सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) को भेजे गये हैं, जिन्हें मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। साथ ही आधुनिक कमान क्षेत्र विकास (एमसीएडी) योजना के तहत सिगुवा प्रवाह सिंचाई परियोजना पर काम चल रहा है, जिसके पूरा होते ही लगभग 1,427 हेक्टेयर कृषि भूमि को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार अपने स्वयं के प्राथमिकता विकास कोष (एसओपीडी), नाबार्ड, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) और अन्य उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी संभावनाओं को देखते हुए नयी सिंचाई परियोजनाओं को लगातार गति दे रही है।

20,911 सखियां दे रही हैं ग्रामीण विकास को रफ्तार

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) के तहत वर्तमान में 12 विभिन्न श्रेणियों में कुल 20,911 सखी कार्यरत हैं। ये सखियां स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। भाजपा विधायक मृणाल सैकिया के पूछे गये एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्तमान जीविका सखी को अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिमाह, जबकि बैंक सखी को 9,000 रुपये मिलते हैं। वहीं कृषि सखी, पशु सखी, संयोग सखी, सीआरपी-ईपी, बीडीएसपी और बीमा सखी को अधिकतम 7,500 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं। मास्टर बुक कीपर और एमसीपी ट्रेनर के लिए अधिकतम मानदेय 5,000 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा बीसी सखी और डिजीपे सखी को सीधे वित्तीय संस्थानों से उनके काम और कमीशन के आधार पर भुगतान किया जाता है। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर के करने सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि उन्होंने बताया कि एएसआरएलएम के अंतर्गत वर्तमान में कुल 3,61,965 स्वयं एसएचजी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पेश

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। राज्य सरकार ने आज असम विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून के कुछ कड़े प्रावधानों से छूट देकर सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंत की ओर से संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने सदन में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (असम संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया। यह छूट राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परियोजनाओं, विद्युतीकरण सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे तथा किफायती आवास योजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि पर लागू होगी।

न्यायाधीशों के 40 पद रिक्त

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। राज्य के कानून एवं न्याय मंत्री सुशांत बड़गोहाईं ने आज सदन को बताया कि असम की विभिन्न अदालतों में वर्तमान में कुल 5,75,541 मामले लंबित हैं, जबकि न्यायाधीशों के 40 पद खाली पड़े हैं।

विधानसभा में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर के एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि राज्य में न्यायाधीशों के कुल 486 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 446 पद भरे हुए हैं।

इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि चालू वर्ष के 31 मई तक राज्य की अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या 5,75,541 थी, जिसमें 1,14,296 सिविल मामले और 4,61,245 आपराधिक मामले शामिल हैं। वर्ष 2021 में अदालतों ने 35,536 सिविल और 1,46,810 आपराधिक मामलों का निपटारा किया। इसके बाद 2022 में 45,184 सिविल और 2,26,175 आपराधिक मामले, जबकि 2023 में 45,555 सिविल और 3,27,728 आपराधिक मामले निपटाये गये। वहीं वर्ष 2024 में 50,483 सिविल और 2,33,399 आपराधिक मामलों का निस्तारण हुआ, जो 2025 में 53,348 सिविल और 1,95,636 आपराधिक मामले रहा।

इसके अलावा राज्य में फिलहाल 40 फास्ट ट्रैक कोर्ट और 6 विशेष अदालतें काम कर रही हैं, हालांकि राज्य में कोई कमर्शियल कोर्ट नहीं है।

12 हजार से अधिक विदेशी के कटे नाम

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। असम समझौता क्रियान्वयन विभाग के मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि बीते 31 मई तक राज्य में कुल 1,72,673 विदेशियों की पहचान की गयी है। चिन्हित विदेशी नागरिकों में 61,189 हिंदू, 1,11,414 मुस्लिम और 70 ईसाई व अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के पूछे गये एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्ष 1985 से अब तक विदेशी घोषित किये जा चुके 12,269 लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गये हैं। सरकार ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम न्यायिक प्राधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किये जाने के बाद उसका नाम मतदाता सूची से हटाना एक निरंतर चलने वाली कानूनी प्रक्रिया है। इसके साथ ही वर्ष 1985 से चालू वर्ष के 30 जून तक कुल 31,789 अवैध विदेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है।

पंचांग

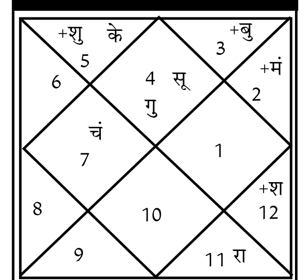

तिथि संवत : आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी प्रातः 7.05 तक रहेगी इसके बाद दशमी तिथि रहेगी।

विक्रम संवत 2083 शाके 1948, सूर्य दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, नव सवंत्सर (रौद्र) तारीख 23 जुलाई गुरुवार।

सूर्योदयकालीन नक्षत्र : विशाखा।

योग :- शुभ सायंकाल 7.18 तक रहेगा तदुपरांत शुक्ल योग रहेगा।

करण :- कौलव प्रातः 7.02 तक तदुपरांत तैतिल करण रात्रि 8.05 तक रहेगा।

ग्रह विचार : (प्रातः 4.41) सूर्य-कर्क, चंद्र-तुला सायंकाल 7.00 बजे तक तदुपरांत वृश्चिक राशि में प्रवेश, मंगल-वृष, बुध-मिथुन, गुरु-कर्क, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुंभ, केतु-सिंह राशि में स्थित है।

राहुकाल : दोपहर 1.30 बजे से 3.00 बजे तक रहेगा।

सूर्योदय : 4.41 बजे सूर्यास्त 6.16 बजे।

ज्योतिर्विद विकास तिवाड़ी
गुवाहाटी मो.9529781915।

डीयू : पहले चरण में 63,756 छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में लिया प्रवेश

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भा)। दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएएस) के तहत स्नातक प्रवेश का पहला चरण पूरा कर लिया है और इस प्रक्रिया में कुल 63,756 छात्रों को दाखिला मिला है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी। इसके मुताबिक प्रवेश पाने वाले 15,265 अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट को फ्रीज करने का विकल्प चुना है, जबकि 48,153 ने अगले चरण में अपनी पसंद के बेहतर पाठ्यक्रम या महाविद्यालय पर विचार किये जाने के लिए अपग्रेड का विकल्प चुना है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में प्रवेश के ताजा आंकड़े 21 जुलाई को जारी किये गये आंकड़ों की तुलना में बढ़ोतरी दिखाते हैं। उस समय विश्वविद्यालय ने बताया था कि पहले चरण में शुल्क भुगतान की समय-सीमा से पहले जरूरी फीस जमा करके 61,932 अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश की पुष्टि कर दी थी। इससे पहले, 81,900 से अधिक अभ्यर्थियों ने पहले चरण में उन्हें आवंटित स्नातक पाठ्यक्रम की सीट स्वीकार कर ली थीं, जो प्रवेश प्रक्रिया में उनकी उत्साहजनक भागीदारी को प्रतिबिंबित करता है। पिछले हफ्ते जारी की गयी पहली आवंटन सूची में, 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 67 महाविद्यालयों के 221 पाठ्यक्रमों में 71,000 से अधिक स्नातक सीटों के लिए 93,033 अभ्यर्थियों को पेशकश की गयी थीं। यह आवंटन उन 2.08 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से किया गया, जिन्होंने अपने कार्यक्रम और महाविद्यालय की प्राथमिकताओं के साथ प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण पूरा किया था।

सरकार से बातचीत के लिए तैयार, जंतर-मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर मिलें प्रतिनिधि : सीजेपी

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भा)। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने आज कहा कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों का समाधान निकालने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, हालांकि, यह बातचीत किसी मंत्री के आवास के बजाय एक तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए। कॉजपा प्रवक्ता सौरव दास ने जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस ने बुधवार सुबह संगठन को सूचित किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने उन्हें (कॉजपा के प्रतिनिधियों) अपने आवास पर आमंत्रित किया है। दास ने कहा कि हमने किसी के आवास या कार्यालय जाने से इनकार कर दिया है। जनता की अदालत यहीं है। मंत्रियों को जनता के बीच आना चाहिए। अगर वे बातचीत करना चाहते हैं, तो बातचीत जंतर-मंतर पर होनी चाहिए।

पूर्वोत्तर की महिला कारीगरों को मिलेगा नया बाजार

एनईएचएचडीसी व एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी ने मिलाया हाथ

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनईएचएचडीसी) और फ्रेंड्स ऑफ वूमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया (एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के बीच आज गुवाहाटी में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनईएचएचडीसी और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत गैर-लाभकारी संगठन एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी की यह संयुक्त पहल पूर्वोत्तर के राज्यों की महिला कारीगरों और बुनकरों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सीधे बाजार से जोड़ने पर केंद्रित है। इस समझौते पर एनईएचएचडीसी के प्रबंध निदेशक मारा कोचो और एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी की सीओओ नेहा कंसारा ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी पूर्वोत्तर के आठों राज्यों की महिला कारीगरों और बुनकरों को वित्तीय रूप से सक्षम, उद्यम-तैयार, गुणवत्ता के प्रति जागरूक और बाजार से सीधे जुड़े उत्पादकों के रूप में सशक्त बनाने के एक व्यापक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। हस्ताक्षर के दौरान कोचो ने कहा कि एफडब्ल्यूडब्ल्यूबी के साथ यह साझेदारी पूरे पूर्वोत्तर में महिला कारीगरों और बुनकरों की उद्यम क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तीन दिवसीय भूपेंद्र संगीत कार्यशाला का समापन

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर होजाई साहित्य सभा के तत्वावधान में साहित्यरथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा भवन में आयोजित तीन दिवसीय भूपेंद्र संगीत कार्यशाला का बीते 20 जुलाई की शाम को समापन हो गया। डॉ. भूपेन हजारिका सांस्कृतिक न्यास के सहयोग से पहली बार होजाई में आयोजित इस कार्यशाला में होजाई, लंका, गुहागांव, काकी, कोमेराकटा और बैठलांग्सू क्षेत्रों के कुल 158 बच्चों, किशोरों, युवाओं और महिला संगीत प्रेमियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने तीन दिनों तक भूपेंद्र संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में न्यास की ओर से कलाकार नित्यानंद डेका, रूपम भुयान और नमिता भट्टाचार्य ने विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहकर प्रतिभागियों को गायन का प्रशिक्षण दिया। समापन समारोह में न्यास की सचिव मंजुला हजारिका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। उनके साथ न्यासी व वरिष्ठ पत्रकार स्निग्धाशिखा बोरा, अनुपम लस्कर, प्रख्यात नाट्यकर्मी माणिक अहमद, अभिनेत्री जॉली लस्कर और डिंपी बर्मन आदि हस्तियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और सभी को प्रमाण-पत्र प्रदान किये। समापन कार्यक्रम में लोकप्रिय गायिका नमिता भट्टाचार्य ने भूपेन हजारिका के गीतों की विशेषताओं पर अपने विचार व्यक्त किये और दो गीत भी प्रस्तुत किये। इस तीन दिवसीय कार्यशाला के समन्वयक अनूप कुमार बरठाकुर के साथ-साथ न्यास की ओर से वाद्ययंत्र वादक भाबीराम बोड़ो और हिमांशु पाठक ने अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। आयोजक समिति के अध्यक्ष जोगेन दत्त और सचिव बिमल कुमार नाथ ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

स्वत्वाधिकारी प्रातः खबर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, खबर बिल्डिंग, दूसरा तल्ला, साइकिल फैक्ट्री, कालापहाड़, गुवाहाटी- 781016 के लिए **श्याम सुंदर लाटा** द्वारा प्रकाशित तथा उनके लिए पीजी इंडिया लिमिटेड, मिनी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कालापहाड़, गुवाहाटी-16 (असम) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
E-mail : pratahkhabar5@gmail.com, pratah_khabar@yahoo.com, **दूरभाष+फैक्स** : 0361-2492131, **मो. :** 091270-70355, **जोरहाट कार्यालय** : 0376-2370042, **फैक्स :** 0376-2370043, **E-mail :** pkhabarjrt@gmail.com
एडिटर इन चीफ : चंद्रप्रकाश शर्मा
*प्रकाशन से उत्पन्न सभी विवाद गुवाहाटी न्यायालय के अधीन।
संपादक : परमेश्वर सिंह

नमस्कार गुवाहाटी

प्रातः खबर

गुरुवार, 23 जुलाई, 2026

मंगलवाणी

जो दूसरों के कल्याण में आनंद पाता है, वही सच्चा भक्त है।

- श्री कृष्ण

मौसम

अधिकतम 32°
न्यूनतम 25°

Ph. : 2548109 2730431
L. GOPAL JEWELLERS
9-11-14, Kuber A.C. Market
Guwahati - 781001
शुद्ध चांदी के बर्तनों एवं शुद्ध चांदी की सिल्ली व चांदी के सिक्कों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान
22/22 KDM Gold Jewellery, Hallmark Gold Jewellery Branded Diamond Jewellery.

0361-2601385
9678211156
D. M. Jeweller's
(As You Like We are)
7/8 (L) Akram's Business Fancy Bazar, Guwahati-1
शुद्ध सील चांदी के बर्तन एवं असली सिक्कों का प्रतिष्ठित स्थान
We also deal in 22/22 KDM hallmark Jewelleries

खाद्य मंत्री कौशिक राय ने की समीक्षा बैठक

राशन कार्ड धारकों को दाल-चीनी की आपूर्ति के निर्देश

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री कौशिक राय ने आज दिसपुर स्थित जनता भवन के अपने कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को मसूर दाल और चीनी के वितरण की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने योजना की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों सहित नेफेड के प्रतिनिधियों से अब तक की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में खाद्य सामग्री की खरीद, आपूर्ति और वितरण प्रणाली से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गयी। राज्य भर के सभी पात्र लाभार्थियों को इन आवश्यक खाद्य वस्तुओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मंत्री ने अधिकारियों और नेफेड के

प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय बेहतर करने तथा परिचालन व्यवस्था को सुचारू बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी हितधारकों से निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की अपील की ताकि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बनी रहे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि योजनाओं का लाभ हर पात्र लाभार्थी तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इस समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्वरंजन सामल, सचिव अनुसूया दत्त बरुवा और आयुक्त हेमंत भुइयां सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

नीट घोटाले पर प्रदेश कांग्रेस का हल्लाबोल

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। प्रदेश कांग्रेस ने नीट परीक्षा घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर आज राजीव भवन से एक विशाल विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वाजेद अली चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस रैली के माध्यम से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा कराने और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज सभी प्राथमिकी को तुरंत वापस लेने की पुरजोर मांग की गयी। इस विरोध प्रदर्शन में असम विधानसभा में विपक्ष के उपनेता डॉ. जयंत प्रकाश दास, विधायक ज़ाकिर हुसैन सिकदर, नूरुल हुदा, बेबी बेगम, आसिफ नज़र, जुबैर अनम और तंजील हुसैन समेत पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हाथों में पार्टी के झंडे लिए बड़ी संख्या में पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं में प्रदेश महासचिव विपुल गोगोई, नगर जिला अध्यक्ष स्वपन दास, वरिष्ठ नेता रूपा देउरी, महासचिव द्वय इमदाद हुसैन व बंदीप दत्ता, मोइनाजान बेगम, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कृष्णा दास, मीडिया विभाग के प्रतिनिधि हैप्पी गोगोई व रूपा कलिता और एनएसयूआई के अध्यक्ष कौशिक कश्यप प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

भाकपा (माले) ने बाढ़ को लेकर जतायी गहरी चिंता

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। भाकपा (माले) की असम राज्य समिति ने ऊपरी असम के शिवसागर और टियोक सहित कई क्षेत्रों में आयी भीषण बाढ़ और उससे हुए व्यापक नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तुरंत बचाव, राहत और आश्रय अभियानों को तेज करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि अचानक आये इस जलप्रलय के लिए लोग पूरी तरह तैयार नहीं थे, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होने की आशंका है। पार्टी के राज्य सचिव विवेक दास ने इस आपदा की वैज्ञानिक और विस्तृत जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि केवल बादल फटने को ही इसका एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहाड़ों में मूसलाधार बारिश होना कोई नयी बात नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि नाज़िरा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने 2018 में ही दिखो नदी से जुड़े खतरों को लेकर विधानसभा में सरकार को आगाह किया था और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की थी। पार्टी का आरोप है कि नगालैंड और अरुणाचल की पहाड़ियों से बहने वाली नदियों के ऊपरी इलाकों में अवैध कोयला, बालू और पत्थर खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के नाम पर जारी अंधाधुंध वनों की कटाई और भू-खनन के कारण पहाड़ों का पानी सीधे मैदानी इलाकों में तबाही मचा रहा है। साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किये बिना बनाये गये चार-लेन के राजमार्ग भी इस अभूतपूर्व बाढ़ के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। पार्टी ने इन तमाम अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने, पूरी स्थिति की निष्पक्ष जांच कराने, मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा देने और प्रभावित परिवारों के नुकसान का आकलन कर उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है।

थर्ड थिएटर महोत्सव 2026 का समापन

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। असम के प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन थर्ड थिएटर द्वारा आयोजित थर्ड थिएटर महोत्सव 2026.के गुवाहाटी संस्करण का 21 जुलाई को श्री श्री माधवदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में शानदार समापन हुआ। इस अवसर पर 20 दिवसीय नृत्य, नाटक और मूक अभिनय कार्यशाला के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग

80 बाल एवं युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के पहले चरण में चार वर्ष के बच्चों से लेकर ऊर्जावान युवाओं ने बिजित कुमार दास के निर्देशन में डॉ. करबी डेका हजारिका द्वारा रचित नाटक राक्षस होवाई भाल की मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके उपरांत आरजे सुजिता द्वारा लिखित और बिजित कुमार दास के ही निर्देशन में संगीतमय आलेख्य सुंदरर आलोकयात्रा प्रस्तुत किया गया। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के बरगीत के भक्तिमय सुरों से लेकर जुबिन गर्ग के आधुनिक गीतों के इस संगम को दर्शकों ने खूब सराहा। इस संगीतमय प्रस्तुति में रुजी मुदै ने सह-निर्देशन किया, जबकि अनीता शर्मा, मीरनंदा बरठाकुर, जॉलीमोनी सैकिया, बनलता बैश्य, काश्यप नाथ, बर्णाली बोड़ो, शुकलेश्वर पातर, प्रातः पराशर और अभिजीत बोड़ो ने नृत्य निर्देशन का दायित्व निभाया। इस सांस्कृतिक संध्या में असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अरुप कुमार मिश्र, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र समाज के सचिव सुदर्शन ठाकुर, प्रख्यात मूर्तिकार बीरेन सिंह, लोकप्रिय गायिका मौसमी सहरिया, विशिष्ट साहित्यकार मणिकुंतला भट्टाचार्य और जयंत माधव बोरा, समाजसेवी गोपाल जालान तथा नाटककार हिल्लोल कुमार पाठक सहित कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और कलाप्रेमियों ने एक स्वर में थर्ड थिएटर के इस प्रयास और बिजित कुमार दास के कुशल निर्देशन की जमकर प्रशंसा की। राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य में नयी पीढ़ी को मंच प्रदान करने वाली इस पहल की सफलता के बाद आयोजकों ने घोषणा की है कि थर्ड थिएटर महोत्सव 2026 का अगला संस्करण शिवसागर में आयोजित किया जाएगा।

मायुमं कामाख्या शाखा की हुई कार्यकारिणी बैठक

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। मारवाड़ी युवा मंच कामाख्या शाखा के 27वें कार्यकाल की चौथी कार्यकारिणी सभा 22 जुलाई को प्रांत ऑफिस, आठगांव में आयोजित की गयी। सभा दोपहर 3.30 बजे शुरू हुई और 3.45 बजे कार्यवाही आगे बढ़ी। सभा की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष नमिता दुधोड़िया ने स्वागत भाषण के साथ की, जिसके बाद दिवंगत आत्माओं के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। पिछली सभा का प्रतिवेदन सचिव ममता सेठी द्वारा एवं आय-व्यय का विवरण कोषाध्यक्ष नम्रता सुराणा द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभा में एक नये सदस्यता फार्म पारित किया गया। आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई जैसे हरियाली तीज, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि। सभा में चांदनी बैद ,भूमिका सेठी, कंचन पारीक, बबीता हरलालका, सीमा शर्मा, जूही पांडे उपस्थित थी। सभी उपस्थित सदस्यों ने सभा में सक्रिय भागीदारी निभायी और संगठन को आगे बढ़ाने के संकल्प को दोहराया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन हुआ।

चिन्मय मिशन गुवाहाटी ने स्मारिका समर्पणम 2026 किया जारी

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख. स.)। चिन्मय मिशन की 75वीं सालगिरह के मौके पर दुनिया भर में चिन्मय अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में चिन्मय अमृत यात्रा देश भ्रमण पर है। चिन्मय अमृत यात्रा के यात्री कल गुवाहाटी पहुंचे। गायन बयान से यात्रा का मिशन

परिसर में भव्य स्वागत किया गया और आज सुबह इस उपलक्ष्य में एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन के देवी ग्रुप और युवा केंद्र, जीएनटी चिन्मय विद्यालय के शिक्षकों और अन्य ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद शाम को मिशन के सभागार में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान चिन्मय मिशन, चेन्नई और पूर्वोत्तर के प्रभारी आचार्य स्वामी मित्रानंद ने चिन्मय मिशन गुवाहाटी की प्रभारी आचार्य ब्रह्मचारिणी अनन्या चैतन्य मिशन के अध्यक्ष आरएस जोशी और सचिव डॉ सुनीता अग्रवाला की मौजूदगी में स्मारिका समर्पणम 2026 का विमोचन किया। मौके पर स्वामी मित्रानंद ने स्मारिका जारी करने पर खुशी जताई और इसकी थीम, ही इज़ प्योर ब्लिस की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि यह थीम आज की दुनिया में खास तौर पर काम की है, जहाँ लोग अपनी खुशी के असली रूप से दूर हो गए हैं और स्ट्रेस और एंग्जायटी के बोझ तले दब रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि खुशी थीम पर आधारित आर्टिकल पढ़ने वालों को ज़िंदगी के गहरे मतलब पर सोचने और अंदर छिपी खुशी को फिर से खोजने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं देवी ग्रुप की सदस्यों ने एक दिल को छू लेने वाली भजन प्रस्तुत किया, जिसने मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

द्वितीय कॉल नोटिस

संख्या: N/52/21/RN/Staff-4609 दिनांक: 09.06.2026.

सेवा में,

श्री आदेश कुमार गुप्ता,
अप्रेन्टिस तकनीशियन ग्रेड-III/टेम्रीकॉम
पिता - श्री जगदीश कुमार गुप्ता
ग्राम - मौहारी का पुरवा, पी.ए.सी. छावनी के पास
डाकघर - पब्लिक यक ऐया
जिला - रायबरेली
पिन - 229001 (उ.प्र.)

एसएसई/टेली/आरपीएन के पत्र संख्या N/TC/07/RP/Intimation/2026-4 दिनांक 26.05.2026, के संदर्भ में, आप बिना किसी सूचना और अनुमति के दिनांक 27.01.2026 से आज तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे हैं। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा पहले ही एक कॉल नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें आपको पत्र प्राप्त होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने की सलाह दी गई थी, किंतु आपने आज तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपको इस कॉल नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने की सलाह दी जाती है, अन्यथा प्रचलित नियमों के अनुसार आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सीनियर डीएसटीई/रंगिया

पूर्वोत्तर सीमा रेल

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

जुबिन-जुबली की अंतिम युगलबंदी से सजेगी असमिया फिल्म आदिशक्ति

अनि बनी के बाद खरिकाजाई के टीजर ने भी बढ़ायी दर्शकों की उत्सुकता

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। असमिया सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म *आदिशक्ति* जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है। फिल्म के पहले गीत अनि बनी को मिले शानदार प्रतिसाद के बाद अब इसके दूसरे गीत खरिकाजाई का टीजर भी आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। टीजर के रिलीज होते ही फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गयी है। फिल्म का पहला गीत अनि बनी अपनी मधुर धुन और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण पहले ही चर्चा का विषय बन चुका है। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग और चर्चित गायिका जुबली की सुरीली युगलबंदी सुनने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि यह दोनों कलाकारों का किसी फिल्म के लिए अंतिम युगल गीत है, जिससे यह गीत प्रशंसकों के लिए और भी खास बन गया है। अब फिल्म के दूसरे गीत खरिकाजाई के टीजर ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस गीत को अपनी मधुर आवाज से सजाया है चर्चित गायक आचुर्य बरपात्र गोहाईं ने। फिल्म की पूरी टीम को विश्वास है कि यह गीत भी श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाएगा। गीत खरिकाजाई के बोल राहुल गौतम शर्मा ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत गौरांग-विशाल की जोड़ी ने तैयार किया है। गीत का मिक्सिंग और मास्टरिंग रूपजीत दास ने किया है, जिससे इसकी ध्वनि और भी प्रभावशाली बन गयी है। आदिशक्ति का निर्माण मोशन पिक्चर्स के बैनर तले किया गया है। फिल्म के गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि यह फिल्म भी असमिया सिनेमा के दर्शकों के लिए एक यादगार प्रस्तुति साबित हो सकती है। अब फिल्म प्रेमियों की निगाहें इसके ट्रेलर और रिलीज की तारीख पर टिकी हुई हैं।

लंकेश्वर में अज्ञात शव बरामद

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। जालुकबाड़ी पुलिस चौकी के अंतर्गत लंकेश्वर के समीप कल एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष बतायी जाती है तथा उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी व्यक्ति की नजर लाश पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया तथा पोस्टमॉर्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को शिनाख्त के लिए 72 घंटे के लिए जीएमसीएच के शवगृह में रखा गया।

घटना के संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पायी थी।

तेरापंथ धर्मस्थल में गूंजी भक्ति व श्रद्धा की स्वर लहरियां, भव्य चातुर्मासिक मंगल प्रवेश समारोह संपन्न

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। आचार्य महाश्रमण के सुशिष्य मुनि आनंद कुमार कालू एवं सहवर्ती मुनि विकास कुमार (ठाणा-2) का तेरापंथ धर्मस्थल, गुवाहाटी में भव्य चातुर्मासिक मंगल प्रवेश अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सुबह से हो रही वर्षा के थमने के पश्चात प्रातः 9.49 बजे मुनियों ने शुभकरण मनीष सिंघी के निवास स्थान से मंगल विहार प्रारंभ किया और विशाल धर्मसभा की उपस्थिति में तेरापंथ धर्मस्थल पहुंचकर चातुर्मासिक मंगल प्रवेश किया। इस अवसर पर पूरे परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ मुनिश्री के मंगल महामंत्रोच्चार से हुआ। तत्पश्चात मुनि आनंद कुमार ने चातुर्मास वर्षावास स्थापना कार्यक्रम संपन्न कराया। तेरापंथ महिला मंडल द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। स्वागत समारोह में तेरापंथी सभा गुवाहाटी के अध्यक्ष रितेश खटेड़, सभा के निवर्तमान

अध्यक्ष बाबूलाल सुराणा, तेरापंथी महासभा के उपाध्यक्ष विजय चोपड़ा, तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्ष सुशीला मालू, तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष रोहित सुराणा, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष पंकज भूरा, अणुव्रत समिति की मंत्री रंजना बरड़िया, एटीएमआरएफ के मंत्री अजय भंसाली, अर्हम् भजन मंडली, आध्यात्मिक भजन मंडली शांतिपुर, जैन विश्व भारती के कार्यकारिणी सदस्य मनीष सिंघी, नगांव सभा के अध्यक्ष विनोद बोथरा, खारुपेटिया से पधारी सरोज दुगड़ सहित मुनिश्री के संसार पक्षीय परिजनों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने गीतिकाओं, उद्‌बोधनों एवं भावपूर्ण शब्दों के माध्यम से मुनियों का अभिनंदन किया। अपने प्रेरणादायी मंगल उद्‌बोधन में मुनि आनंद कुमार कालू ने कहा कि चातुर्मास केवल चार महीनों का ठहराव नहीं, बल्कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की साधना का अमूल्य अवसर है। यह आत्मनिरीक्षण, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ समय है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वास्तविक सुख बाहरी भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की शांति, संयम और साधना में निहित है। संतों का सान्निध्य जीवन को नयी दिशा देता है और चातुर्मास के दौरान अधिकाधिक धर्म, स्वाध्याय, सामायिक, प्रेक्षाध्यान तथा सेवा-साधना से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। मुनिश्री ने सभी तेरापंथी संस्थाओं से आह्वान किया कि वे चातुर्मास के दौरान धर्मप्रभावना, संस्कार निर्माण, युवा जागरण, अणुव्रत एवं सेवा कार्यों को और अधिक गति प्रदान करें ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वातावरण निर्मित हो सके। इस अवसर पर आरती सेठिया 11 की तपस्या पूर्ण कर कार्यक्रम में उपस्थित हुईं। मुनिश्री ने उनकी तपस्या की मुक्तकंठ से अनुमोदना करते हुए कहा कि तप आत्मबल को जागृत करने का सशक्त माध्यम है तथा ऐसे तपस्वियों से समाज को प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में गुवाहाटी सहित नगांव, खारुपेटिया एवं अन्य क्षेत्रों से श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित रहीं। धर्मस्थल श्रद्धा, भक्ति, मंगल गीतों एवं जयघोषों से गुंजायमान रहा। पूरे समारोह में अनुशासन, आध्यात्मिक गरिमा और धार्मिक उत्साह का सुंदर समन्वय देखने को मिला। चातुर्मास के इस मंगल प्रवेश के साथ ही गुवाहाटी में आगामी चार महीनों तक विविध धार्मिक, आध्यात्मिक एवं संस्कारमूलक कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ हो गया।

प्रातः खबर
गुरुवार, 23 जुलाई 2026

हग्रामा ने की केएमसीएच की पहली गवर्निंग बॉडी बैठक की अध्यक्षता

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर

कोकराझाड़, 22 जुलाई। बोड़ोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के प्रमुख एवं कोकराझाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (केएमसीएच) की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हग्रामा महिलारी ने कल इस वर्ष की पहली गवर्निंग बॉडी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधायक, कार्यकारी सदस्य (ईएम), एमसीएलए, कोकराझाड़ के जिला आयुक्त, गवर्निंग बॉडी के सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के समग्र कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, आधारभूत संरचना के विकास तथा संस्थान के सुचारु संचालन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में मरीजों, उनके परिजनों तथा कर्मचारियों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में एटीएम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परिसर में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने, आवासीय परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए चारदीवारी निर्माण तथा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट एवं सामान्य कचरा निस्तारण की वैज्ञानिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर विचार किया गया। आगामी एमबीबीएस छात्रों के आवास की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए गवर्निंग बॉडी ने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ (एमसीएच) भवन को एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से छात्रावास (बॉयज़ हॉस्टल) के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दी। साथ ही निर्माणाधीन छात्रावास भवन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिये गये। बैठक में ग्रेड-द्वितीय, ग्रेड-तृतीय एवं ग्रेड-चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की समीक्षा की गयी तथा संस्थान के बेहतर संचालन के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सुरक्षा कर्मी और हाउसकीपिंग स्टाफ की आवश्यकता पर चर्चा हुई। सहायक कर्मचारियों के वेतन के समय पर भुगतान और नियमित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए बीटीसी प्रमुख हग्रामा ने कहा कि संस्थान की चुनौतियों के समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों को लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए दोहराया कि कोकराझाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को एक आधुनिक, पूर्णतः सक्षम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में विकसित करना परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

कोकराझाड़ में ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक

कोकराझाड़, 22 जुलाई (ख.सं)। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कोकराझाड़ की एक बोर्ड बैठक आज जिला आयुक्त सह अध्यक्ष पंकज चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। इस बैठक में कोकराझाड़ शहर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और परिवहन परमिट नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिनमें कोकराझाड़ नगरपालिका क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में ई-रिक्शा के नये पंजीकरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है। यह कदम शहर में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या, कोकराझाड़ नगरपालिका बोर्ड की सिफारिशों और जनता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बोर्ड ने यह भी तय किया है कि दूरदराज के इलाकों और हाईवे से आने वाले ई-रिक्शा के कोकराझाड़ शहर में प्रवेश और संचालन को प्रतिबंधित किया जाएगा क्योंकि ई-रिक्शा मुख्य रूप से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए हैं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य का कोई भी डीलर कोकराझाड़ शहर के 10 किमी दायरे के भीतर के पते पर किसी ई-रिक्शा का पंजीकरण न करे। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि अन्य क्षेत्रों या राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये ऐसे यात्री वाहन, जिन पर सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक काउंटर-हस्ताक्षर नहीं है, उन्हें कोकराझाड़ जिले में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी कोकराझाड़ को नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

तामुलपुर में जिला आयुक्त ने की समीक्षा बैठक

कोकराझाड़, 22 जुलाई (ख.सं)। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर आज तामुलपुर जिला आयुक्त कार्यालय के सभागार में जिला आयुक्त सिमी करण (आईएएस) की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और समारोह को भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने की रूपरेखा तय की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह तामुलपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गयी। बैठक में वृक्षारोपण अभियान, राष्ट्रीय गान, मार्चपास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, मैत्री फुटबॉल मैच, विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी, विशिष्ट व्यक्तियों एवं प्रतिभाओं के सम्मान समारोह सहित अनेक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गयी। इसके अलावा जनगणना-2027 के तहत एक विशेष प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। जिला आयुक्त सिमी करण ने नागरिकों से पोर्टल के माध्यम से सेल्फ एन्यूमरेशन (स्व-गणना) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुमन चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार फहराने, सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसकी जानकारी महकमा सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विजय बेजबरुवा ने मीडिया को दी।

स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर कसा गया शिकंजा

लमडिंग, 22 जुलाई (ख.सं)। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने कल लंका क्षेत्र में विशेष निरीक्षण एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे भोजन बेचने वाले विक्रेताओं, होटलों, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की गहन जांच की गयी। अधिकारियों ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। निरीक्षण अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिष्ठा चेतिया ने किया। उनके साथ फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला की टीम मौजूद रही, जिसका संचालन प्रयोगशाला तकनीशियन सौरव मोदक कर रहे थे। निरीक्षण दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का दौरा कर वहां की स्वच्छता व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा कानूनी मानकों के अनुपालन का आकलन किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भोजन तैयार करने, संग्रहित करने और ग्राहकों को परोसने की पूरी प्रक्रिया में साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि खाद्य पदार्थों के दूषित होने की संभावना को रोका जा सके। अभियान के दौरान व्यवसायियों को यह भी बताया गया कि एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य है। जिन प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी, उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गयी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने समाचार पत्र या अन्य मुद्रित कागज में भोजन परोसने की प्रथा पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग इंक में मौजूद रासायनिक तत्व भोजन में मिलकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए सभी प्रतिष्ठानों को केवल खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही टीम ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच संख्या और अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हों, ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्राप्त हो सके। निरीक्षण के दौरान फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला में उपलब्ध ऑयल टेस्टर की सहायता से खाद्य तेल की गुणवत्ता की मौके पर जांच की गयी। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल किया जा रहा खाद्य तेल निर्धारित सुरक्षा मानकों से अधिक खराब पाया गया।

तालाब में डूबने से बच्चे की मौत

कोकराझाड़, 22 जुलाई (ख.सं)। कोकराझाड़ जिले के ढोलमारा स्थित काठलगुरी में के फ्लाई ऐश (अवशिष्ट पदार्थ) वाले विशाल तालाब में डूबने से एक 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गयी। मृतक बच्चे की पहचान स्थानीय निवासी जीवन राय के पुत्र चंदन राय (8) के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार खेलते समय बच्चे की चप्पल तालाब में गिर गयी थी। उस चप्पल को उठाने के दौरान पैर फिसल जाने से बच्चा तालाब के गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। इस अकाल मृत्यु से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गयी है। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने तालाब पर तैनात जवानों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जमकर रोष व्यक्त किया और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि इतने बड़े और खतरनाक फ्लाई ऐश तालाब के चारों ओर सुरक्षा के लिए कोई बैरिकेडिंग या दीवार नहीं बनायी गयी है, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

अवैध यूरिया खाद के साथ चार गिरफ्तार

सिलचर, 22 जुलाई (ख.सं)। गुप्त सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने लैलापुर में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान दो ट्रकों को रोककर तलाशी ली गयी। इस दौरान बिना वैध दस्तावेज के ले जाये जा रहे दो ट्रकों से भारत यूरिया के 1,050 बोरे जब्त किये गये। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच कर रही है।

कछार में 1.2 करोड़ की हेरोइन जब्त, एक बंदी

सिलचर, 22 जुलाई (ख.सं)। कछार जिले के जिरीघाट में आज दोपहर एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन में बदल गयी, जब असम रायफल्स के सतर्क जवानों ने संदिग्ध ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की। चलाये गये अभियान के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया और लगभग 234 ग्राम हेरोइन वाले 20 साबुन के डिब्बे बरामद किये गये, जिनकी कीमत 1.2 करोड़ रुपये आंकी गयी है। इस ऑपरेशन में एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक मोबाइल हैंडसेट भी जब्त किया गया, माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल तस्करी के सामान को लाने-ले जाने में किया गया था। पकड़े गये व्यक्ति को बरामद नशीले पदार्थों के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया।

सुरंग निर्माण हादसे में गोहपुर के व्यक्ति की मृत्यु

गोहपुर, 22 जुलाई (ख.सं)। सिक्किम में एनएचपीसी के लिए सुरंग निर्माण कार्य में तैनात गोहपुर के एक युवक की हादसे में मौत हो गयी। मृतक की पहचान गोहपुर उप-मंडल के बाकरी दलनी गांव पंचायत के अंतर्गत बेकिजान निवासी बाबुल बरदलै (37) के रूप में हुई है। बाबुल अपने पीछे आठ वर्षीय बेटे, चार महीने की गर्भवती पत्नी जुलीमणि कटकी, माता-पिता और एक भाई को छोड़ गये हैं। उनकी असामयिक मौत की खबर से पूरे गोहपुर में शोक की लहर है। बताया गया है कि बाबुल बरदलै वर्ष 2005 से सिक्किम में काम कर रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए उन्होंने करीब 21 वर्षों तक सिक्किम में काम किया। शुरुआत में मजदूर के रूप में काम करने वाले बाबुल बाद में सुपरवाइजर के पद तक पहुंचे थे।

सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

सिलचर, 22 जुलाई (ख.सं)। सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी ने कछार जिला आयुक्त को आठ सूत्री मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विभिन्न लंबित नागरिक मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग की गयी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सजल आचार्य के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि सिलचर को हाल ही में नगर निगम का दर्जा दिया गया है, लेकिन अप्रैल 2020 में नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से निगम चुनाव नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की कमी के कारण नागरिक सेवाओं, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में बाधा आ रही है। इस ज्ञापन में शहर की कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर किया गया है। इनमें थोड़ी सी बारिश के बाद भी विभिन्न वार्डों में जलभराव, शुद्ध पेयजल की अनियमित आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि, जर्जर सड़कें और खराब जल निकासी व्यवस्था, निर्वाचित बोर्ड के बिना नगरपालिका कर में वृद्धि के आरोप, नगरपालिका निधि के व्यय में पारदर्शिता की कमी, बढ़ता यातायात जाम और युवाओं में नशीली दवाओं की लत और असामाजिक गतिविधियों का प्रसार शामिल हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन से 8 सूत्री मांगें रखी गयी। इन मांगों में नालियों की सफाई और स्थायी जलभराव की समस्या के समाधान के लिए योजना अपनाना, सभी वार्डों में शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति, बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी निगरानी, क्षतिग्रस्त सड़कों और नागरिक बुनियादी ढांचे का शीघ्र जीर्णोद्धार, 2020 से मार्च 2026 तक नगरपालिका के व्यय खाते का प्रकाशन, यातायात जाम के समाधान के लिए प्रभावी यातायात योजना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, नशा-विरोधी अभियान को मजबूत करना और जन जागरूकता बढ़ाना, और सिलचर नगर निगम का शीघ्र चुनाव कराकर लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन को बहाल करना शामिल है। ज्ञापन के अंत में जिला कांग्रेस ने आशा व्यक्त की कि जिला आयुक्त राहुल कुमार गुप्ता इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जनहित में शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएंगे।

बाल विवाह करने पर वार्ड सदस्य ने गंवायी सदस्यता

नगांव, 22 जुलाई (ख.सं)। बाल विवाह में शामिल होने के कारण नगांव जिले के महेरीपार ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य आजिजुर रहमान को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। जिले के बगरीगुरी विकास खंड के अंतर्गत महेरीपार ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 से निर्वाचित सदस्य पर चुनाव के दौरान दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप लगा था। जिला आयुक्त के निर्देश पर की गयी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह नाबालिग अवस्था में ही एक संतान के पिता बन गये थे। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उनका जन्म 31 जनवरी 1999 को हुआ था जबकि उनकी पहली संतान का जन्म 7 अगस्त 2016 को हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि पहला संतान के जन्म के समय उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट तथा सहायक आयुक्त की जांच में भी इस तथ्य की पुष्टि होने के बाद जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार आजिजुर रहमान की ग्राम पंचायत सदस्यता रद्द कर दी गयी।

तेजपुर राउंड टेबल 351 की 5वीं वार्षिक आम सभा संपन्न

तेजपुर, 22 जुलाई (ख.सं)। तेजपुर राउंड टेबल 351 ने वर्ष 2025-26 की अपनी 5वीं वार्षिक आम सभा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। निवर्तमान चेयरमैन विशाल बोरा ने वर्षभर के दौरान टेबल द्वारा किये गये विभिन्न सेवा प्रकल्पों, उपलब्धियों एवं गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पुरस्कार वितरण समारोह में शिवम चंदक को बेस्ट फ्लोर टैबलर अवॉर्ड तथा पुनीत जैन को बेस्ट डेब्यूटेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। आशीष सोनी, जयंत टिबड़ेवाला, कार्तिक दुग्गड़ एवं चेतन सराफ को फोर पिलर्स ऑफ द टेबल के रूप में सम्मानित किया गया। स्क्वॉयर लेग वरुण अग्रवाल को जुलाई 2026 स सक्रिय टैबलिंग से सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में लेजेंडरी अवॉर्ड एवं रिटायरमेंट प्लाक प्रदान किया गया। एजीएम के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए नयी हेड बोर्ड का भी विधिवत स्थापना समारोह आयोजित किया गया। जयंत टिबड़ेवाल ने टेबल चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। तीर्थ राज भूतोड़िया को टेबल सेक्रेटरी, पुनीत जैन को वाइस चेयरमैन, विशाल बोरा को इमीडिएट पास्ट चेयरमैन तथा यश झाबक को ट्रेजरर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों को विभिन्न दायित्वों एवं समितियों का संयोजक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर एरिया 14 के एरिया चेयरमैन चंद्रकांत वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गुवाहाटी से देवांशु स्वामी एरिया ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुए जबकि तिनसुकिया से सिद्धांत लोहिया एवं एरिया 14 के एरिया चेयरमैन-इलेक्ट ट्र. चेतन सराफ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एजीएम में जयंत टिबड़ेवाल, आशीष सोनी, विशाल बोरा, तीर्थ राज भूटोरिया, पुनीत जैन, चेतन सराफ, अंकित सेठिया, शिवम चंदक, स्क्वॉयर लेग वरुण अग्रवाल एवं यश झाबक सहित नगांव, गुवाहाटी एवं डिब्रुगढ़ से आये अनेक टैबलर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन गणमान्य अतिथियों के प्रेरणादायक संबोधनों के साथ हुआ। सभी अतिथियों ने उत्कृष्ट आयोजन एवं आतिथ्य की सराहना की। एरिया ऑब्जर्वर एलएमएफ देवांशु स्वामी ने वार्षिक आम सभा को आधिकारिक रूप से वैध घोषित करते हुए तेजपुर राउंड टेबल 351 को एक और सफल एवं यादगार टैबलिंग वर्ष पूर्ण करने पर बधाई दी।

नलबाड़ी में पीएम अजय योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरित

नलबाड़ी, 22 जुलाई (ख.सं)। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति पीएम अजय योजना के तहत आज नलबाड़ी जिले की अनुसूचित जाति की महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय अनुदान के स्वीकृति पत्र वितरित किये गये। स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम आज नलबाड़ी जिला पुस्तकालय सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में निम्नलिखित विशिष्ट जन उपस्थित रहे। नलबाड़ी के जिला आयुक्त निवेदन दास पटवारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव सह अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की निदेशक डॉ. कुलश्री नाथ, नलबाड़ी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ध्रुवज्योति हजारिका, जिला कृषि अधिकारी समाजसेवी जयंत बुजरबरुवा, जिला परिषद अध्यक्ष गीतुमणि वैश्य, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला योजना प्रबंधक शिवालिका मेधी उपस्थित थे। कार्यक्रम में 147 अनुसूचित जाति महिला स्वयं सहायता समूहों और 15 महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से सब्सिडी (अनुदान) के स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये। इनमें से आज औपचारिक रूप से 6 स्वयं सहायता समूहों और 1 महिला को स्वीकृति पत्र सौंपे गये। कार्यक्रम में जिला आयुक्त निवेदन दास पटवारी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि महिलाएं आज कमजोर नहीं हैं, बस उन्हें खुद को सशक्त समझना होगा। आज नलबाड़ी की महिलाएं केंचुआ खाद बेचकर न केवल खुद स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं बल्कि दस अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। इसलिए महिलाओं को खुद को कमजोर न मानकर आगे आना चाहिए। मुख्य अतिथि डॉ. कुलश्री नाथ ने कहा कि जिन महिलाओं को यह 50000 की सब्सिडी मिली है, वे इस राशि का उपयोग अपने व्यावसायिक कार्यों में करें। डॉ. नाथ ने यह भी कहा कि जब वे इस पैसे का सही और उत्पादन-उन्मुख कार्यों में उपयोग करेंगी, तभी पीएम अजय योजना वास्तव में सफल होगी और पैसे का मिलना सार्थक होगा। कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवी जयंत बुजरबरुवा और जिला परिषद अध्यक्ष गीतुमणि वैश्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

नीट परीक्षा में सफल मेधावी छात्र का अभिनंदन

कोकराझाड़, 22 जुलाई (ख.सं)। नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने वाले दीप कुमार नाथ के आवास पर आज अखिल असम बंगाली छात्र फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और उन्हें सम्मानित किया। दीप कुमार नाथ पान किष्णो देबनाथ और सुप्रिया देबनाथ के पुत्र हैं। संगठन के सदस्यों ने मेधावी छात्र दीप कुमार नाथ को जातीय गामोछा और मानपत्र भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अखिल असम बंगाली छात्र फेडरेशन की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष गोपाल घोष, महासचिव इंद्रजीत देबनाथ, कोकराझाड़ जिला समिति के महासचिव देब सरकार और बंगाली टाइगर फोर्स के कोकराझाड़ जिला समिति के सचिव अरबिंद देबनाथ सहित कई अन्य संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बाढ़ प्रभावित सेक्शनों में बहाली का काम जोरों पर : पूसीरे

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं)। दिखो नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) के तिनसुकिया मंडल के अधीन शिवसागर ज़िला अंतर्गत शिमलगुड़ी टाउन स्टेशन और आस-पास के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पानी के बहाव से शिमलगुड़ी स्टेशन यार्ड और रेल कॉलोनी के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं और प्रभावित सेक्शनों में रेल पटरियों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने बुधवार को बताया कि चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद, तिनसुकिया मंडल ने ट्रेन सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए 247 निगरानी के साथ व्यापक पैमाने पर बहाली कार्य शुरू किया है। मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारियों की अगुवाई में इंजीनियरिंग टीमें बाढ़ के पानी के असर से निपटने और ट्रेन सेवाओं को जल्द बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर निरंतर कार्य कर रही हैं। सेलेंगहाट-आमगुड़ी सेक्शन में अभी मरम्मत और बहाली का कार्य ज़ोरों पर चल रहा है। यहां मरम्मत और बहाली के कार्य में तेज़ी लाने के लिए रेल इंजीनियरों और सुपरवाइज़रों सहित 200 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। ये कर्मचारी ट्रैक की बहाली, बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और प्रभावित स्थलों का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि ट्रेनों का परिचालन सुरक्षित रूप से पुनः शुरू किया जा सके। विगत दिनों से शिवसागर टाउन-शिमलगुड़ी सेक्शन में भी मरम्मत का व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। खराब मौसम के बावजूद रेल कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कार्य प्रगति पर है। पूसीरे के वरिष्ठ अधिकारी बहाली कार्य की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जबकि सभी संबंधित विभाग एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, ताकि ट्रेन सेवाओं में व्यवधान कम से कम हो और जल्द से जल्द हालात सामान्य हो सकें। यात्रियों की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि बहाली का कार्य कुशल और सुरक्षित तरीके से पूरा हो।

मणिपुर में पिस्तौल के साथ प्रीपाक (प्रो) का सक्रिय कैडर गिरफ्तार

इंफाल, 22 जुलाई (एजें)। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के थौबल ज़िले में एक अभियान के दौरान प्रतिबंधित प्रीपाक (प्रोग्रेसिव) गुट के एक सक्रिय कैडर को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार व्यक्ति की पहचान स्वयंभू कैप्टन लौरमबम कुमार मैतेई (उर्फ़ कांतो, उर्फ़ नाओबी, उर्फ़ अबुंग) (43) के रूप में हुई है, जो इंफाल वेस्ट ज़िले के हाओबम मारक लौरम लीकाई का रहने वाला है। पुलिस अधिकारियों ने आज बताया है कि यह अभियान 21 जुलाई को थौबल ज़िले के लिलोंग पुलिस स्टेशन के तहत लिलोंग आलिया लमखाई इलाके में चलाया गया था, जिसमें उग्रवादी को पकड़ा गया। अभियान के दौरान, सुरक्षा कर्मियों ने उसके पास से एक .32 कैलिबर की पिस्तौल और एक मैगज़ीन बरामद की। गिरफ़्तार सदस्य और ज़ब्त हथियार को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। सुरक्षा बल राज्य भर में 'शांति के लिए हथियार छोड़ें' पहल के तहत उग्रवाद-विरोधी अभियान और अवैध हथियार बरामद करने की कोशिशें तेज कर दिए हैं।

मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों ने पीएमजीएसवाई का पुल उड़ाया

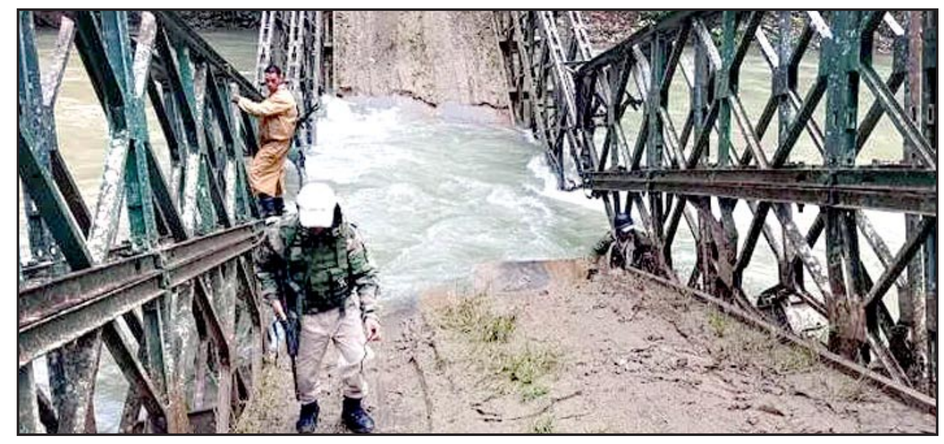

इंफाल, 22 जुलाई (एजें)। मणिपुर के कामजोंग जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बने एक बेली पुल को विस्फोट कर उड़ा दिया। इस घटना से कई गांवों का जिला मुख्यालय से एकमात्र सड़क संपर्क टूट गया। पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 9:30 बजे फांगे और चाट्रिक गांवों के बीच नंबान लोक नदी पर बने पुल पर हुई। प्रारंभिक जांच में पुल को उड़ाने के लिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। हमलावरों ने घटना के दौरान नदी किनारे खड़े दूरसंचार विभाग के एक वाहन में भी आग लगा दी, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। पुलिस का कहना है कि यह पुल चाट्रिक तथा आसपास के गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग था। अधिकारियों के अनुसार, हमले का उद्देश्य सार्वजनिक अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना, परिवहन और संचार सेवाओं को बाधित करना, लोगों की आवाजाही रोकना तथा क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करना था। पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सीएसडी थाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे किसी भी उग्रवादी संगठन ने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है।

भाजपा ने राहुल गांधी पर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने का लगाया आरोप

इटानगर, 22 जुलाई (एजें)। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करने और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की आज कड़े शब्दों में निंदा की। आज इटानगर में भाजपा मुख्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुत्चू मिथी ने कहा कि निट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप इस रैकेट में कथित तौर पर शामिल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। तुरंत दोबारा परीक्षा भी आयोजित की गई और इस मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि विरोध क्यों किया जा रहा है। सरकार देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की मदद से यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करने और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की कड़ी निंदा करते हैं। जबकि, उनकी मांग के अनुसार भाजपा संसद में इस मामले को उठाने के लिए तैयार थी, उन्होंने अपनी बात बदल दी और विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने लगे और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने इटानगर के राजभवन के सामने भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, और इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस शांति नहीं चाहती है और बातचीत से मामले को हल करना नहीं चाहती है; कांग्रेस देश में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की योजना बना रही है। आज प्रदेश भाजपा ने भी कांग्रेस पार्टी के कानून विरोधी कृत्य के जवाब में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस भवन के सामने धरना आयोजित किया।

अरुणाचल के बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रशासन चला रही हवाई सेवा

इटानगर, 22 जुलाई (एजें)। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी ज़िला प्रशासन ने बुधवार से निलिंग, लिंगदाम और अपर गिबा के दूर-दराज गांव और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जरूरी खाने-पीने का सामान हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से पहुंचाना (एयरलिफ़्टिंग) शुरू कर दिया है। हाल ही में मॉनसून की बारिश से सड़कें और पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे इन इलाकों का संपर्क टूट गया था; प्रशासन यह पक्का कर रहा है कि यहां रहने वाले लोगों को सामान की सप्लाई बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। भारी बारिश के बाद, न्यो और जाओ नदियों में कटाव के कारण निलिंग और अपर गिबा सर्कल को जोड़ने वाली सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। जाओ नदी पर बना पुल भी बह गया, जिससे अपर गिबा के 22 गांव ज़िला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए। इसके अलावा, सड़क संपर्क टूटने की वजह से निलिंग सर्कल के 20 गांव भी अलग-थलग पड़ गए हैं। लिंगदाम और निलिंग तक सड़क संपर्क भी टूट गया, जिससे सड़क मार्ग से ज़रूरी सामान पहुंचाना नामुमकिन हो गया था। प्रभावित लोगों की मुश्किलों को देखते हुए, जिला उपायुक्त के अगुवाई में जिला प्रशासन ने तुरंत हेलीकॉप्टर सेवाएं लेने की प्रक्रिया शुरू की। स्थानीय विधायक तानिया सोकी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अनाज, दवाइयां व अन्य ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नागरिक उड्डयन निदेशालय को अनुरोध भेजा। नागरिक उड्डयन निदेशालय ने अनुरोध को मंजूरी दे दी और 22 व 23 जुलाई के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानों का नया शेड्यूल जारी किया है। इन उड़ानों के जरिए डपोरिजो से लिंगदाम और निलिंग तक चावल और अन्य ज़रूरी सामान पहुंचाया जा रहा है, ताकि प्रभावित लोगों तक बिना देरी के राहत सामग्री पहुंच सके। ज़िला प्रशासन ने नागरिक उड्डयन विभाग, ज़िला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय, सर्कल प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर हेलीपैड पर सभी ज़रूरी इंतज़ाम किए हैं। इनमें दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, आग और आपातकालीन सेवाएं, सफ़ाई, रुकावटें हटाना और सुरक्षा के अन्य उपाय शामिल हैं। ज़िला प्रशासन ने अरुणाचल प्रदेश सरकार, नागरिक उड्डयन निदेशालय, हेलीकॉप्टर क्रू, सभी संबंधित विभागों और स्थानीय प्रतिनिधियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इन सभी के समय पर सहयोग और मिलकर किए गए प्रयासों से ही अपर सुबनसिरी ज़िले के सबसे दूर-दराज़ और दुर्गम इलाकों तक ज़रूरी सामान पहुंचाना मुमकिन हो पाया है।

सिक्किम विस के बजट सत्र का तीसरा दिन, तीन विधेयक पारित

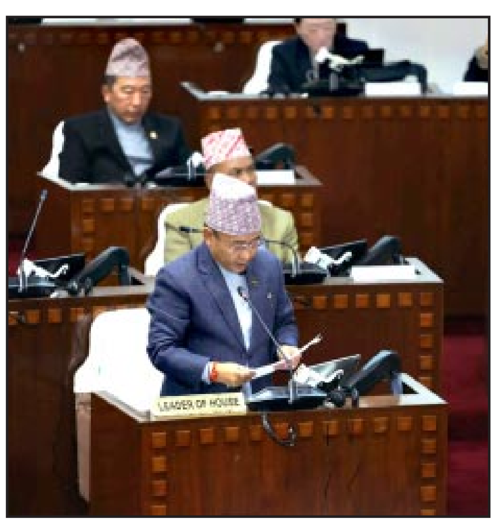

गंगटोक, 22 जुलाई (एजें)। सिक्किम विधानसभा के चार दिवसीय बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन ने तीन विधेयक पारित किए। इसके साथ ही एक सरकारी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई तथा पांच विभागों से संबंधित अनुदान की मांगों को भी पारित किया गया। सदन ने शिक्षा विभाग के मंत्री राजू बस्नेत द्वारा प्रस्तुत सिक्किम निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, सिक्किम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित किया। इसके अलावा, गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा प्रस्तुत सिक्किम अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन से पारित हो गया। ये सभी विधेयक संबंधित मंत्रियों ने 20 जुलाई को बजट सत्र के पहले दिन सदन में पेश किए थे। इसी प्रकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री पिंछो नामग्याल लेप्चा द्वारा प्रस्तुत तथा विधायक सोनाम छिरिंग वेंचुंगपा द्वारा समर्थित सरकारी प्रस्ताव संख्या-02, 2026 को भी सदन ने स्वीकृति प्रदान की। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2024 को सिक्किम राज्य में लागू करने से संबंधित था। सदन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद उन्हें भी पारित कर दिया। इनमें भवन एवं आवास तथा श्रम विभाग के मंत्री भीम हांग लिम्बू, शहरी विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री भोजराज राई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संस्कृति तथा आयुष विभाग के मंत्री जीटी ढुंगेल, कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा तथा मत्स्य विकास विभाग के मंत्री पूरण कुमार गुरूंग, तथा वन एवं पर्यावरण, खान एवं भूविज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री पिंछो नामग्याल लेप्चा द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगें शामिल थीं।

चार संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक चढ़े पुलिस के हत्थे

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। असम के कमलपुर के पुठिमारी क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के संदेह में एक बच्चे समेत चार संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार, सतर्क ग्रामीणों ने चारों को संदिग्ध परिस्थितियों में रोका और पूछताछ के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर उनकी पहचान, नागरिकता और राज्य में कथित प्रवेश की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।

पर्यावरण संरक्षण : कचरे से रोजगार की ओर

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, उत्तर गुवाहाटी शाखा द्वारा कल पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष योजना का आयोजन किया गया। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं ने अपने पुराने वस्त्र जिनमें अंडर गार्मेंट्स, मौजे और एकदम अनुपयोगी कपड़े शामिल थे, जिन्हें पुनः चक्रित कर कालीन बनाये जाएंगे। संस्था की अध्यक्ष इंदु पारीक ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कचरे को कम करना और पर्यावरण को मीथेन गैस के दुष्प्रभाव से बचाना है। पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय उनका दोबारा उपयोग करने से न केवल कचरा कम होगा, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि एक टी-शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी बर्बाद होता है और रोज सड़कों पर एक ट्रक से भी ज्यादा पुराने कपड़े फेंके जाते हैं। उपाध्यक्ष पूनम पारीक ने बताया कि हमने कुल 24 कालीन का ऑर्डर दिया है ताकि रोजगार भी मिल सके। इन कालीनों को स्कूलों और वृद्धाश्रम में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर सलाहकार विनीता पारीक, सचिव राखी गुप्ता, किरण साबू ,उषा शर्मा, श्वेता नौहाल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थी।

पश्चिम कार्बी आंग्लांग के वरिष्ठ व्यापारी का निधन

खेरनी 22 जुलाई (ख.सं)। पश्चिम कार्बी आंग्लांग जिले के माइलू बाजार निवासी गिरबानेंदु राय का 78 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। वे लंबे समय से माइलू बाजार में निवास कर रहे थे और वर्ष 1966 से लगातार अपनी दुकान का संचालन कर रहे थे। गिरबानेंदु राय एक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यवसायी थे। अपने मिलनसार स्वभाव और सभी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार के कारण वे पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय थे। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए आज सुबह 5:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक माइलू बाजार की सभी दुकानें बंद रखी गईं। शाम 6:30 बजे उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, दीप प्रज्वलित किया गया तथा एक मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम माइलू बाजार समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें सभी स्थानीय दुकानदारों ने सक्रिय सहयोग किया। गिरबानेंदु राय न केवल माइलू क्षेत्र बल्कि पूरे जिले की अनेक सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है।

कछार पुलिस ने 13 अपराधियों को किया गिरफ्तार

कछार, 22 जुलाई (एजें)। कछार जिला के विभिन्न इलाकों में पुलिस द्वारा बीते दो दिनों में चलाए गये सात अभियानों में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान मादक पदार्थ, यूरिया खाद, भारी मात्रा में हेरोइन, गांजा, याबा टैबलेट्स एवं अन्य सामग्री बरामद किया गया है। कछार पुलिस मुख्यालय द्वारा बुधवार को दी गयी जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों में सात अभियान चलाए गए। इस दौरान कचुदारम थाना क्षेत्र से दस साबुनदानी में छिपाए गये संदिग्ध हेरोइन (119.11 ग्राम) और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस मामले में एक आरोपित को पकड़ा गया। वहीं, धोलाई थाना की पुलिस द्वारा रोके गए एक ऑटो-रिक्शा से चार साबुनदानी में छिपाकर लाए गये संदिग्ध हेरोइन (49 ग्राम) बरामद कर एक आरोपित को पकड़ा गया। इसी कड़ी में सिलचर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 2.113 किलोग्राम संदिग्ध गांजा बरामद कर दो आरोपित को गिरफ्तार किया। कछार जिला मुख्यालय शहर सिलचर बाईपास इलाके से 26 शीशियों में छिपाकर लाए गये संदिग्ध हेरोइन (0.79 ग्राम) बरामद किया गया। इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। जिरीघाट थाना की पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से 20 साबुनदानी में छिपाकर लाए गये संदिग्ध हेरोइन (234 ग्राम) बरामद किये गये। साथ ही एक आरोपित को पकड़ा गया। सिलचर थाने की पुलिस ने एक वैगनआर (एएस-11सी-4461) से संदिग्ध याबा टैबलेट (24,000 टैबलेट) बरामद किया गया। पुलिस ने एक गाड़ी और चार मोबाइल फोन ज़ब्त किए। इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। धोलाई थाना क्षेत्र के लैलापुर इलाके से दो ट्रकों से भारत यूरिया फर्टिलाइज़र के 1,050 बैग (प्रत्येक 45 किलोग्राम) बरामद किये गये। इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। सातों अभियानों में बरामद कुल संदिग्ध हेरोइन के 34 साबुन के डिब्बे व 26 शीशियां (402.90 ग्राम), संदिग्ध याबा टैबलेट (24,000 टैबलेट), संदिग्ध गांजा (2.113 किलो), भारत यूरिया फर्टिलाइज़र के 1,050 बैग शामिल हैं। वहीं एक वैगनआर कार, एक ऑटो-रिक्शा, एक बाइक, दो ट्रक और पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए।

सीजेपी जैसे संगठन को राज्य में पनपने नहीं दे सरकार : हिंदू सुरक्षा सेना

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख. स.)। हिंदू सुरक्षा सेना, असम ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) जैसे संगठन असम में नहीं पनप सके इसके लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है। हिंदू सुरक्षा सेना के अध्यक्ष कंचन नाथ और महासचिव आकाश सैकिया ने एक बयान जारी कर सीजेपी पर राष्ट्र और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर ऐसे संगठनों को पनपने से पहले नहीं रोका गया तो राज्य विनाश और अराजकता के एक अभूतपूर्व युग में प्रवेश करेगा। बयान में कहा गया है कि सीजेपी कोई पार्टी या संगठन नहीं है। यह देशद्रोही, गद्दार हिंदू वामपंथी इस्लामी पारिस्थितिकी तंत्र का एक नया चेहरा है। नाथ और सैकिया ने कहा कि असम जैसे संवेदनशील राज्य में सीजेपी का उदय अधिक खतरनाक होगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ साल पहले पूरे देश में सीएए के विरोध के पीछे ऐसे ही तत्व का हाथ था। इसके चलते देश के संसाधन नष्ट किये गये, देश की सुरक्षा में रुकावट आयी, देशवासियों के मानवाधिकारों का हनन हुआ, नागरिकों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और पूरे देश का विकास रुका। इसलिए सरकार और प्रशासन इस बार भी वही गलती नहीं करेगा।

एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। असम साहित्य सभा द्वारा आज अपने पूर्व अध्यक्ष, मूर्धन्य कवि, गीतकार, उपन्यासकार और बाल-साहित्यकार नवकांत बरुआ की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी स्थित भगवती प्रसाद बरुआ भवन में एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन उपसमिति के संयोजन और सेउज स्वर्ण शाखा साहित्य सभा की मेजबानी में संपन्न इस कार्यक्रम में कृष्णकांत हैंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. प्राणजीत बोरा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान डॉ. बोरा ने नवकांत बरुआ के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हे अरण्य, हे महानगर के अंग्रेजी अनुवाद द वुड्स, द सिटी का औपचारिक विमोचन किया। इस पुस्तक का अनुवाद कॉटन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर प्रदीप आचार्य ने किया है। डॉ. बोरा ने कहा कि नवकांत बरुआ सदैव असम के एक सर्वमान्य और वरेण्य साहित्यकार रहेंगे तथा इस अनुवाद ग्रंथ का प्रकाशन कर असम साहित्य सभा ने अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया है। साहित्य सभा के उपाध्यक्ष पदुम राजखोवा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में उन्होंने नवकांत बरुआ को असमिया कविता का सम्राट बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मातृभाषा के शुद्ध प्रयोग और संरक्षण से ही किसी जाति का अस्तित्व अक्षुण्ण रह सकता है। वहीं साहित्य सभा के महासचिव देवजीत बोरा ने कहा कि यह आयोजन असमिया साहित्य और समाज में नवकांत बरुआ के ऐतिहासिक योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। सम्मानित अतिथि एवं अनुवादक प्रोफेसर प्रदीप आचार्य ने स्मरण किया कि नवकांत बरुआ ने अपने जीवनकाल में ही उनसे इस कृति का अंग्रेजी अनुवाद करने की इच्छा जताई थी, जिसे आज साहित्य सभा ने साकार कर दिया है। समारोह की शुरुआत गोविंद कलिता और कवि मनोज कुमार दास द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद सेउज स्वर्ण शाखा साहित्य सभा के सदस्यों ने बरुआ के जीवन पर आलेख पाठ, कविता पाठ और संगीतमय प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान आयोजित विशेष कवि-शिविर में राज्यभर से आए सैकड़ों काव्य-प्रेमियों ने हिस्सा लिया, जहां आलोचक राजीव बरुआ और अरिंदम बोरकटकी ने काव्य सृजन के विभिन्न आयामों पर मार्गदर्शन दिया। अवनी बोरा और उपम सैकिया ने नवकांत बरुआ की कविताओं का ओजस्वी पाठ किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान सचिव डॉ. जगदीश पाटगिरि और कामरूप महानगर जिला साहित्य सभा के अध्यक्ष प्रफुल्ल बर्मन सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।

बाढ़ में फंसे यात्रियों के लिए चलायी जा रही अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) के तिनसुकिया मंडलाधीन शिवसागर जिले के शिमलगुड़ी शहर और आस-पास बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, रेल यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिमलगुड़ी-नामतिआलि और शिमलगुड़ी से लेंगहाट सेक्शनों के बीच ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से आने-जाने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों का रूट परिवर्तन कर उसे वाया रंगियारंगापाड़ा नॉर्थडिब्रूगढ़ होकर चलाया जा रहा है। कुछ सेवाओं को बीच में ही किसी सुरक्षित स्टेशन पर रोक दिया गया है या फिर वहीं से यात्रा प्रारंभ की गयी है और कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। इन व्यवधानों से प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए, दो अतिरिक्त जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इसका विवरण इस प्रकार है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने आज बताया है कि 22 से 26 जुलाई तक प्रतिदिन तिनसुकिया और भोजो के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गयी है। ट्रेन संख्या 05911 (तिनसुकिया भोजो) स्पेशल तिनसुकिया से 12 बजे रवाना होकर उसी दिन भोजो 14:00 बजे पहुंचती है। वापसी में, ट्रेन संख्या 05912 (भोजो न्यू तिनसुकिया) स्पेशल भोजो से 15:00 बजे रवाना होकर उसी दिन न्यू तिनसुकिया 16:35 बजे पहुंचती है। 22 से 26 जुलाई तकप्रतिदिन न्यू तिनसुकिया और मोरानहाट के बीच एक अन्य स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गयी है। ट्रेन संख्या 05913 (न्यू तिनसुकिया मोराणहाट) स्पेशल, न्यू तिनसुकिया से 16:45 बजे रवाना होकर उसी दिन मोरानहाट 19:30 बजे पहुंचती है। वापसी में, ट्रेन संख्या 05914 (मोरानहाट-तिनसुकिया) स्पेशल, मोरानहाट से 20:00 बजे रवाना होकर उसी दिन तिनसुकिया 23:00 बजे पहुंचती है। इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा, पूसीरे ने इस रूट पर फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए लामडिंग मरियानी जंक्शन और रंगिया मरियानी जंक्शन के बीच पहले ही तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है।

लक्षण नहीं, कारण का उपचार जरूरी

हाल के वर्षों में देश में प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं। प्रश्नपत्र लीक, मूल्यांकन में अनियमितताएं, भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब और पारदर्शिता की कमी ने युवाओं के मन में गहरी असुरक्षा पैदा कर दी है। जब किसी समाज का युवा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त न हो, तब असंतोष का सड़कों पर उतरना केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि शासन व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी बन जाता है।

किसी भी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। यह अधिकार शांतिपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। वहीं सरकार का भी दायित्व है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। यदि प्रदर्शन हिंसक होता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या पुलिस पर हमला होता है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि सुरक्षा बलों द्वारा भी अनावश्यक बल प्रयोग, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार या मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं तो उनकी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में जवाबदेही एकतरफा नहीं हो सकती।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि युवाओं का गुस्सा केवल किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। यह वर्षों से जमा हो रही निराशा और अविश्वास का विस्फोट है। लाखों विद्यार्थी अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने और बेहतर भविष्य की उम्मीद में दिन-रात मेहनत करते हैं। उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का अवसर होती है। जब बार-बार प्रश्नपत्र लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं या परिणाम विवादों में घिरते हैं, तब केवल परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि युवाओं का विश्वास भी टूटता है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा और रोजगार सामाजिक गतिशीलता के सबसे बड़े साधन हैं। एक साधारण परिवार का छात्र कठिन परिश्रम के बल पर प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य क्षेत्रों में स्थान बनाकर अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल सकता है। यदि यही व्यवस्था संदिग्ध हो जाए तो समाज में निराशा, हताशा और असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का भी प्रश्न है।

सरकारों को यह समझना होगा कि केवल प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर देना या पुलिस बल के सहारे आंदोलन दबा देना स्थायी समाधान नहीं है। इससे समस्या कुछ समय के लिए शांत दिखाई दे सकती है, लेकिन असंतोष की जड़ें और गहरी होती जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुरक्षित और जवाबदेह बनाया जाए। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, समयबद्ध जांच, दोषियों को त्वरित एवं कठोर दंड तथा स्वतंत्र परीक्षा नियामक तंत्र जैसे कदम अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुके हैं।

साथ ही, सरकार और युवाओं के बीच संवाद भी उतना ही आवश्यक है। विद्यार्थियों की आशंकाओं को सुनना, उनकी शिकायतों का समय पर समाधान करना और भर्ती प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। लोकतंत्र में संवाद हमेशा टकराव से अधिक प्रभावी होता है।

अंततः किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा वर्ग होता है। यदि वही व्यवस्था पर भरोसा खोने लगे तो यह केवल शिक्षा प्रणाली की विफलता नहीं, बल्कि शासन की भी चुनौती है। इसलिए समय की मांग है कि सरकार विरोध के स्वर को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानने की भूल न करे। लक्षणों का उपचार अस्थायी राहत देता है, जबकि स्थायी समाधान कारणों को दूर करने में है। युवाओं का विश्वास लौटाना ही आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है।

जिन प्रेम कियो, तिन ही प्रभ पायो

सागर किनारे खड़े होकर उसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, समुद्र की गहराई तो उसमें डूब कर ही पता लगायी जा सकती है। उसी तरह प्रेम के ढाई आखर को समझने के लिए, प्रेम, प्यार को समझने के लिए गहन चिंतन में डुबकी लगानी पड़ती है। प्रेम में है त्याग, निःस्वार्थ की भावना, विशालता और उदारता। किसी में खो जाना, उसके प्रेम में डूब जाने का नाम प्यार है। अपना कुछ नहीं, सब तेरा। तेरा तुझको सौंपिओ, क्या लागे है मेरा प्रेम की भावना में निहित है, मैं नहीं तू। ढाई आखर प्रेम के, जो पढ़े, सो पंडित होए। प्रेम एक गहरी अनुभूति है, जो लगाव, स्नेह, समर्पण और निःस्वार्थ पर आधारित है। यह केवल एक भावना ही नहीं बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक लगाव है। प्रेम एक भावनात्मक लगाव है। जब व्यक्ति अपने-आप को खो देता है, फिर वह स्वयं को पा लेता है। स्वयं को पा लेना ही प्रेम है। प्रेम तीन प्रकार का होता है-प्रेम जो आकर्षण से पैदा होता है; जो सुख-सुविधा के लोभ से होता है तथा तीसरा है दिव्य प्रेम। जो प्रेम आकर्षण से पैदा होता है वह क्षणिक है, क्योंकि ऐसा प्रेम अज्ञान या सम्मोहन के कारण पैदा होता है। ऐसे प्रेम से व्यक्ति का मोह जल्दी भंग हो जाता है क्योंकि आकर्षण स्थायी नहीं होता। आकर्षण खत्म तो प्रेम भी खत्म। जिस प्रेम में सुख-सुविधा मिलती है, वह मात्र घनिष्ठता है। ऐसे प्रेम में कोई जोश, उत्साह या आनंद नहीं रहता। सुख-सुविधा प्राप्त करना व्यक्ति की आदत बन जाती है। आदत में प्रेम नहीं होता। दिव्य प्रेम रांझा ने किया। दोनों हीर और रांझा सात्विक रहे। सस्सी पुन्नू के प्यार में दीवानी बनी, मरुस्थलों में आहें भरती रही, सोहनी महिवाल के प्रेम में पक्के और कच्चे घड़े में अंतर ही न कर सकी और दरिया में डूब गयी। साहिबां ने मिरजे-खान को अपने भाईयों से मरवा दिया परंतु प्रेम में सात्विकता सभी प्रेमियों ने बनाये रखी। प्रेम में मीरा दीवानी हो गयी। द्रौपदी ने संकट में अपने कृष्ण को पुकारा तो वह दौड़े चले आये। प्रेम राधा ने किया, इसलिए कृष्ण से पहले उसका नाम आया। गोपियां कृष्ण के साथ पहले रास-रचाती रहीं, फिर उनकी विरह में रोती रहीं। तुलसीदास प्रेम में संन्यासी हो गये और रामचरित मानस की रचना कर अमर हो गये। प्रेम में कोई ताजमहल बना गया, कई रेल की पटरियों पर कट मरे। प्रेम में सोनम ने अपने प्रेमी की खातिर अपने नव-विवाहित पति को मरवा दिया। प्रेम में सिया गोयल ने अपने प्रेमी के लिए अपने करोड़पति मंगेतर को लोहागढ़ किले से धक्का देकर 400 फुट की गहरी खाई में धकेल दिया। यह प्रेम नहीं बदला है, इसमें घृणा है। प्रेम में घृणा तो पाप है। जिस प्यार में बदला लेने का भाव हो, ऐसा प्रेम समय के साथ दूषित हो जाता है। दिव्य प्रेम तो आकाश जैसा विशाल और विस्तृत है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं वैसे ही दिव्य प्रेम की कोई सीमा नहीं। जो दिव्य प्रेम में रंग गया, उसके लिए सब तरफ हरा ही हरा है। दिव्य प्रेम में प्रकाश ही प्रकाश है। प्रेम किसी शब्दकोष में नहीं ढूंढा जा सकता। प्रेम को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। दिव्य प्रेम अनुभव से आता है। प्रेम एक आग है, जिस तरह सोना जितना ही अग्नि में डालते जाओ वह लगातार निखरता ही जाता है। उसी तरह प्रेम की अग्नि में जलकर व्यक्ति में शुद्धता आती है। प्रेम में व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। मनुष्य में जो कुछ व्यर्थ है वह जल जाता है। धुल जाता है। प्रेम ही परमात्मा है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पापी-मनुष्य में प्रेम नहीं होता। प्यार की कमी के कारण ही समाज में अराजकता है। हिंसा है। जहां प्रेम नहीं, वहां शांति नहीं। प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जैन धर्म के संस्थापक स्वामी महावीर जी ने कहा है कि अहिंसा का अर्थ है-प्रेम।

-मा. मोहन लाल

नये भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय

ललित गर्ग

भारत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि यदि संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टि और नवाचार का संगम हो तो आकाश भी सीमा नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रारंभ बन जाता है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और विज्ञान-प्रधान भविष्य की ओर बढ़ते राष्ट्र का एक नया घोषणापत्र है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन आगमन के अंतर्गत हुई यह ऐतिहासिक उड़ान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गयी है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब अंतरिक्ष विज्ञान केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी उद्यम भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे। निश्चित ही विक्रम-1 नये भारत की अंतरिक्ष उड़ान का स्वर्णिम अध्याय एवं निजी अंतरिक्ष क्रांति की आकाशीय सफलताओं की नयी जमीन है। विक्रम-1 की सफलता उस महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने कभी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान विलासिता नहीं, बल्कि विकास का अनिवार्य साधन है। आज उसी विचार की आधुनिक अभिव्यक्ति स्काईरूट एयरोस्पेस के रूप में दिखायी देती है, जिसने अपने पहले ही प्रयास में इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय दुनिया में केवल कुछ ही देशों के निजी उपक्रम ऑर्बिटल रॉकेट विकसित कर पाये हैं। भारत अब उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जहां नवाचार, वैज्ञानिक कौशल और उद्यमशीलता मिलकर नयी संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका के स्पेसएक्स ने जिस निजी अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत की थी, भारत ने अब उसका अपना स्वदेशी संस्करण प्रस्तुत कर दिया है।

विक्रम-1 की तकनीकी विशेषताएं भी इसे विशिष्ट बनाती हैं। पूरी तरह कार्बन कंपोजिट से निर्मित यह रॉकेट अपेक्षाकृत हल्का, अधिक मजबूत तथा कम लागत वाला है। थ्री-डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग ने इसके निर्माण खर्च को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण का वैश्विक बाजार भारत के लिए नये आर्थिक अवसर लेकर आएगा। आज दुनिया में संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के लिए हजारों छोटे उपग्रहों की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में भारत कम लागत और उच्च विश्वसनीयता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। विक्रम-1 को विकसित करने वाली निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट का नामकरण कर न सिर्फ उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, बल्कि हमारे औद्योगिक घरानों को भी यह संदेश दिया है कि कारोबार करते हुए भी अपने देश की समृद्ध विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए।

गौर कीजिये, अप्रैल 1975 में जब भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, तब उसका नामकरण महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। यह सफलता केवल एक कंपनी की उपलब्धि नहीं है। यह उस नयी नीति का परिणाम भी है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश और स्टार्टअप के लिए खोलने का साहसिक निर्णय लिया। नयी अंतरिक्ष नीति, इन-स्पेस जैसी संस्थाओं की स्थापना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार प्रावधानों ने भारतीय युवाओं के सामने नये अवसरों के द्वार खोल दिये हैं। आज देश में अनेक स्पेस स्टार्टअप उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष संचार और डेटा सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत आधार प्रदान करेगा। किन्तु हर सफलता अपने साथ नयी चुनौतियां भी लेकर आती है।

विक्रम-1 की पहली उड़ान सफल अवश्य रही है, परंतु अंतरिक्ष उद्योग में स्थायी सफलता केवल एक प्रक्षेपण से सुनिश्चित नहीं होती। स्काईरूट एयरोस्पेस को अब वैश्विक बाजार में स्पेसएक्स, रॉकेट लैब तथा चीन की अनेक निजी कंपनियों जैसी सशक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। नियमित ग्राहक, समय पर प्रक्षेपण, कम लागत, उच्च विश्वसनीयता तथा भविष्य में पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक विकसित करना उसकी अगली बड़ी परीक्षा होगी। अंतरिक्ष उद्योग में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है और वह निरंतर सफल अभियानों से ही अर्जित किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक सफलता के बीच एक गंभीर प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा है-क्या इसरो अपनी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को लंबे समय तक अपने साथ बनाये रख पाएगा? हाल के वर्षों में अनेक अनुभवी वैज्ञानिक निजी क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए हैं। इसका कारण केवल अधिक वेतन नहीं, बल्कि बेहतर कार्य संस्कृति, अनुसंधान की स्वतंत्रता, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण भी है।

इसरो ने भारत को चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-एल1, गगनयान जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां दी हैं। सीमित संसाधनों में विश्वस्तरीय परिणाम देकर इसरो ने पूरी दुनिया का सम्मान अर्जित किया है। किंतु यदि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक धीरे-धीरे संस्थान से बाहर जाते रहे तो दीर्घकाल में अनुसंधान और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नये मिशन तैयार करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रेरित, सम्मानित और संतुष्ट बनाये रखना भी है। सरकार को चाहिए कि इसरो के वैज्ञानिकों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना, अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं, निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां विकसित करे। सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का वातावरण तैयार होना चाहिए। निजी क्षेत्र इसरो का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी बन सकता है। जिस प्रकार अमेरिका में नासा और स्पेसएक्स मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नयी ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, उसी प्रकार भारत में इसरो और निजी कंपनियों का समन्वय देश को वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि अंतरिक्ष विज्ञान को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के स्तर तक पहुंचाया जाए। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं का विषय न रहकर जन-आंदोलन बने। युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवाचारकर्ताओं को स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। यदि प्रत्येक राज्य में स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर स्थापित किये जाएं, उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान साझेदारी विकसित की जाए तथा अंतरिक्ष तकनीक में निवेश को बढ़ावा दिया जाए तो भारत अगले दशक में विश्व का अग्रणी अंतरिक्ष नवाचार केंद्र बन सकता है। भविष्य की आकाशीय सफलताओं की नयी जमीन तैयार करने के लिए कुछ रचनात्मक कदम अत्यंत आवश्यक हैं-इसरो और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ हों; पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक और हरित प्रणोदन (ग्रीन प्रोपल्शन) पर विशेष निवेश किया जाए; अंतरिक्ष विनिर्माण के लिए स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाए; युवाओं के लिए अंतरिक्ष उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले विशेष कोष बनाए जाएं; तथा अंतरिक्ष कानूनों को सरल, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल बनाया जाए। साथ ही, अंतरिक्ष मलबे (स्पेस डेब्रिस) के प्रबंधन, पर्यावरणीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि भविष्य का अंतरिक्ष विकास केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का भी विषय है।

विक्रम-1 ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब केवल अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र बन चुका है। यह सफलता नये भारत के आत्मविश्वास, युवाओं की प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच की विजय है। यह उस राष्ट्र की कहानी है जिसने कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ढोए थे और आज निजी क्षेत्र के माध्यम से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वास्तव में, विक्रम-1 केवल एक रॉकेट नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास का उड़ता हुआ प्रतीक है। यह सफलता हमें यह संदेश देती है कि यदि नीति, प्रतिभा, उद्योग और राष्ट्रीय संकल्प एक दिशा में आगे बढ़ें तो असंभव भी संभव बन जाता है। निजी क्षेत्र की यह सफलता विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले भारतीयों के लिए एक आह्वान है-अंतरिक्ष सेनानिया करो प्रयाण, सारा आकाश तुम्हारा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को एक शुरुआत मानते हुए भारत अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की ऐसी मजबूत नींव तैयार करे, जहां इसरो की गौरवशाली परंपरा और निजी क्षेत्र की नयी ऊर्जा मिलकर विश्व को नयी दिशा दें। तभी सच अर्थों में यह कहा जा सकेगा कि अब केवल धरती ही नहीं, बल्कि पूरा आकाश भी भारत की नयी विकास-गाथा का विस्तार बन चुका है।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा : क्या अधर में रहेगा

पूनम आई कौशिश

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होते ही विरोध-प्रदर्शनों का दौर भी तेज हो गया और देशभर का राजनीतिक ध्यान संसद की ओर केंद्रित हो गया। इस शोर-शराबे के बीच एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा अपेक्षाकृत दब गया। जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नैकां) ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराते हुए मोदी सरकार से संसद और सर्वोच्च न्यायालय में किये गये अपने वादे को निभाने की अपेक्षा जताई। विशेष रूप से वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद 2024 में शांतिपूर्ण ढंग से हुए विधानसभा चुनावों ने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार आतंकवादी घटनाओं में कमी और पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि को नया कश्मीर में सामान्य स्थिति लौटने का प्रमाण बताती रही है।

ऐसे में राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी को लेकर नैशनल कॉन्फ्रेंस की निराशा बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि भाजपा हमें यह बता दे कि राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए क्या हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना होगा और व्हाइट हाऊस के बाहर धरना देना होगा? यदि वास्तव में कश्मीर आज पूर्ण लोकतांत्रिक स्वशासन के लिए पर्याप्त रूप से सामान्य हो चुका है, तो फिर राज्य का दर्जा बहाल करने में बाधा क्या है? आखिर ऐसा कौन-सा मानदंड है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? संक्षेप में कहें तो सबसे बड़ी बाधा संवैधानिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक है। केंद्र सरकार बार-बार यही कहती रही है कि जम्मू-कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। असली विवाद इस बात को लेकर है कि वह उचित समय कब आएगा और किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया जाएगा?

केंद्र की हिचकिचाहट का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। सरकार का मानना है कि यद्यपि सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है लेकिन यह सुधार अभी पूरी तरह स्थायी नहीं माना जा सकता। आखिरकार जम्मू-कश्मीर दशकों तक आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के घाव अभी भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। इस मुद्दे का एक राजनीतिक पहलू भी है। केंद्र शासित प्रदेश बने रहने से केंद्र सरकार का प्रशासनिक प्रभाव कहीं अधिक बना रहता है। इसके अलावा, उपराज्यपाल (एल.जी.) के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण रहने से सुरक्षा संबंधी निर्णय तेजी से लिए जा सकते हैं तथा सेना, अर्द्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।

दरअसल, सवाल यह भी है कि जब मौजूदा व्यवस्था स्थिरता बनाये रखने और अलगाववादी राजनीति पर नियंत्रण रखने में केंद्र की मदद कर रही है, तो वह अपने अधिकार क्यों छोड़े? भाजपा के लिए फिलहाल प्रशासनिक नियंत्रण का महत्व, राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रतीकात्मक महत्व से कहीं अधिक है। राज्य का दर्जा बहाल होने का अर्थ होगा कि निर्वाचित सरकार के साथ सत्ता सांझी करनी पड़ेगी, जो शासन, कानून-व्यवस्था और कश्मीर से जुड़े राजनीतिक विमर्श जैसे मुद्दों पर दिल्ली से अलग राय रख सकती है। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे को टालने की कोई स्पष्ट चुनावी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ती नहीं दिख रही। जम्मू-कश्मीर के बाहर पार्टी के अधिकांश समर्थकों के लिए अनुच्छेद 370 का निरसन ही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, राज्य का दर्जा कब बहाल होगा, यह नहीं। इसके विपरीत, यदि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद निर्वाचित सरकार नयी दिल्ली की मुखर आलोचक बन जाती है अथवा सुरक्षा स्थिति फिर से बिगड़ती है, तो उसके राजनीतिक दुष्परिणाम भाजपा और केंद्र सरकार दोनों को भुगतने पड़ सकते हैं।

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार के लिए राज्य का दर्जा केवल प्रतीकात्मक महत्व का विषय नहीं है। यह इस मूल प्रश्न से जुड़ा है कि राजनीतिक शक्ति, वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक नियंत्रण का अंतिम अधिकार किसके पास होगा? वर्तमान व्यवस्था में वास्तविक अधिकार अभी भी नयी दिल्ली के हाथों में केंद्रित है। कानून-व्यवस्था, पुलिस तथा लोक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में हैं। कश्मीरी नेताओं का तर्क है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह तो हैं लेकिन उनके पास वे अधिकार नहीं हैं जो सामान्यतः किसी राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नैशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल कराने के मुद्दे को प्रमुख चुनावी वादा बनाया था। यदि वह इस वादे को पूरा नहीं कर पाती, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) उसे केंद्र सरकार की कठपुतली और शक्तिहीन सरकार बताकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेगी। उमर अब्दुल्ला सरकार की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक यह भी है कि नौकरशाही निर्वाचित मंत्रियों की अपेक्षा उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति अधिक जवाबदेह महसूस करती है। राज्य का दर्जा बहाल होने पर प्रशासनिक तंत्र पर मंत्रिपरिषद की पकड़ कहीं अधिक मजबूत होगी।

इस पूरे विवाद के केंद्र में दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास भी मौजूद है। कांग्रेस हो या भाजपा, लगभग सभी केंद्रीय सरकारों ने समय-समय पर कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना और उस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देने के आरोप लगाये। वहीं कश्मीरी राजनीतिक दलों का आरोप रहा है कि नयी दिल्ली ने निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने, राज्यपाल शासन लगाने और राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को बार-बार कमजोर किया है। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि केंद्र सरकार लगातार यह दावा करती है कि जम्मू-कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं, आतंकवाद में कमी आयी है, निवेश बढ़ रहा है, आधारभूत संरचना का तेजी से विकास हो रहा है और राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण की प्रक्रिया सफल रही है, तो फिर राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार विलंब उसके अपने ही दावों से मेल नहीं खाता।

स्पष्ट है कि उचित समय अब एक ऐसी राजनीतिक प्रतिबद्धता बन चुका है, जिसकी कोई निश्चित समय-सीमा या पारदर्शी एवं मापनीय कसौटी निर्धारित नहीं है। राज्य का दर्जा कब बहाल होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि शेष सुरक्षा जोखिमों और पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों के बीच किसे अधिक महत्व दिया जाता है? ऐसे में सभी पक्षों को राजनीतिक सुविधा की बजाय सुरक्षा, सुशासन और संस्थागत स्थिरता जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित एक स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रोडमैप तैयार करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

एआई व डाटा सेंटर पर बरस रहा पैसा, इंसानों के लिए घट रहे अवसर

शंकर अय्यर

दुनिया अब तेजी से बंटी हुई स्क्रीन पर दिखायी दे रही है। एक तरफ एआई, डाटा सेंटर, मार्केट वैल्यूएशन और कैपिटल में निवेश की भारी बढ़ोतरी दिख रही है, तो दूसरी तरफ यह पता चलता है कि जॉन एफ कैनेडी के जमाने में जिन्हें मूनशॉट कहा जाता था, वे कैसे भारत व दुनियाभर में तकनीकी कंपनियों द्वारा इंजीनियरों की भर्ती कम कर रहे हैं। दरअसल, पिछले हफ्ते चीनी स्टार्टअप मूनशॉट एआई ने एक नया मॉडल (किमि के3) पेश किया, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। के3 के लांच को एआई इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि यह अमेरिकी दिग्गज कंपनियों के बराबर नतीजे बहुत कम लागत में देने का वादा करता है। मूनशॉट इस दौड़ का अकेला खिलाड़ी नहीं है। कई और कंपनियां भी हैं। ऐसे में, अगर बेहद कम लागत पर उच्च स्तर की एआई क्षमता उपलब्ध होने लगे, तो मौजूदा कारोबारी मॉडल तेजी से अप्रासंगिक हो सकते हैं। भारत की तस्वीर फिलहाल दो हिस्सों में बंटी हुई दिखायी देती है। एक ओर आईटी कंपनियां डाटा सेंटर, एजेंटिक एआई, बढ़ते निवेश और बेहतर वित्तीय नतीजों की खबरों से उत्साह पैदा कर रही हैं। दूसरी ओर, एक शांत, लेकिन चिंताजनक स्थिति भी है, जहां कर्मचारियों की संख्या घट रही है और नयी भर्तियां दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी हैं। ये खबरें कमाई और रोजगार के बीच एक खामोश अलगाव की ओर इशारा करती हैं। अगर पहली तस्वीर को ध्यान से देखें, तो कंपनियों की निवेशक बैठकों और विश्लेषकों के बीच सबसे अधिक चर्चा सिर्फ दो अक्षरों (ए और आई) की रही। टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों ने मजबूत ऑर्डर बुक और बढ़ती आय का दावा तो किया, लेकिन इस उत्साह के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। कंपनियों की आय रुपये में जरूर दो अंकों की दर से बढ़ी, कुछ मामलों में 14 प्रतिशत से भी ज्यादा, पर असलियत यह है कि आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां डॉलर में कमाई करती हैं। इसलिए, रुपये के कमजोर होने से यह वृद्धि ज्यादा दिखायी दी। अगर रुपये और डॉलर के बीच कीमत में आये इस बदलाव के असर को हटा दें, तो डॉलर के हिसाब से कमाई में बहुत कम बढ़ोतरी हुई, जो लगभग एक से छह प्रतिशत के बीच ही रही। वहीं, कर्मचारियों की संख्या पर नजर डालें, तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। टीसीएस ने इस तिमाही में लगभग 9,000 कर्मचारी जोड़े हैं। लेकिन, असल बात यह है कि कुल कर्मचारियों की संख्या 5.93 लाख है, जो एक साल पहले के 6.13 लाख के आंकड़े से कम है। विप्रो ने भी घोषणा की है कि वह इस साल नये इंजीनियरिंग स्नातकों को नौकरी पर नहीं रखेगी। टेक महिंद्रा में कर्मचारियों की संख्या 1.46 लाख है, जो एक साल पहले के मुकाबले कम है। एचसीएल टेक में भी एक वर्ष में करीब 3,200 कर्मचारियों की कमी आई है। यदि राजस्व वृद्धि और कर्मचारियों की वृद्धि को एकसाथ देखा जाए, तो एक तरह का आर्बिट्राज इंडेक्स बनता है, जो बताता है कि कमाई बढ़ रही है, लेकिन रोजगार नहीं। यह स्पष्ट है कि भारत की आईटी कंपनियां टिके रहने की होड़ में हैं और वे खुलकर दांव लगा रही हैं। निवेश अब लोगों के बजाय एआई पर हो रहा है। कभी सस्ती और बड़ी कार्यशक्ति भारत की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी ताकत थी, पर अब विकास के लिए उसकी जरूरत पहले जैसी नहीं रही। अब नयी और क्रांतिकारी तकनीकों के आने से वह मॉडल बदल रहा है। नौकरियों की मांग व पूर्ति से पता चलता है कि भर्ती में कमी आयी है। कॉलेज प्लेसमेंट पहले ही कमजोर पड़ चुके थे, अब अनुभवी पेशेवरों के लिए भी अवसर तेजी से घट रहे हैं। यानी, कॅरिअर की शुरुआत से लेकर ऊंचे पदों तक, हर स्तर पर रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं। जून 2026 की चैलेंजर रिपोर्ट, जो भर्ती के रुझान पर नजर रखती है, बताती है कि उस महीने में एआई से जुड़ी 14,000 से ज्यादा नौकरियों में कटौती की घोषणा की गयी थी। इस वर्ष अब तक 1,01,743 नौकरियों में कटौती के पीछे एआई को वजह बताया गया है, जो कुल घोषित छंटनी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। किसी बात को समझने के लिए संदर्भ बहुत जरूरी है। यह बदलाव केवल अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं है। वैश्विक कंपनियों में होने वाला ऑटोमेशन सीधे भारत के रोजगार पर असर डालता है। न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में कोई कंपनी एआई अपनाती है, तो उसका असर भारत में कर्मचारियों की छंटनी के रूप में दिख सकता है, क्योंकि मशीनें अब तेजी से इन्सानी काम अपने हाथ में ले रही हैं। एआई का असर कंपनियों के दावों में भी दिखायी देता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि एआई 30 प्रतिशत कोड लिख रहा है। ओरेकल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि एआई की वजह से 21,000 नौकरियां कम हो गईं। सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनिऑफ ने बताया कि एआई एजेंटफोर्स अब कंपनी की लगभग आधी सर्विस कॉल संभाल रहा है और इसके बाद 4,000 से अधिक पद समाप्त किये गये। जब एआई नया कोड लिखने लगे, तो बिल योग्य घंटे और लागत, दोनों घटते हैं, जिससे ऑटोमेशन की रफ्तार और तेज हो जाती है। यह बदलाव केवल आईटी उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा बदल रहा है। आईटी सेवाएं भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र हैं और मध्यम वर्ग के लिए रोजगार का प्रमुख आधार भी। लेकिन, जिस लागत-आधारित प्रतिस्पर्धी मॉडल ने भारतीय मध्यम वर्ग को मजबूत बनाया, उसकी कीमत अब हर तिमाही नये सिरे से तय हो रही है। सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के नये मॉडल तैयार करने की है। यह स्प्लिट स्क्रीन (दो हिस्सों वाली स्थिति) हमेशा नहीं रहेगी। एआई क्रांति के असल आर्थिक नतीजे साफ दिखने लगेंगे और उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

मांस-मछली की दुकानें शहर से बाहर करने की मांग

वाराणसी , एजेंसी। श्रीआदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास के सदस्यों ने मंगलवार दोपहर सीएम को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें श्रावण मास और कांवर यात्रा से पहले वाराणसी शहर से मांस-मछली की दुकानों को बाहर करने की मांग की गई है। न्यास ने महापौर और नगर आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में न्यास के कार्यकारिणी अध्यक्ष आरके अग्रवाल, बांकेलाल, संजीव चंद त्रिपाठी, अनुराग त्रिवेदी, अजय शास्त्री, डॉ राम प्रसाद सिंह शामिल रहे।

एलोपैथी की तर्ज पर हो आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथी चिकित्सा फार्मेसी की शिक्षा

वाराणसी, एजेंसी। आईएमएस बीएचयू के आयुर्वेद संकाय के धनवंतरि भवन के समिति कक्ष में हुए कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बनाए गए राष्ट्रीय भेषजीय आयोग अधिनियम 2026(नेशनल फार्मेसी कमीशन अधिनियम) पर चर्चा हुई। इस दौरान वक्ताओं ने एलोपैथी की तर्ज पर ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में फार्मेसी की शिक्षा की बात कही ।कमीशन की ओर से बनाए गए फार्मेसी नियमावली पर आयुर्वेद संकाय के रसशास्त्र विभाग के प्रो. आनंद चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस नियमावली के संदर्भ में संबंधित सभी प्रभावित पक्षों से 28 जुलाई तक सुझाव मांगा है। सरकार ने इस अधिनियम से भारत में औषधियों के निर्माण में तकनीकी सुदृढ़ता सहित सुधार लाने के लिए सभी चिकित्सा पद्धतियों(आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी) के लिए नए नियम कानून बनाए हैं। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात सभी चिकित्सा पद्धतियों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ऑनलाइन बैठक में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा से डॉ. शिल्पा पाटिल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानित विवि जयपुर से डॉ राकेश सिंह, बीएचयू से डॉ. गुरु प्रसाद नीले साथ ही डॉ. कनिका,डॉ. गायत्री, डॉ. शिवम, अपर्णा, अंजू आदि ने सहभागिता की।

बीएचयू में कटऑफ से ज्यादा स्कोर के बावजूद दाखिला नहीं

वाराणसी , एजेंसी। बीएचयू ने पीजी स्पॉट राउंड की मेरिट में कटऑफ से ज्यादा अंक पाने पर भी दाखिले के लिए बुलावा नहीं आया। इस तरह के कई मामले आने के बाद केंद्रीय प्रवेश समिति ने बताया है कि स्पॉट और नियमित राउंड की संयुक्त मेरिट और सीट कैंसिल होने पर ऐसी स्थिति बन जा रही है। इससे कटऑफ बदल जाता है। यदि 37 अंक वाले ने दाखिला कैंसिल करा लिया तो फिर कटऑफ 41 अंक पर भी जा सकता है। सीएसी के अध्यक्ष प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने एडमिशन पोर्टल पर सूचना जारी कर बताया है कि नियमित राउंड से प्रवेश ले चुके छात्रों और स्पॉट राउंड के आवेदकों को एक साथ क्रम से रखा जाता है। इसकी संयुक्त रैंकिंग निकाली जाती है। यही अंतिम आवंटन और कटऑफ निर्धारित करता है। यदि किसी एक कोर्स में किसी श्रेणी में 10 सीटें हैं। एक दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि यदि नियमित राउंड से प्रवेश लेने वाला कोई छात्र अपनी सीट वापस ले लेता है, तो कटऑफ बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि 37 अंक वाला छात्र अपनी सीट वापस ले लेता है, तो कटऑफ 42 हो सकता है और 55 अंक वाले छात्र को प्रवेश मिल सकता है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इसमें अपग्रेडेशन और फ्रीज के मामलों पर विचार नहीं किया गया है, जिन्हें शामिल करने पर कुछ अलग तरह के मामले सामने आ सकते हैं।

भोपुरा और इंद्रप्रस्थ में 10 घंटे बिजली गुल, 60 हजार लोग परेशान

गाजियाबाद , एजेंसी। टीएचए में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। सोमवार रात 33 केवी बिजली लाइन में फॉल्ट होने से भोपुरा क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी, पंचशील कॉलोनी, कृष्णा विहार कॉलोनी और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी समेत कई इलाकों में करीब 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। लंबे बिजली संकट के कारण करीब 60 हजार लोगों को दिक्कत हुई। बिजली नहीं होने से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही और लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा। डिफेंस कॉलोनी निवासी सोनू प्रजापति ने बताया कि सोमवार रात करीब एक बजे 33 केवी लाइन में फॉल्ट आने से भोपुरा की तीन कॉलोनी की बिजली गुल हो गई। पूरी रात और सुबह तक लोग बिजली आने का इंतजार करते रहे। सुबह आठ बजे तक उपभोक्ता लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों और कंट्रोल रूम में फोन कर आपूर्ति बहाल करने की जानकारी लेते रहे, लेकिन फॉल्ट दूर होने में काफी समय लग गया। बिजली नहीं होने के कारण लोग पानी की मोटर नहीं चला सके। वहीं, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी सतीश भारद्वाज ने बताया कि लगातार फॉल्ट की समस्या बनी हुई। सोमवार रात भी करीब दो बजे इलाके में फॉल्ट की वजह से बिजली गुल हो गई। लोग ऊर्जा निगम से फॉल्ट की जल्द मरम्मत करने मांग करते रहे। मंगलवार सुबह करीब दस बजे बिजली आपूर्ति सामान्य हुई।

पटना विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर संग्राम

नए विश्वविद्यालय विधेयक के विरोध में उतरे शिक्षक और छात्र

पटना, एजेंसी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के साथ ही उच्च शिक्षा से जुड़ा एक प्रस्तावित विधेयक राज्य की राजनीति और शैक्षणिक जगत का बड़ा मुद्दा बन गया है. बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में करीब पांच दशक बाद व्यापक बदलाव की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित विधेयक की ड्राफ्टिंग पूरी होने की जानकारी के बीच पटना विश्वविद्यालय में इसका विरोध तेज हो गया है। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र संगठन दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बचाने के लिए एक मंच पर आ गए हैं।

सामूहिक अवकाश को लेकर विरोध: प्रस्तावित विधेयक के विरोध में मंगलवार को पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहे और हड़ताल की। पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से आयोजित विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल हुए। शिक्षक संघ ने फैसला लिया है कि विधानसभा के शेष तीन कार्य दिवसों के दौरान भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यदि सरकार विधेयक को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को सड़क तक ले जाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी।

क्या है सरकार की तैयारी?: जानकारी के अनुसार राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के संचालन से जुड़े अलग-अलग अधिनियमों को समाप्त कर एक समान कानून लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही स्नातक शिक्षा को विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से अलग कर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन लाने पर भी विचार किया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना बताया जा रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर विधेयक सदन में पेश नहीं किया गया है, लेकिन इसकी संभावित रूपरेखा सामने आने के बाद विरोध शुरू हो गया है।

'पटना विश्वविद्यालय की अलग पहचान है': पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो। शिव सागर प्रसाद ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 अन्य विश्वविद्यालयों के कानून से पूरी तरह अलग है। उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि इसके अपने अंगीभूत कॉलेज हैं और इसकी प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था भी अलग है।

स्थानांतरण और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी चिंता: प्रो। शिव सागर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के अपने कॉलेजों तक सीमित रहता है। यदि सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान कानून लागू हुआ तो शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य के किसी भी कॉलेज में किया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्नातक स्तर की शिक्षा और विश्वविद्यालय प्रशासन को अलग करने की तैयारी भी चल रही है, जिसका शिक्षक संघ विरोध करेगा। उनका कहना है कि जब तक सरकार विधेयक वापस लेने की घोषणा नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 'शोध और स्वायत्तता प्रभावित होगी': पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो। सुहेली मेहता ने कहा कि सरकार सभी विश्वविद्यालयों को एक ही नियम के तहत लाने की तैयारी कर रही है लेकिन पटना विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक और शैक्षणिक पहचान अलग है।

छात्र संघ भी आंदोलन में शामिलः पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर ने कहा कि विश्वविद्यालय का पूरा परिवार इस मुद्दे पर एकजुट है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े छात्र हों या शिक्षक और कर्मचारी, सभी का उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और गरिमा को सुरक्षित रखना है। किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विधानसभा से सड़क तक आंदोलन की चेतावनीः विरोध कर रहे शिक्षक और छात्र संगठनों का कहना है कि यदि सरकार विधानसभा में यह विधेयक पारित कराती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल विरोध शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है लेकिन जरूरत पड़ने पर सड़क और विधानसभा के बाहर भी व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित विश्वविद्यालय विधेयक केवल विधायी मुद्दा नहीं, बल्कि राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ी बहस का विषय बन गया है।

लखनऊ मेट्रो ने लॉन्च किया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड

लखनऊ, एजेंसी। मेट्रो यात्रियों का सफर अब और भी स्मार्ट होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सेवा की शुरुआत की है। एक देश एक कार्ड की संकल्पना पर आधारित इस कार्ड से हर यात्रा पर किराये में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसे कानपुर, आगरा मेट्रो के अलावा देश के अन्य मेट्रो की यात्रा में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

मंगलवार को यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने इस सुविधा का शुभारंभ किया। बताया कि एनसीएमसी किसी भी मेट्रो स्टेशन पर बनवाया जा सकता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह एक इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है। इसका इस्तेमाल मेट्रो के अलावा उन बस, पार्किंग और रिटेल सेवाओं में भी किया जा सकता है जहां एनसीएमसी को अपनाया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि फिलहाल पहले से चल रहे गो स्मार्ट कार्ड और नए एनसीएमसी, दोनों के माध्यम से यात्रा की जा सकती है। यात्रियों को सलाह दी कि वे अपने पुराने गो स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर लें। यूपीएमआरसी शीघ्र ही एक विशेष एक्सचेंज विंडो शुरू करेगा जिसके माध्यम से यात्री 30 दिन के अंदर अपने गो स्मार्ट कार्ड को एनसीएमसी में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदलवा सकेंगे।

एलटी लाइन में लगी आग, 105 गांवों की बिजली दो घंटे तक ठप

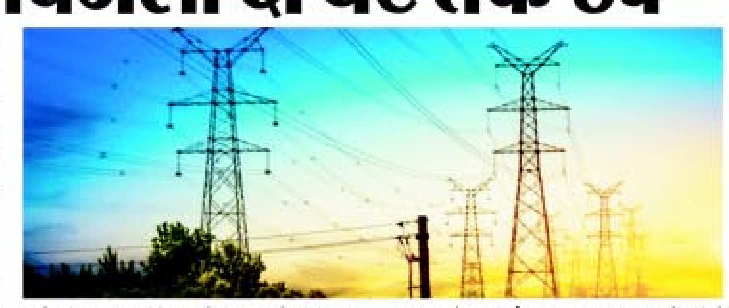

लखनऊ, एजेंसी। लेसा के अमौसी जोन के अंतर्गत समेसी उपकेंद्र से पोषित समेसी टाउन व मीरखनगर टाउन फीडर की बिजली आपूर्ति मंगलवार को करीब दो घंटे बाधित रही। शाम चार बजे कासिमपुर गांव की एलटी लाइन में आग लगने की सूचना मिलने पर मीरखनगर टाउन फीडर बंद किया गया। जिससे 60 गांवों की बिजली ठप हो गई। दूसरी ओर दोपहर करीब 3:30 बजे समेसी टाउन फीडर ब्रेकडाउन में चला गया। इससे 45 गांवों की बिजली बंद हो गई। दोनों ही इलाकों के 10 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।

समेसी फीडर के प्रभावित गांवों में भवानीखेड़ा, शंकरपुर, गणेशखेड़ा, समेसी बाजार, छेदाखेड़ा, पटवाखेड़ा, भोरा कला, अचलीखेड़ा, मितौली प्रमुख रहे। इसी प्रकार मीरखनगर फीडर इलाके में प्रमुख रूप से रामदासपुर, कासिमपुर, नंदौली, कुबहरा, पतौना आदि गांवों की बिजली गुल रही। इलाके अवर अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि समेसी टाउन फीडर में आए ब्रेकडाउन और कासिमपुर की एलटी लाइन के फॉल्ट को दुरुस्त करने के बाद लगभग दो घंटे में दोनों फीडरों की बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी गई।

बारिश में तारों पर गिरा पेड़, पांच घंटे रहा बिजली संकट : दुबग्गा में काकोरी के हरदोई रोड स्थित एक निजी अस्पताल के पास मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे 33 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। वहीं, फॉल्ट के चलते दुर्गागंज, शाहपुर फीडर की सप्लाई बंद हो गई। एफसीआई उपकेंद्र के रहमानखेड़ा और बसंतकुंज उपकेंद्र के लालाबाग फीडर से जुड़े एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं को करीब पांच घंटे तक बिजली संकट का सामना करना पड़ा।

दुर्गागंज फीडर की आपूर्ति चार घंटे से अधिक समय तक बंद रही। उपभोक्ता राघवेंद्र उर्फ मोनू मौर्य, विष्णु, राकेश और कल्लू ने बताया कि हल्की बारिश में भी क्षेत्र की बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है। विभाग यदि समय रहते जर्जर तारों और उपकरणों की मरम्मत करा दे तो उपभोक्ताओं को बार-बार परेशानी न झेलनी पड़े।

खतरनाक थे आतंकी शहरोज के मंसूबे, सीमा पर स्लीपर सेल खड़ा करने की थी तैयारी, अब सामने आएंगे राज

लखनऊ, एजेंसी। आईएसआई और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के इशारे पर बलरामपुर का शहरोज मुंबई में आतंकी हमला करने की फिराक में था। इसके लिए उसने मुंबई में करीबियों को जोड़कर नेटवर्क बना लिया था। इन सभी का मकसद आईएसआई के इशारे पर हिंदूवादी नेताओं और संगठनों को निशाना बनाना था। इसके जरिये आईएसआई मुंबई में सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश बुन रहा था।

यूपी एटीएस द्वारा शहरोज की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं, हालांकि गहनता से जांच के लिए उसे रिमांड पर लेने की कवायद की जाएगी। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई एजेंट जसवीर चौधरी ने उसे राजस्थान के श्रीगंगानगर जाने को कहा था, जहां हथियार और विस्फोटक ड्रोन के जरिये सीमार पार से आने थे। शहरोज हथियार और विस्फोटक लेकर वापस मुंबई जाने वाला था, जहां उसे जल्द टारगेट के बारे में बताने को कहा गया था। एटीएस उसके मोबाइल से मिले संपर्कों के जरिये नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ रही है।

सीमा पर स्लीपर सेल खड़ा करने की थी तैयारी : प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियों का मानना है कि शहरोज को फिलहाल नेटवर्क के ट्रायल (परीक्षण) चरण में रखा गया था। इस दौरान उसकी गतिविधियों, गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता और निर्देशों के पालन का आकलन किया जा रहा था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, यदि वह इस चरण में सफल रहता तो उसे भारत-नेपाल सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में कथित तौर पर स्लीपर सेल खड़ा करने और स्थानीय युवाओं को नेटवर्क से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। इससे पहले ही एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एटीएस यह भी पता लगा रही है कि उसने किन-किन लोगों से संपर्क किया, किसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की और क्या किसी स्थानीय व्यक्ति को नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया था।

फंडिंग की भी होगी जांच : एटीएस की जांच का सबसे अहम आधार शहरोज से बरामद मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण हैं। इनका फोरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया अकाउंट, चैट, कॉल डिटेल, फोटो, वीडियो, दस्तावेज, बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड तथा विदेशी नंबरों से संपर्क की कड़ियों की पड़ताल कर रही हैं।

एटीएस यह भी पता लगा रही है कि क्या उसे किसी विदेशी स्रोत से आर्थिक सहायता मिली थी। एजेंसियां पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसके आवागमन का ब्योरा भी खंगाल रही हैं। वह लंबे समय तक मुंबई में रहा, बीच-बीच में बलरामपुर आता-जाता रहा और हाल के महीनों में भी लगातार यात्रा कर रहा था।

एक और नए हाईवे की सौगात

आगरा, एजेंसी। आगरा के टेढ़ी बगिया से नूंहखास, एटा तक 51.600 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-321जी) के निर्माण का रास्ता मंगलवार को साफ हो गया। 685.51 करोड़ रुपये की लागत वाले इस टू-लेन प्रोजेक्ट की तकनीकी निविदा 16 जुलाई को खुल चुकी है। टीटीजेड क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से पेड़ काटने की अनुमति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल भी लगातार शासन से पत्राचार कर रहे थे। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व में 19 मार्च 2024 को इसकी वित्तीय निविदा खोली गई थी, जिसे सड़क परिवहन मंत्रालय ने 7 अगस्त 2025 को निरस्त कर दिया था। इसके बाद 26 फरवरी 2026 को नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। फिलहाल प्रोजेक्ट की भौतिक प्रगति शून्य है। प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भोपाल की एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है।

परियोजना में देरी का मुख्य कारण वन विभाग की अनापत्ति (क्लीयरेंस) न मिलना और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला था। संरक्षित वन क्षेत्र के लिए 24 अगस्त 2023 को ही स्टेज-1 की मंजूरी मिल चुकी थी। 27 मई 2026 को हुई पिछली सुनवाई में कोई फैसला नहीं हो सका था। मंगलवार को टीटीजेड क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यहाँ से अनुमति मिलने के बाद, अब वन विभाग में स्टेज-2 की क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया जाएगा।

हाइवे पर बैठे किसान, नौ घंटे तक नारेबाजी...जाम और खींचतान

कौशांबी , एजेंसी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध कर रहे किसानों और यूपी पुलिस के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 9 पर मंगलवार को तीखी झड़प और खींचतान हुई। किसानों ने हाइवे पर बैठकर नारेबाजी की। उधर, बैरिकेडिंग हटाते हुए किसानों ने दिल्ली जाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने 70 किसानों को हिरासत में लेकर इंदिरापुरम व कौशांबी थाना और गाजियाबाद पुलिस लाइन में रखा गया। सुबह करीब 9:30 बजे से यूपी गेट पर किसानों के आने का सिलसिला शाम 5 बजे तक चलता रहा। दोपहर में एक किसान संगठन को खदेड़ते हुए कौशांबी थाने और पुलिस लाइन भिजवाया।

करीब नौ घंटे तक चले हंगामे के कारण एनएच नौ पर वाहन रेंगते रहे और जाम से राहगीरों को जूझना पड़ा। देर शाम हालात सामान्य हुए तब यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (यूएस ट्रेड डील) के विरोध में देश बचाओ मोर्चा और किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने 21 जुलाई को दिल्ली में महापंचायत करने का ऐलान किया था। उनके साथ-साथ 50 से अधिक किसान संगठनों ने महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया था। सोमवार को किसानों की घोषणा के बाद से ही यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर थी। देर रात से ही यूपी-दिल्ली के सभी बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई।

वहीं, मंगलवार सुबह कौशांबी स्थित यूपी गेट बॉर्डर, साहिबाबाद के सीमापुरी बॉर्डर, शालीमार गार्डन स्थित अप्सरा बॉर्डर आदि को बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया। यूपी गेट पर सुबह 6 बजे से एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के नेतृत्व में पांच थानों और 12 से अधिक चौकियों से एसआई और कांस्टेबल के अलावा डेढ़ प्लाटून पीएसी तैनात की गई थी। सुबह 9:30 बजे के करीब 35-40 किसानों का पहला समूह यूपी गेट पहुंचा। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो खूब झड़प हुई। गुस्साए किसान हाइवे पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस पर पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इंदिरापुरम थाने भेज दिया। इसके बाद लगातार किसान संगठनों की आवाजाही लगी रही। दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचे किसानों ने बैरिकेडिंग हटाकर दिल्ली की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की और खींचतान भी हुई। पुलिस ने सभी को खदेड़ते हुए कौशांबी थाने और पुलिस लाइन भिजवाया। दिल्ली में आंदोलन बंद न होने तक किसानों को पुलिस हिरासत में ही रखा गया।

जाम से जूझे राहगीर, एंबुलेंस और स्कूल बस भी फंसी : यूपी गेट पर किसानों के प्रदर्शन व पुलिस झड़प की वजह से जाम के हालात पैदा हो गए। स्थिति यह हो गई कि सुबह से ही वाहनों की रफ्तार एनएच पर थमती चली गई। दोपहर तक कुछ-कुछ देरी पर वाहनों की लंबी कतार लगना शुरू हो गई। एक तरफ यूपी पुलिस की बैरिकेडिंग और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की सख्ती के चलते वाहन रेंगते रहे। इस दौरान जाम में एंबुलेंस और स्कूल बसें भी फंसी रहीं। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करते हुए चेकिंग की जा रही थी। किसानों को समझाकर शांत कराया गया। उन्हें थाने में बिठाया गया था। मौके पर पुलिस फोर्स और यातायात कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की गई थी। हंगामा शांत होने के बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया गया।

कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

जम्मू, 22 जुलाई (भा)। जम्मू क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में लगातार चौथे दिन हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात आज रोक दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित पुंछ और राजौरी जिलों में लापता सात लोगों की तलाश का अभियान जारी रहा। वहीं, अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा और मचैल माता यात्रा समेत सभी प्रमुख तीर्थ यात्राएं रविवार से निलंबित हैं। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 250 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही सुबह 9.30 बजे रोक दी गयी। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण उधमपुर और बनिहाल के बीच करीब एक दर्जन स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर खिसकने की घटनाएं हुईं। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि मौसम में सुधार होने और सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित घोषित किये जाने तक राजमार्ग पर यात्रा न करें। उन्होंने बताया कि मलबा हटाने के लिए सड़क साफ करने वाली एजेंसियों ने अपने कर्मियों को तैनात कर दिया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार आज सुबह 8.30 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों के दौरान कठुआ जिले में सबसे अधिक 153 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गयी। इसके बाद सांबा में 133 मिमी, उधमपुर में 112.6 मिमी, जम्मू में 62.1 मिमी, कटरा में 58.5 मिमी, पुंछ में 51 मिमी और राजौरी में 40.5 मिमी बारिश दर्ज की गयी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार शाम तक मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार से पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में अचानक आयी बाढ़ और भूस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गयी है, जबकि सात अन्य लापता हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा है। कई सड़कें और पुल बह गये हैं तथा कई इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

लोस में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और एनसीपीआई सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भा)। लोकसभा की कार्यवाही आजे हंगामे के कारण स्थगित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी और उनके धुर्व पार्टी सहयोगी तथा नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के कुछ सांसदों के बीच सदन में तीखी नोकझोंक हुई। इस नोकझोंक में एनसीपीआई नेता मिताली बाग, शताब्दी राय और काकोली घोष दस्तीदार शामिल थीं। कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दोनों पक्षों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ।विपक्ष के कुछ सांसदों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। कुछ विपक्षी सांसदों द्वारा घटना के बारे में पूछे जाने पर कल्याण बनर्जी सदन से बाहर चले गए।इसके बाद मिताली बाग, काकोली घोष दस्तीदार और एनसीपीआई के कुछ अन्य सांसद इस मामले को उठाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में पहुंचे। सूत्रों के अनुसार बिरला ने एनसीपीआई के सांसदों से इस संबंध में लिखित शिकायत देने को कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के 20 सांसदों ने नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। वे लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसदों से अलग बैठ रहे हैं। एनसीपीआई के सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी अपना समर्थन जताया है।

10वीं अनुसूची की व्याख्या संबंधी सिब्बल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भा)। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दसवीं अनुसूची की व्याख्या पर पुनर्विचार का अनुरोध करने संबंधी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की याचिका को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर आज सहमति जतायी। दसवीं अनुसूची के तहत विधायक और सांसद किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय का दावा करके दल-बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराये जाने से बच सकते हैं। निर्दलीय राज्यसभा सदस्य सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ से कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत क्षमता से याचिका दायर की है और इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मैंने स्वयं याचिका दायर की है। यह इस सवाल से जुड़ी है कि क्या संसद की संरचना उस तरीके से बदल सकती है, जैसा इस देश में हो रहा है और

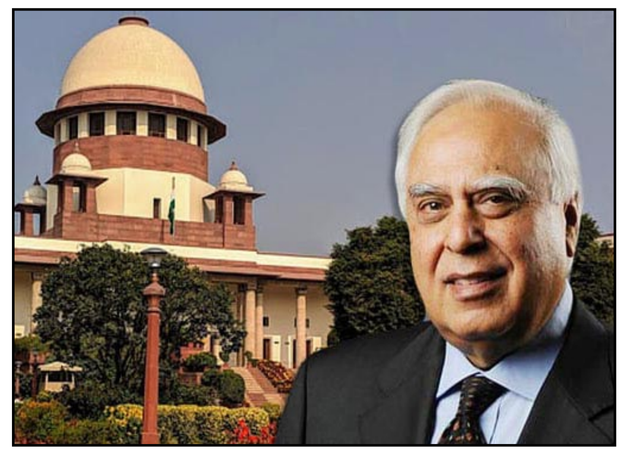

इस संदर्भ में दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद चार की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह की अन्य याचिकाएं भी उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। प्रधान न्यायाधीश ने दलीलों पर गौर करते हुए सिब्बल की याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जतायी। यह याचिका ऐसे समय दायर की गयी है, जब आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कुछ सांसदों ने दसवीं अनुसूची के तहत विलय के प्रावधानों का हवाला देते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का दामन थामा है।

शुभेंदु की हादसा पीड़ितों के परिवारों को पांच लाख अनुग्रह राशि देने की घोषणा

कोलकाता, 22 जुलाई (भा)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में समुद्र तट के पास हाल ही में हुई नौका दुर्घटना और पड़ोसी राज्य सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले राज्य के हर व्यक्ति के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को नागरिक स्वयंसेवक की नौकरी दी जाएगी। शुभेंदु ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए दोनों हादसों पर दुख जताया और कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। यह घोषणा उस वक्त की गयी, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक चंद्रशेखर मंडल ने दो जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कई मछुआरों के साथ मछली पकड़ने वाली नौका के लापता होने का मुद्दा उठाया। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के शंकरपुर की यह नौका पांच दिन बाद काकद्वीप के पास बहार चार के नजदीक पलटी पायी गयी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को एक बड़ी त्रासदी बताते हुए कहा कि अब तक नौका पर सवार 11 मछुआरों के शव बरामद किये जा चुके हैं, जबकि चार अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि जान गंवाने वाले अधिकतर मछुआरे पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा और नदिया जिलों के तटीय इलाकों के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने सिक्किम में सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के निवासियों के परिवारों के लिए भी समान मुआवजा राशि का ऐलान किया। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग में संदिग्ध मीथेन गैस के कारण हुए धमाके के बाद सुरंग ढह गयी, जिसमें कम से कम 20 मजदूरों की मौत हो गयी और पांच मजदूर 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। फंसे हुए लोगों में पश्चिम बंगाल के कई मजदूर भी शामिल थे।

पश्चिम रेलवे ने इंदौर को अनाथ समझ लिया है : सुमित्रा महाजन

इंदौर, 22 जुलाई (भा)। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल सुविधाओं को लेकर अपने गृहनगर की कथित उपेक्षा पर गहरी नाराजगी जताते हुए रेलवे के एक शीर्ष अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम रेलवे ने इंदौर को अनाथ समझ लिया है। महाजन के एक स्थानीय सहयोगी ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय को 20 जुलाई को पत्र लिखा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं में शामिल महाजन, लोकसभा में 1989 से 2014 के बीच लगातार आठ बार इंदौर की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। महाजन ने दो पन्नों के पत्र में कहा कि मैं अत्यंत खेद के साथ आपको संबोधित कर रही हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम रेलवे ने इंदौर को अनाथ समझ लिया है। यात्री गाड़ियां बढ़ाने के स्थान पर अन्य रेलवे जोन द्वारा दिये गये प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में डाल दिये गये हैं। उन्होंने पत्र में कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जयपुर से इंदौर और पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रीवा से इंदौर के बीच प्रस्तावित यात्री गाड़ियों के प्रस्ताव अधर में छोड़ दिये गये हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2021 में उद्घाटित मेमू सेवा का जिक्र किया और कहा कि इस सेवा का रैक (आपस में जुड़े हुए रेल डिब्बों का समूह) शहर से छीन लिया गया और स्थानीय लोगों को दोयम दर्जे के यात्री समझकर भंगार (कबाड़) में डालने लायक ऐसे डेमू रैक चलाए जा रहे हैं, जो तकनीकी खराबी के कारण कभी भी खड़े हो जाते हैं। महाजन ने अपने पत्र में इंदौर से पुणे, पटना, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम और अयोध्या के लिए रेल सेवाओं की कमी तथा मौजूदा सेवाओं के विस्तार में हो रही देरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने लाइन और प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होने को लेकर पश्चिम रेलवे के कथित तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर दो अतिरिक्त प्लेटफॉर्म हैं और नजदीकी कस्बे महू में भी अतिरिक्त लाइन क्षमता और रखरखाव की व्यवस्था उपलब्ध है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महाप्रबंधक पाण्डेय ने इस महीने की शुरुआत में अपने दो दिवसीय दौरे में इंदौर और इसके आसपास की विभिन्न रेल परियोजनाओं का निरीक्षण किया था और मातहत अफसरों को निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिये थे। महाजन ने इस दौरे की ओर इशारा करते हुए पत्र में महाप्रबंधक से कहा के आपने कुछ दिन पहले ही यह क्षेत्र देखा है। (इंदौर में) 40 लाख की आबादी की ष्टि से क्या पर्याप्त रेल सुविधाएं हैं? उन्होंने कहा कि शहर में रेल सुविधाओं की मौजूदा स्थिति देखकर कई बार लगता है कि बेहतर होता कि कोई सुविधा ही नहीं होती। पत्र के अंत में लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि महाप्रबंधक एक सक्षम अधिकारी हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह उनके शब्दों के बीच की पीड़ा और उसके पीछे की भावना अच्छी तरह समझेंगे।

चीन संचालित ठगी केंद्र से कर्नाटक के दो युवकों को बचाया गया

बेंगलुरु, 22 जुलाई (भा)। कर्नाटक साइबर कमान ने म्यांमार में चीन संचालित एक ठगी केंद्र से दो भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक बचाया है और उन्हें वापस लाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, प्रवर्तन निदेशालय और म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से यह अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के रहने वाले दोनों युवकों को सुरक्षित वापस लाया गया है और वे अपने घर पहुंच गये हैं। पुलिस के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय के एक उप निदेशक द्वारा साझा की गयी विशेष सूचना के आधार पर कर्नाटक साइबर कमान ने तत्काल मामले पर कार्रवाई की। कर्नाटक साइबर कमान के पुलिस महानिदेशक प्रणब मोहंती ने कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के साथ विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और म्यांमार में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क के माध्यम से यह बचाव अभियान पूरा किया गया।

भविष्य के युद्ध किसी एक सैन्य बल के दम पर नहीं लड़े जा सकते : एपी सिंह

करवार (कर्नाटक), 22 जुलाई (भा)। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि भविष्य के युद्ध किसी एक सैन्य बल के दम पर नहीं लड़े जा सकते। उन्होंने सशस्त्र बलों के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्तता की जरूरत पर जोर दिया। माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) के दूसरे पोत आईएनएस मालवन के जलावतरण के बाद सिंह ने कहा कि सैन्य प्रौद्योगिकियों का विकास इतनी तेजी से किया जाना चाहिए कि वे प्रासंगिक बनी रहें, क्योंकि तकनीक में देरी, तकनीक से वंचित होने के समान है। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय वायुसेना का उल्लेख करते हुए विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी युद्ध किसी एक सैन्य बल के दम पर नहीं लड़ा जाएगा। हम सभी, चाहे हम वायुसेना, नौसेना या ओजी (थलसेना के ऑलिव ग्रीन) में हों या किसी अन्य संबद्ध सेवा में, हमें एक राष्ट्र के रूप में मिलकर लड़ना होगा और तभी हम सफल होंगे। सिंह ने कहा कि पिछले चार-पांच वर्षों में इस सामूहिक अभियान को मिली गति, विशेष रूप से प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) पद के गठन के बाद जो रफ्तार मिली, वह और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। जलावतरण समारोह में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और सार्वजनिक क्षेत्र की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम सभी समझते हैं कि भारत के विकास के लिए समुद्री सुरक्षा और समुद्री शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि किसी भी देश के लिए समुद्री मार्ग उसके व्यापार को तय करते हैं और व्यापार ही उसके भविष्य को निर्धारित करता है। जहां तक भारत का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।

पृष्ठ 1 का शेष

सीएम हिमंत ने...

प्रभावित जिला है, जहां करीब 3.6 लाख लोग प्रभावित हैं। इसके बाद जोरहाट में लगभग 88,000 और चराइदेव में 72,500 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि .यह रिपोर्ट कल मध्यरात्रि जारी रिपोर्ट के आधार पर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने असम के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले चार दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार येलो अलर्ट का अर्थ सतर्क रहने और स्थिति से संबंधित अद्यतन जानकारी पर नजर बनाये रखना है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए चराइदेव में स्थापित एक राहत शिविर में लोगों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि गंभीर रूप से बीमार या चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने जनता को यह आश्वासन भी दिया कि बाढ़ में लोगों के खो गये सभी दस्तावेजों को दोबारा उपलब्ध कराने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

असम में 60 साल..

प्राकृतिक बाढ़ नहीं, बल्कि 60 से ज्यादा सालों में आया सबसे बड़ा अभूतपूर्व प्राकृतिक संकट है, जिसे बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने और भी विकराल बना दिया है। जल संसाधन विभाग के तीन से चार तटबंध टूट गये हैं और कई अन्य के ऊपर से तीन से चार मीटर की ऊंचाई पर पानी बह रहा है। सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा खुद सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जबकि अभिभावक मंत्रियों, स्थानीय विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों को जमीनी स्तर पर राहत अभियानों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस आपदा पर राजनीति न करने की अपील करते हुए बताया कि कई लोग अभी भी लापता हैं। विपक्ष के नेता वाजेद अली चौधरी ने कहा कि कई गांवों के जलमग्न हो जाने के कारण लोग छतों और पेड़ों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपूरक मांगों पर मतदान की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का हवाला देते हुए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर कांग्रेस विधायकों को अपनी बात रखने की अनुमति दी। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल के उपनेता जय प्रकाश दास ने सरकार के राहत उपायों पर सवाल उठाते हुए दो दिनों के लिए विस स्थगित करने, स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सर्वदलीय समिति प्रभावित क्षेत्रों में भेजने और प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों से असम का दौरा करने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए सदन में इस पर विस्तृत चर्चा होना बेहद जरूरी है।

छात्रों पर पुलिस...

के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जिन मुद्दों पर नोटिस दिये गये हैं, उन सभी पर चर्चा करायी जाएगी। सदन में हंगामा थमते न देख बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू होने पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहरायी और इस मुद्दे पर विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग भी की। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने पहले दिन से यह बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय अध्यक्ष (बिरला) सभी दलों के नेताओं से बात कर लेंगे। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बयान देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि सभी के मत आ गये हैं और दोनों पक्ष चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुले मन से कहा है कि वह चर्चा के लिए तैयार है। इस बीच विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा जारी रहा और अध्यक्ष ने बैठक अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने सदन में हंगामे के बीच कहा कि आज सांसद कल्याण बनर्जी ने कुछ महिला सदस्यों के खिलाफ असंसदीय टिप्पणियां की हैं, जिसकी लिखित शिकायत अध्यक्ष ओम बिरला को प्राप्त हुई है। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव रखा कि तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता की और दुर्व्यवहार किया, उन्हें मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किया जाए। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पीठासीन सभापति तेन्नेटी ने बनर्जी को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किये जाने की घोषणा की और उन्हें तत्काल सदन से बाहर जाने का आदेश दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण तेन्नेटी ने बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी। सदन में आज कई विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध स्वरूप काले परिधान पहनकर आये थे। उधर राज्यसभा में भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध कायम रहा। सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। पूर्वाह्न 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत का जिक्र किया। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। राधाकृष्णन ने स्वदेश में विकसित एवं हाइड्रोजन ईंधन से संचालित पहली रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी सदन को दी और इसे रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसके बाद विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। खरगे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खरगे की बांह पर काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक बारह बजे पुनः शुरू हुई, तब विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। हरिवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि यह प्रश्नकाल है। आजादी के 50 साल पूरे होने पर सदन में यह संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। अपनी बात का असर न होते देख हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी। दो बजे बैठक शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष खरगे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है, जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है? उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने के बाद नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अब विपक्षी कांग्रेस के सदस्य शर्त रख कर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

राहुल की केंद्र...

कि मेरी सरकार से पहली मांग ये कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारी छात्रों की भी यही मांग है। मेरी दूसरी मांग ये हैं कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार लोकसभा में चर्चा करें. ये देशहित से जुड़ा मुद्दा है और छात्रों का भविष्य अधर में जा रहा है। तीसरा और आखिरी मांग ये है कि छात्रों के साथ सरकार ने जो रवैया अपनाया है। उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माफी मांगें। इन तीनों मांगों से हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार घबराई हुई है और सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैलाना चाहती है। हमने पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्पीकर से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत के बाद आपको बताएंगे। हम छात्रों के साथ हैं और इस मुद्दे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। राहुल गांधी ने कल पीएम आवास के बाहर हुए प्रदर्शन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कल मुझे घसीटकर पुलिस वैन में भरा गया। धरनास्थल से मुझे हटाने वाले पुलिसकर्मी भी कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए, लेकिन उनको ऊपर का आदेश मानना पड़ता है. एक पुलिसकर्मी हरियाणा का था जबकि दूसरा राजस्थान का था। राहुल गांधी ने कहा कि कल पीएम आवास के बाहर मेरा साथ क्या हुआ यह मुद्दा नहीं है। कल मेरा मुंह से खून निकल रहा था। जितेंद्र सिंह उनसे बात करने के लिए आये थे, लेकिन उनकी बातों को कोई महत्व नहीं था। सरकार मुझपर क्या आरोप लगा रही है मुझे कोई मतबल नहीं है। हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। हिंदुस्तान के छात्र सड़क पर हैं और विपक्ष को भी सड़क पर होना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस सरकार ने देश में रोजगार के सारे अवसर खत्म कर दिये हैं। सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार इस पर भी कुछ नहीं कह रही है, जबकि ये उनकी जवाबदेही बनती है। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हो चुके हैं। इससे करीब 7.5 करोड़ परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक मामले में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। शिक्षा को बर्बाद करने वालों को सजा नहीं हुई है।

छात्रों पर लाठीचार्ज...

पूरा करने के लिए मानेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने साफ तौर पर कह दिया है कि हम घर या ऑफिस नहीं आ रहे हैं। पहली मुलाकात में हमें चार घंटे रोके रखा गया था। हमारी तरफ से कहा गया है कि अगर हमारी मांगें पूरी करेंगे, तभी हमें बुलाइए।

10 वर्षों में...

लोगों को वापस भेजा गया। इनमें 1,810 बांग्लादेशी और 1 नाइजीरियाई नागरिक शामिल था। वहीं चालू वर्ष में 30 जून तक 263 अन्य विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजा जा चुका है, जिनमें बांग्लादेश के 261 और माली के 2 नागरिक शामिल हैं।

असम के किसान...

सब्सिडी भी दे रही है। सरकार चाहती है कि किसान पोखरी एवं तालाबों को केवल मछली पालन तक सीमित न रखें बल्कि उसके साथ-साथ मखाने की भी खेती करें। उनका कहना था कि विश्व में यह सुपर फूड कहलाता है और इसकी मांग काफी है। हमें क्षेत्र में नयी संभावनाओं को तलाश कर युवाओं को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं।

भारत ने हिंद-प्रशांत...

यात्रा पर आये थे। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। क्वाड ने एक संयुक्त बयान में कहा कि संगठन ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीयता के प्रति अटूट समर्थन व्यक्त किया। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) को इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है और भारत तथा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद साझेदार हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि हम इस क्षेत्र की सफलता और आसियान तथा उसके सदस्य देशों के साथ सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसमें कहा गया है कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय चुनौतियों और हिंद-प्रशांत संबंधी आसियान आउटलुक (एओआईपी) को व्यावहारिक रूप से लागू करने के अवसरों पर भी चर्चा की। बयान के मुताबिक बैठक में समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि एवं सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों और मानवीय सहायता एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़ी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। बयान में विदेश मंत्रियों ने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता ही इस क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि का आधार है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नयी दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक के परिणामों पर आगे की कार्रवाई की गयी। आसियान की केंद्रीय भूमिका को मानते हुए एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत की प्रतिबद्धता दोहरायी गयी। रुबियो ने कहा कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रेखांकित किया गया कि मजबूत सहयोग इस क्षेत्र में आसियान की अपनी प्राथमिकता और केंद्रीय भूमिका का समर्थन करने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक ऐसे स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत ष्टिकोण को साझा करते हैं, जो कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित है। रुबियो ने कहा कि क्वाड एक प्राथमिकता बना हुआ है और हम इस साल के आखिर में फिर मिलेंगे। जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में इस बात की पुष्टि हुई कि यह समूह समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, अहम प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता पर केंद्रित स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुख्ता सहयोग को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। मोतेगी ने कहा कि यह बहुत अहम बात है कि मई में हुई बैठक के बाद क्वाड मंत्री इतनी जल्दी फिर से मिले। आज बैठक से यह कड़ा संदेश जाता है कि क्वाड ऐसे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे इस क्षेत्र को लाभ हो। जापान के एक बयान में कहा गया कि चारों मंत्रियों ने पुष्टि की कि क्वाड मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत (एफओआईपी) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस सहयोग जारी रखेगा। इसमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, अहम और उभरती हुई प्राद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे चार क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत और मध्य पूर्व (जिसमें पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर भी शामिल हैं) की स्थितियों पर अपने-अपने नजरिए को खुले माहौल में साझा किया। बयान के मुताबिक मोतेगी ने ताकत या दबाव के दम पर एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया और अहम खनिजों समेत निर्यात पर लगी पाबंदियों को लेकर गंभीर चिंता जतायी। साथ ही उन्होंने उत्तर कोरिया को पूरी तरह परमाणु-मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। बयान के मुताबिक चारों देशों के विदेशमंत्रियों ने अगले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की बैठक के आयोजन का बेसब्री से इंतजार होने की बात कही।

सिक्किम : सुरंग में...

सिक्किम के समरडुंग में सोमवार दोपहर एनएचपीसी पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन हेड रेस सुरंग (एचआरटी) कथित तौर पर चट्टानों के भीतर फंसी मीथेन गैस के अचानक निकलने से हुए विस्फोट के कारण ढह गयी। अधिकारियों ने इस हादसे में कम से कम 20 श्रमिकों की मौत की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग से अब तक 12 श्रमिकों के शव निकाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग में जमा हुए पानी को निकालने और दुर्घटनास्थल को आगे के अभियान के लिए सुरक्षित घोषित किये जाने के बाद ही बाकी शवों को निकालने का काम शुरू होगा। एनएचपीसी के मुताबिक निर्माणाधीन सुरंग में कथित तौर पर चट्टानों के भीतर की मीथेन गैस के अचानक निकलने से हुए विस्फोट के कारण वहां घना धुआं और जहरीली गैस फैल गयी। अधिकारियों ने बताया कि बचाव कर्मियों को आपातकालीन सहायता देने के लिए दुर्घटनास्थल पर चिकित्सा दल और एंबुलेंस तैनात की गयी हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सुरंग ढहने की घटना में मारे गये श्रमिकों के परिजन को चार-चार लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया।

त्रिपुरा डीजीपी मौत...

मौत का मामला दर्ज किया गया है और हमने जांच शुरू कर दी है। जांच के तहत डीजीपी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और निजी कंप्यूटर समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिये गये हैं। इन्हें जांच के लिए पश्चिम त्रिपुरा के नरसिंगढ़ स्थित राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल) भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक विश्लेषण में कम से कम डेढ़ महीने का समय लगेगा। जांच अधिकारी ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि डीजीपी ने आत्महत्या की है तो हमें यह पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजीपी) प्रबीर मजूमदार ने शिकायत में कहा कि उन्होंने सोमवार को डीजीपी से मिलने के लिए काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने सोमवार को कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि पूर्वाह्न 11 बजे तक किसी भी आगंतुक को उनके कमरे में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। जब मजूमदार उस दिन डीजीपी से मिलने पहुंचे तो कर्मचारियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने मंगलवार को डीजीपी की कथित आत्महत्या मामले की न्यायिक जांच की मांग दोहरायी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता ने एक वीडियो में कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि जिस शीर्ष पुलिस अधिकारी ने अपने पेशेवर जीवन में कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने बिना किसी बड़े कारण के आत्महत्या कर ली। मुझे पता था कि डीजीपी मानसिक तनाव में थे। मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करता हूं कि सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायिक जांच का आदेश दिया जाए। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सौमिक देब ने लोगों से अपील की कि वे अदालत का रुख करें, ताकि वह इस मामले का स्वतः संज्ञान ले सके।

युवा सुयोग बनेगा बदलाव का माध्यम, पंचायत और वार्डों में विकसित होगा युवा नेतृत्व : भजनलाल शर्मा

जयपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेल-खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री युवा सुयोग का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की शक्ति को सामर्थ्य में बदलने के लिए युवा सुयोग प्लेटफॉर्म एक सही दिशा, सही अवसर और सही मंच उपलब्ध कराएगा। क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे सामूहिक खेलों के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक पंचायत और वार्ड में युवा नेतृत्व विकसित होगा और वे अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 65 प्रतिशत युवा आबादी के साथ हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है। यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा शक्ति को राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय सहभागी बनाने के लिए माय भारत की अभिनव पहल की है। इसी से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने सुयोग प्लेटफार्म जैसी क्रांतिकारी शुरूआत की है। इस प्लेटफॉर्म को माय भारत पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि युवा को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने किया खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद

मुख्यमंत्री ने बारां और बगरू के खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद करते हुए उनके विचार जाने। युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का प्रभावी मंच मिलेगा। साथ ही, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता के अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय प्रतिभाएं खेल के मैदान में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।

पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक युवाओं का सहयोग कर रही राज्य सरकार

उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलने का मौका मिलता रहे और उनकी रूचि विकसित हो, इसके लिए राज्य सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। गांव से लेकर कस्बों तक खेल सुविधाओं एवं सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार युवाओं से विभिन्न विषयों पर संवाद कर उनके सुझावों को बजट में शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर क्षेत्र में कार्य करते हुए युवाओं को सफलता की पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक की यात्रा में पूर्ण सहयोग कर रही है।

युवाओं की निखरेगी प्रतिभा, खेल मैदानों की होगी डिजिटल पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि युवाओं के सुझावों के मुख्य आधार पर ही खेल की नीतियां तैयार की जाए। इसी क्रम में युवा सुयोग के अंतर्गत राज्य सरकार जमीनी स्तर पर प्रतियोगिताओं की शुरूआत करेगी। वार्ड और पंचायत स्तर से आगे बढ़कर विजेता टीमें विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अपना हुनर दिखाएंगी और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। युवा इसके लिए सुयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कूल, कॉलेज तथा पंचायत और वार्ड के खेल मैदानों की डिजिटल पहचान भी की जाएगी।

जिला स्तरीय सुयोग युवा क्लब बनेंगे, पंचायत-वार्ड क्लबों से जुड़ेंगे

उन्होंने कहा कि सुयोग प्लेटफार्म एक डिजिटल क्रांति है जो प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड के अंतिम पंक्ति के युवाओं की ट्रैकिंग कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ेगी। इसके माध्यम से बड़ा सामाजिक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सुयोग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्रत्येक युवा सदस्य होगा। ये जिला क्लब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर के युवा क्लबों से जुड़ेंगे। प्रारंभिक रूप से बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा सुयोग के अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों पर विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। युवाओं की नेतृत्व क्षमता को परखने के लिए स्वच्छता अभियान और डिजिटल साक्षरता जैसे स्वयंसेवक कार्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुयोग-चर्चा के तहत युवा संवाद, टॉक शो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रख सकेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। गत ढाई वर्षों में युवाओं को लगभग 1 लाख 78 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। करीब 1 लाख पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और सवा लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। साढ़े चार लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार प्रदान किया गया है। वहीं, इस दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और सभी भर्ती परिक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई।

उन्होंने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति-2025 और राजस्थान युवा नीति-2025 लाई गई है। इसी प्रकार साढ़े तीन लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4 लाख से अधिक आशार्थियों को 1 हजार 347 करोड़ रुपये की राशि एवं साढ़े चार हजार से अधिक स्टार्टअप्स का पंजीकरण सहित कई परिणामोन्मुखी निर्णय किए गए हैं।

बगरू विधायक डॉ. कैलाश वर्मा ने कहा कि अनुशासित युवा विकसित राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद है। युवा हितों की दिशा में युवा सुयोग अनुपम पहल है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि युवा सुयोग महज एक खेल योजना नहीं है, बल्कि खेल प्रतिभाओं को प्रभावी मंच उपलब्ध करवाने का माध्यम है, जो कि स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तलाशेगा और तराशेगा।

अब 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच होंगे निकाय और पंचायत चुनाव

जयपुर, एजेंसी। नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव क्रमिक रूप से 15 अगस्त 2026 से 15 नवंबर 2026 के मध्य संपन्न होंगे। पहले नगरीय निकाय चुनाव दो चरण में और फिर पंचायती राज चुनाव चार चरण में करवाया जाना प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि अलग-अलग चरणों में चुनाव कराए जाने का कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव के एक चरण के लिए 60,000 कर्मचारी और 50 हजार पुलिस कर्मी चाहिए। इसी प्रकार पंचायती राज चुनाव के एक चरण के लिए 80,000 कर्मचारी और 70,000 पुलिस कर्मी चाहिए। नगरीय चुनाव दो चरण में कुल 309 नगरीय निकायों के 10, 245 वार्ड के 16,482 मतदान केन्द्रों पर होगा, जिसमें 1,43,75,806 मतदाता भाग लेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव चार चरणों में कुल 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के कुल 45316 मतदानकेंद्रों पर होगा जिसमें कुल 4,02,18,969 मतदाता भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि नगरीय चुनाव प्रत्यक्ष रूप से केवल सदस्य पद के लिए होगा जबकि पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चार पदों क्रमशः वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए होगा। इसके अलावा नगरीय निकाय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख के अप्रत्यक्ष चुनाव भी होंगे।

यह विस्तृत, जटिल और व्यापक चुनाव प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अतुलनीय है । राजस्थान के धरातलीय लोकतंत्र के लिए यह अद्भुत, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर है कि समस्त नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव एक साथ संपन्न होने जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक सम्पन्न

जयपुर, एजेंसी । उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के संयोजक डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में राजकीय महाविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों के नामकरण संबंधी प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णयार्थ मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कार्यसूची में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लिए गए। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह, विद्यालय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं उपसमिति के सदस्य सचिव कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों का नामकरण ऐतिहासिक महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में किया जाएगा। साथ ही, जिन संस्थानों के लिए दानदाताओं का योगदान रहा है, उनमें 'राजकीय' शब्द के बाद दानदाता का नाम जोड़ा जाएगा।

उपसमिति ने चिकित्सा महाविद्यालय, हनुमानगढ़ का नाम परिवर्तित कर 'बलिदानी योद्धा मेजर विकास भाम्भू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हनुमानगढ़' करने का निर्णय लिया। चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर के लिए 'महाराजा गंगा सिंह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर किया गया। इसी प्रकार चिकित्सा महाविद्यालय, पाली का नाम 'महाराणा प्रताप राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली' तथा चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर का नाम 'भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज, अलवर' किए जाने का निर्णय लिया गया।

वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 : मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी, 24 से 26 जुलाई तक दर्ज होंगी ऑनलाइन आपत्तियां

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 28 जून 2026 को आयोजित वनपाल (परीक्षा कोड-ल12क) सीधी भर्ती 2026 परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की है। सूची बोर्ड की वेबसाइट www.rssb. rajasthan.gov.in पर अपलोड की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव प्रीति माथुर ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आई.डी. के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आपत्तियां 24 जुलाई 2026 समय 00:01 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 26 जुलाई 2026 समय 23:59 बजे मध्यरात्रि तक दर्ज करवाई जा सकेंगी। ऐसे अभ्यर्थीगण जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे अपनी आपत्ति सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा जयपुर के नाम से निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर आपत्ति के साथ संलग्न कर दिनांक 24, जुलाई 2026 समय प्रातः 10 बजे से दिनांक 28 जुलाई 2026 समय सायं 6 बजे तक अपनी ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा करवा सकते हैं।'

नगर निगम जयपुर की बड़ी कार्रवाई: 37 हजार रुपये कैरिंग चार्ज वसूला, 4 कैंटर सामान जब्त

जयपुर, एजेंसी। नगर निगम जयपुर की सतर्कता शाखा ने सोमवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 37 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया और 4 कैंटर सामान जब्त किया। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देशों और पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में की गई। नगर निगम की टीम ने गंगा मार्ग (खातीपुरा स्टेशन के सामने), बंशीपुर द्वितीय (जगतपुरा), नामदेव कॉलोनी (एनडब्ल्यूआर रेलवे ऑफिस के सामने), किसान मार्ग से अर्जुन नगर फाटक, गैलेक्सी टावर (विद्याधर नगर), परशुराम सर्किल (विद्याधर नगर) तथा बीकेआई रोड नंबर-6 से कालवाड़ रोड तक अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण में प्रयुक्त और सड़क पर रखे गए सामान को जब्त कर 4 कैंटर में भरकर नगर निगम के गोदाम भेजा गया। साथ ही मौके पर ही अतिक्रमणकर्ताओं से 37 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूला गया।

उपायुक्त सतर्कता ने बताया कि अभियान के दौरान संबंधित लोगों को भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। उन्होंने कहा कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो नगर निगम की ओर से भारी जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण न करें तथा शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और यातायात के लिए सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करें।

एआई से बीच वेडिंग तक वेडिंग इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स पर मंथन

जयपुर, एजेंसी। वेडिंग सेलिब्रेशन अब सिर्फ परंपराओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सोशल मीडिया और नई तकनीकों ने वेडिंग इंडस्ट्री का स्वरूप बदलना शुरू कर दिया है। होटल फेयरमॉन्ट में आयोजित इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव (आईडब्लूटी) सीजन-3 के दूसरे दिन 'द एआई वेडिंग्स' विषय पर आयोजित मास्टर क्लास में एआई विशेषज्ञ मोहम्मद इरशाद ने कहा कि एआई की मदद से वेडिंग प्लानिंग, गेस्ट मैनेजमेंट, डिजिटल इनविटेशन, डेकोरेशन, बजट प्लानिंग और कंटेंट क्रिएशन पहले की तुलना में अधिक स्मार्ट और प्रभावी हो गए हैं। एआई आधारित तकनीकों से वेडिंग प्लानर्स 50% तक समय की बचत करते हुए कम लागत में ग्राहकों को बेहतर और व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को एआई के व्यावहारिक उपयोग, उभरते ट्रेंड्स और भविष्य की संभावनाओं से भी अवगत कराया। कॉन्क्लेव में फोरम के प्रेसिडेंट, हितेश शर्मा; वाईस प्रेजिडेंट, अजय चौहान; सेक्रेटरी, भुवनेश अग्रवाल और पूर्व प्रेसिडेंट, मोहित माहेश्वरी मजूद रहे। 'ग्रेट ग्रैंड कूकस रोड' एक और मास्टर क्लास में महावीर शर्मा, रजत सेठी, हेमंत और अनूप पाण्ड्य ने चर्चा की कि जयपुर का कूकस- दिल्ली रोड कॉरिडोर देश के सबसे तेजी से उभरते डेस्टिनेशन हब में शामिल हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग की संख्या में 30-40% तक बढ़ी है। इसके चलते फाइव स्टार होटल, लग्जरी रिसॉर्ट्स और बड़े वेडिंग वेन्यू की मांग लगातार बढ़ रही है। एक वेडिंग में औसतन 200 से 500 कमरे और 500 से 2,000 मेहमानों के ठहरने व आयोजन की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ऐसे में आने वाले वर्षों में कूकस रोड पर 10 से अधिक नए लग्जरी होटल और रिसॉर्ट्स विकसित होने की संभावना है। इन ही पहलुओं के देखते हुए बेहतर सड़क, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की निकटता, विश्वस्तरीय हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं और इस क्षेत्र के सभी होटलों के सहयोग के कारण जयपुर अंतरराष्ट्रीय वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से अपनी पहचान मजबूत करेगा। 'द वेडिंग बजट इकोनॉमिक्स' सत्र में प्रितेश शर्मा ने लागत प्रबंधन और वेडिंग बिजनेस के नए मॉडल पर चर्चा की।

पालतू श्वान-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 30 सितंबर तक कराएं पंजीयन, नहीं तो लगेगा रु 5,000 जुर्माना : ओम कसेरा

जयपुर। जयपुर नगर निगम ने शहर में पालतू श्वान और बिल्ली पालने वाले सभी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 30 सितंबर 2026 तक सभी पालतू श्वानों एवं बिल्लियों का नगर निगम में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई पालतू श्वान बिना पंजीकरण के पाया जाता है, तो उसके मालिक पर प्रति श्वान ?5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आयुक्त ओम कसेरा ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी प्रकार की सख्ती करना नहीं, बल्कि पालतू पशुओं की सुरक्षा, उनके बेहतर स्वास्थ्य और जयपुर को रेबीज मुक्त शहर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य भवन में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की

जयपुर, एजेंसी। प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को डिजीटल माध्यम से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, हाई रिस्क गर्भवतियों की निगरानी, रेफरल प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग तथा प्रसव सुविधा वाले राजकीय अस्पतालों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पिछले 24 घंटे में प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में हुए सभी सिजेरियन प्रसव तथा हाई रिस्क गर्भवतियों की स्थिति की अधिकारियों एवं फील्ड स्वास्थ्यकर्मियों से सीधे जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इस

अवधि में सभी प्रसव सुरक्षित रहे। इस पर उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को भर्ती सभी प्रसूताओं की सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जयपुर, चूरू, झुंझुनूं जिलों की एएनएम से भी सीधे संवाद किया। उन्होंने हाई रिस्क गर्भवतियों के नियमित फॉलोअप, संभावित प्रसव तिथि की निगरानी, समय पर चिकित्सकीय परामर्श तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रेफरल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज द्वारा विकसित 'सेतु डिजिटल इमरजेंसी हेल्थकेयर सॉफ्टवेयर' की कार्यप्रणाली की जानकारी लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इसी प्रकार का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं अन्य फील्ड स्वास्थ्यकर्मियों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे गर्भवती महिलाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग तथा रेफरल प्रबंधन और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) से अस्पतालों में दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता तथा इन्वेंटरी प्रबंधन की समीक्षा की। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी सेवाओं के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल तैयार कर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर (आरओपी) जारी करने के निर्देश दिए, ताकि सभी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण एवं एकरूप सेवाएं सुनिश्चित हो सकें। मुख्य सचिव ने सुरक्षित मातृत्व सेवाओं से जुड़ी सूचनाओं एवं प्रसव संबंधी मामलों की त्वरित मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर समर्पित कंट्रोल रूम स्थापित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक प्रसूता की स्थिति पर राज्य स्तर से सतत निगरानी रखी जा सकेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित निर्णय संभव होंगे।

जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, मोदी सरकार के अच्छे दिन का बर्बर चेहरा देख रहा देश : टीकाराम जूली

जयपुर, एजेंसी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली ने मोदी सरकार के 'अच्छे दिन' वाले जुमले पर करारा तंज कसते हुए कहा कि 'जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है 'राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां मोदी सरकार की संवेदनहीनता पर पूरी तरह सटीक बैठती हैं। उन्होंने कहा कि जिस अच्छे दिन का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा गया था, उसका असली और खौफनाक चेहरा पुलिस के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में घायल हुआ युवा अस्पताल में इलाज करवाते हुए देख रहा है।

यह भी शर्मनाक है कि मोदी सरकार अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा तक नहीं है और कांग्रेस को संसद में इस मुद्दे को उठाने तक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवा को निर्दयतापूर्वक क्यों मारा-पीटा गया इस पर संसद में भी चर्चा न हो, तो कहां बात करें?उन्होंने कहा कि आज देश का युवा सड़कों पर है, लेकिन उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वह अपने हक, अपने सुनहरे भविष्य और पारदर्शी परीक्षाओं की मांग कर रहा है। मगर अहंकार और संवेदनहीनता की तमाम सीमाएं लांघ चुकी मोदी सरकार को इन युवाओं की जायज आवाज सुनने के बजाय उन पर बर्बरता से लाठियां बरसाना ज्यादा आसान लग रहा है।

श्री जूली ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी मंगलवार को अस्पताल पहुंचकर पुलिस की इस बर्बरता में गंभीर रूप से घायल हुए छात्रों से मुलाकात की, उनका हाल-चाल जाना और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़े होने का भरोसा दिलाया।

एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर भर्ती 2024: एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की पात्रता जांच के लिए 45 अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी

जयपुर, एजेंसी। लोक सेवा आयोग द्वारा एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर (कृषि विभाग) भर्ती-2024 के तहत पात्रता जांच के लिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की विचारित सूची जारी की गई है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त भर्ती अंतर्गत आयोजित परीक्षा के फलस्वरूप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 45 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु विचारित सूची में सम्मिलित किया गया है। विचारित सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन/वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची कृषि विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी- अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें।

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 24 से 30 जुलाई 2026) तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (कृषि विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं एवं कृषि विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों की पात्रता जांच विज्ञापन की शर्तों व नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी। संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

राज्य सरकार प्रगतिशील नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध : कर्नल राज्यवर्धन राठौड

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने सोमवार को अलवर में ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (टैफे) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैफे मोटर्स एण्ड ट्रैक्टर्स लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र में डॉयट्स इंजन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। यह टैफे मोटर्स और डॉयट्स एजी के बीच उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में पहली साझेदारी है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रगतिशील नीतियों एवं व्यापार को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं के माध्यम से उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राज्य एक पसंदीदा मैन्युफेक्चरिंग केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश अनुकूलता के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं। इससे प्रदेश में उद्योगों की रफ्तार में गति मिल रही है और युवाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैफे नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने व विश्व स्तरीय तकनीक एवं मैन्युफेक्चरिंग उत्कृष्टता के माध्यम से भारत के किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वनडे रैंकिंग

डेरिल मिशेल के करीब पहुंचे गिल

जो रूट की टॉप-10 में एंट्री

नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा बुधवार को जारी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल नंबर वन बल्लेबाज बनने के काफी करीब आ गए हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को भी काफी फायदा हुआ है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेरिल मिशेल 802 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। गिल और मिशेल की रेटिंग में सिर्फ एक अंक का अंतर है। विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं, जबकि लॉर्ड्स में हाल ही में 138 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान पांचवें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम और आयरलैंड के हैरी टैक्टर को 1-1 स्थान का फायदा हुआ है। दोनों क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ संपन्न वनडे सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे इंग्लैंड के जो रूट को 4 स्थान का फायदा हुआ है। रूट शीर्ष 10 खिलाड़ियों में वापस आ गए हैं और आठवें नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज के शे होप को तीन स्थान का घाटा हुआ है, वे नौवें नंबर पर हैं। श्रीलंका के चरिथ असलांका एक अंक के नुकसान के बावजूद दसवें स्थान पर हैं। वनडे फॉर्मेट के शीर्ष दस गेंदबाजों की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान पहले और पाकिस्तान के अबरार अहमद दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को एक स्थान का फायदा हुआ है, वह तीसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर को तीन स्थान का फायदा हुआ है। सेंटनर चौथे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज और श्रीलंका के महिश तिक्षाणा क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर हैं। दोनों को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी दो स्थान के फायदे के साथ सातवें और बांग्लादेश के मेहदी हसन दो स्थान के फायदे के साथ आठवें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के आदिल रशीद तीन स्थान के नुकसान के साथ नौवें और वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती 7 स्थान की छलांग लगाकर दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ

शुभमन गिल-मोसाद्देक हुसैन को पछाड़कर नाथन स्मिथ ने जीता जून माह का खिताब

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ 'जून 2026' के लिए 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' चुने गए हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। कीवी खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल और बांग्लादेशी ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन जैसे दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है। 27 वर्षीय स्मिथ ने इंग्लैंड में खेली गई 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 23 की औसत से सर्वाधिक 16 विकेट चटकाए थे। न्यूजीलैंड के कई मुख्य तेज गेंदबाजों के चोट के कारण बाहर होने के बाद स्मिथ ने जिम्मेदारी संभालते हुए दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। नाथन स्मिथ ने सोमवार को 'आईसीसी' के एक बयान में कहा, 'यह वाकई बहुत खास है। टीम के लिए इंग्लैंड का दौरा शानदार रहा और यह बहुत अच्छी बात है। मैं आमतौर पर व्यक्तिगत अवॉर्ड के लिए नहीं खेलता, लेकिन यह पहचान मिलना अच्छा लगता है और इससे भी जरूरी बात यह है कि मैंने सीरीज जीतने में योगदान दिया। व्यक्तिगत रूप से, जीत में योगदान देना बहुत संतोषजनक रहा। न्यूजीलैंड के लिए मैं बस यही करना चाहता हूं- पूरी कोशिश करना और जिस भी तरह से हो सके, योगदान देना। दुर्भाग्य से, सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, इसलिए मुझे आगे आकर नई गेंद से बॉलिंग की शुरुआत करनी पड़ी।

WWE के सबसे बड़े मेगा इवेंट का एलान

ब्रॉक लैसनर बनाम ओबा फेमी से रोमन रेंस बनाम सैथ रॉलिंस तक

नई दिल्ली। नई दिल्ली। WWE के सबसे बड़े मेगा इवेंट में से एक समरस्लैम 2026 को लेकर सुर्खियां तेज हैं। इस इवेंट के मैच कार्ड भी लगभग तय हो चुके हैं। कई मुकाबलों का ऐलान हो चुका है, जिसमें ब्रॉक लैसनर की भिड़ंत ओबा फेमी और रोमन रेंस की भिड़ंत सैथ रॉलिंस से तय है। इस मेगा इवेंट का आयोजन अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के शहर मिनियापोलिस में होगा। समरस्लैम के छह बड़े मैचों का कार्ड फाइनल हो चुका है। वहीं फैंस बिल्कुल ही इन सभी मैचों के शेड्यूल, समय, वेन्यू और तारीखों की जानकारी चाहते होंगे। वैसे तो इस मेगा इवेंट का आयोजन दो दिन होगा। 1 अगस्त और 2 अगस्त 2026 की रात में समरस्लैम के मुकाबले होंगे। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होने वाला है ब्रॉक लैसनर और ओबा फेमी का हेल इन ए सेल मैच, जिसमें दोनों रेसलर पिंजड़े में भिड़ते नजर आएंगे।

ब्रॉक लैसनर और ओबा फेमी के बीच विवाद रेसलमेनिया 2026 के पहले से चल रहा है। रेसलमेनिया में लैसनर को हार मिली थी। फिर क्लैश इन इटली में उन्होंने बदला लिया था। इसके बाद भी विवाद नहीं थमा और अब समरस्लैम में दोनों रेसलर्स आमने-सामने होंगे।

कब और कहां आयोजित होंगे समरस्लैम 2026 के मैच?

समरस्लैम 2026 के मुकाबले 1 और 2 अगस्त को मिनियापोलिस स्थित यूएस बैंक स्टेडियम में आयोजित होंगे। इस इवेंट की शुरुआत दोनों दिन (1 और 2 अगस्त को) ब्रिटिश समय के मुताबिक रात 11 बजे से होगी। यानी भारत में फैंस शाम 6.30 बजे से WWE समरस्लैम का लुत्फ उठा सकते हैं। सोनी टेन भारत में इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर होगा। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फैंस देख सकते हैं।

कुलदीप यादव यॉर्कशायर से जुड़े, 'वन-डे कप' और 'काउंटी चैंपियनशिप' खेलते नजर आएंगे

लीड्स, । बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव ने मौजूदा घरेलू सीजन के लिए इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशायर के साथ करार किया है। क्लब ने बुधवार को भारत के प्रमुख खिलाड़ी के जुड़ने की घोषणा की। इस समझौते के तहत, कुलदीप सितंबर में यॉर्कशायर के आखिरी चार काउंटी चैंपियनशिप मुकाबलों में से तीन खेलने के लिए हेडिंग्ले लौटने से पहले पांच वन-डे कप मैचों में हिस्सा लेंगे। उनका यह कार्यकाल शुक्रवार को नीथ में ग्लैमॉर्गन के खिलाफ 50 ओवरों के मैच से शुरू होगा। कुलदीप यादव इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज

का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिल सका। इस फैसले ने फैंस को हैरान किया। कुलदीप ने क्लब की तरफ से जारी बयान में कहा, 'मैं यॉर्कशायर से जुड़कर बहुत खुश हूं और इस मौके के लिए आभारी हूं। यॉर्कशायर के शानदार इतिहास वाले क्लब का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मुझे हमेशा इंग्लिश परिस्थितियों में खेलने की चुनौती पसंद है। मैनेजमेंट से बात करने के बाद, मैं टीम से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हो गया और हेडिंग्ले में अपने समय के दौरान सकारात्मक योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।'

31 वर्षीय कुलदीप यादव ने 18 टेस्ट मुकाबलों में 22.35 की औसत के साथ 79 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान साल 2024 में इंग्लैंड के विरुद्ध पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 19 विकेट हासिल किए थे। वनडे फॉर्मेट में कुलदीप ने 121 मुकाबलों में 194 विकेट निकाले हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25/6 रहा है। कुलदीप ने भारत की तरफ से 54 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 13.74 की औसत के साथ 95 विकेट चटकाए। यॉर्कशायर के क्रिकेट महाप्रबंधक गैविन हैमिल्टन ने कहा कि कुलदीप के आने से सीजन के अहम आखिरी चरण में उनकी गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी। हैमिल्टन ने कहा, 'कुलदीप एक बेहतरीन, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो इन मैचों के दौरान हमारी टीम को बहुत मजबूती देंगे।

जिम्बाब्वे के खिलाफ बस 11 छक्के और बन जाएंगे T20 में नंबर 1

वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली। भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद अब जिम्बाब्वे के दौरे पर गई है। इस दौरे पर टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा। इस सीरीज में पहली बार वैभव सूर्यवंशी बतौर प्रमुख ओपनर बनकर गए हैं। इंग्लैंड में वैभव का प्रदर्शन खास नहीं था लेकिन अब जिम्बाब्वे सीरीज में उनके पास मौका है अपनी जगह पक्की करने का।

जिम्बाब्वे दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर टी20 क्रिकेट का खास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वह तीन मैचों की सीरीज में अगर 11 छक्के लगा देते हैं तो टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 150 छक्के पूरे करने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे। वैभव के नाम अभी तक 37 पारियों में 139 छक्के टी20 क्रिकेट में दर्ज हैं।

हालांकि, इस मामले में नंबर 1 पर काबिज खिलाड़ी ने 66 पारियों में यह कारनामा किया था। नंबर 1 पर नाम है यूएई के मोहम्मद वसीम का। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के एविन लुईस और तीसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं। अगर वैभव ने यह कारनामा किया तो वह तीनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ नंबर 1 बन जाएंगे।

टी20 में सबसे तेज 150 छक्के

- मोहम्मद वसीम (UAE): 66 पारी
- एविन लुईस (WI): 70 पारी
- क्रिस गेल (WI): 72 पारी
- **सूर्यकुमार यादव को भी पीछे छोड़ सकते हैं वैभव-** वैभव सूर्यवंशी ने 37 पारियों में 139 छक्के टी20 क्रिकेट में अभी तक लगाए हैं। वह 11 छक्के और लगाते ही भारत समेत पूरी दुनिया में नंबर 1 बन जाएंगे। उनके नाम टी20 में सबसे तेज 150 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। भारत के लिए यह रिकॉर्ड 86 पारियों में सूर्यकुमार यादव ने बनाया था। यानी वैभव सूर्या को भी पीछे छोड़ सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में कैसा रहा था प्रदर्शन?

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड सीरीज में तीन पारियों में 42 रन ही बनाए थे। उन्होंने 27 गेंद का सामना किया था जिसमें 5 छक्के और सिर्फ एक चौका उनके बल्ले से निकला था। उन्होंने तीन मैचों में 12 गेंद पर 14 रन, 5 गेंद पर 13 रन और 10 गेंद पर 15 रन बनाए थे।

एपीएल से निखरेगी राज्य की नई क्रिकेट प्रतिभाएं : नेचिम

गुवाहाटी, 22 जुलाई (ख.सं.)। आईपीएल के पूर्व तेज गेंदबाज और गुवाहाटी रॉयल्स के दिग्गज खिलाड़ी अबू नेचिम ने असम प्रीमियर लीग (एपीएल) को राज्य की छिपी हुई क्रिकेट प्रतिभाओं को सामने लाने का एक शानदार मंच बताया है। एपीएल की खिलाड़ी नीलामी के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट युवा और उभरते खिलाड़ियों को स्थापित क्रिकेटरों के साथ एक ही मंच पर खेलने और खुद को साबित करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। नीलामी सूची में 270 से अधिक खिलाड़ियों की मौजूदगी का हवाला देते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि वे इनमें से केवल 120 खिलाड़ियों से ही परिचित थे। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि पूरे असम में कितनी बड़ी संख्या में ऐसी प्रतिभाएं मौजूद हैं, जिन्हें अब तक सही पहचान नहीं मिल सकी थी और एपीएल उन्हें यह मुकाम दे रहा है। अपने क्रिकेट सफर और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रियान पराग का उदाहरण देते हुए अबू नेचिम ने कहा कि हर टीम का मुख्य मकसद टूर्नामेंट जीतना होता है, लेकिन इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य खिलाड़ियों को आईपीएल और भारतीय राष्ट्रीय टीम के दरवाजे तक पहुंचाना है। असम क्रिकेट संघ (एसीए) के तत्वावधान में आयोजित यह प्रीमियर लीग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आई फ्रेंचाइजी टीमों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को एक पेशेवर टी-20 माहौल मुहैया करा रही है। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि यह पहल आने वाले लंबे समय तक असम क्रिकेट के भविष्य को संवारने और मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगी।

रोहित नंबर 1 कोहली-गिल-श्रेयस सब पीछे

वनडे में चेज करते हुए इस दशक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

नई दिल्ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे थे, बात उनके रिटायरमेंट की भी हो रही थी, लेकिन इन सारी बातों को बीच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में वनडे प्रारूप में उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने इससे पहले नहीं किया था। रोहित ने बताया कि वो अभी चूके नहीं हैं और वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रोहित ने लॉर्ड्स में जो 138 रन की पारी खेली थी उसके दम पर उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए।

विराट कोहली को बेशक चेज मास्टर कहा जाता हो, लेकिन इस दशक में वनडे प्रारूप में अगर चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं जो बताता है कि उन्होंने कितनी शानदार बल्लेबाज इस दशक में अब तक यानी साल 2020 से की है।

इस दशक में वनडे में चेज करते हुए रोहित के नाम सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा इस दशक में यानी साल 2020 से लेकर अब तक भारत की तरफ से वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। रोहित ने अब तक इस दशक में वनडे में 61 की औसत और 115 की स्ट्राइक रेट के साथ चेज करते हुए कुल 1819 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 54 की औसत और 92 की स्ट्राइक रेट के साथ 1564 रन वनडे में चेज करते हुए बनाए हैं। शुभमन गिल लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने इस दशक में वनडे में चेज करते हुए 57 की औसत और 92 की स्ट्राइक रेट के साथ 1481 रन बनाए हैं जबकि श्रेयस अय्यर ने 41 की औसत के साथ कुल 1200 रन बनाए हैं।

बेथेल घुटने की चोट के कारण 'द हंड्रेड' से बाहर

नई दिल्ली। दाहिने घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल इस साल 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। इस उभरते हुए खिलाड़ी को बर्मिंघम फीनिक्स की कप्तानी का एक अहम मौका नहीं मिल सकेगा। इसी के साथ बेथेल के अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है। बर्मिंघम फीनिक्स ने शुक्रवार को ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ ओपनिंग मैच के लिए बेथेल की जगह साउथ अफ्रीका के डोनोवन फरेरा को कप्तान चुना है। फ्रेंचाइजी बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की फिटनेस पर भी नजर रख रही है, जो हाल ही में इंटरनेशनल ड्यूटी के दौरान लगी चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल हुए हैं। बेथेल भारत के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे। सोमवार सुबह एमआरआई स्कैन के बाद उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बेथेल के फिट होने में लगने वाले समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त को हेडिंग्ले में शुरू होगा। सीरीज के अगले दो मुकाबले 27 अगस्त और 9 सितंबर से खेले जाएंगे। ईसीबी ने एक बयान में कहा, 'जैकब बेथेल दाहिने घुटने की चोट के कारण 'द हंड्रेड' से बाहर हो गए हैं। उन्हें मेट्रो बैंक वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी और कल सुबह उनका एमआरआई स्कैन हुआ था।

दिग्गज शतरंज खिलाड़ी का हंगरी की राष्ट्रपति बनने से इनकार

'देश को एकजुट करने की जिम्मेदारी निभाने की ताकत नहीं'

नई दिल्ली। शतरंज की दिग्गज खिलाड़ी जूडिट पोलगार ने हंगरी की अगली राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। यह फैसला उस घोषणा के एक दिन बाद आया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने कहा था कि वह पोलगार से मिलकर पूछेंगे कि क्या वह यह जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पीटर मैग्यार चाहते थे कि नई हंगरी की संविधान व्यवस्था लागू होने तक जूडिट पोलगार इस पद पर बनी रहें। सोमवार को हुई मुलाकात के बाद जूडिट पोलगार ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने पीटर मैग्यार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। बताया गया कि उनका नामांकन 'हंगरी के सार्वजनिक जीवन की सम्मानित हस्तियों' ने आगे बढ़ाया था।

जूडिट पोलगार ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एक बंटे हुए देश को एकजुट करने जैसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने की ताकत है, इसलिए मैं इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकती।'' जूडिट पोलगार ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, ''मैं अपनी पूरी क्षमता से ऐसे नए, स्वतंत्र और सम्मानित राष्ट्रपति का समर्थन करूंगी, जो इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करें।'' अगर 50 वर्षीय जूडिट पोलगार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेतीं तो उन्हें पीटर मैग्यार की टिस्जा पार्टी का सर्वसम्मत समर्थन मिलता। संसद में इस पार्टी के पास दो-तिहाई बहुमत है। साथ ही, वह संभवतः अपने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली दुनिया की एकमात्र महिला शतरंज खिलाड़ी भी बन जातीं। पीटर मैग्यार ने जूडिट पोलगार के उनके अनुरोध को

ठुकराने के फैसले पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। पीटर मैग्यार ने लिखा, ''मुझे दुख है, लेकिन मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं। हमारे अनुरोध को गंभीरता से लेने के लिए उनका धन्यवाद। उनकी स्पष्टता, बेबाकी और जिस गरिमा के साथ उन्होंने इस पूरे मामले को संभाला, उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूं।'' जूडिट पोलगार को शतरंज इतिहास की सबसे महान महिला खिलाड़ी माना जाता है। वह अब तक की एकमात्र महिला हैं, जिन्होंने विश्व शतरंज रैंकिंग के शीर्ष-10 में जगह बनाई। उन्होंने शतरंज इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंडमास्टर बनने का बॉबी फिशर का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। जूडिट पोलगार ने मुकाबलों में गैरी कास्पारोव और विश्वनाथन आनंद सहित 11 विश्व चैंपियनों को हराया है। वह पांच बार की चेस ओलंपियाड चैंपियन भी हैं और उन्हें हंगेरियन ऑर्डर ऑफ सेंट स्टीफन से सम्मानित किया जा चुका है।

आशीर्वाद ने गुणात्मक परंपरा अभियान के जरिये विश्वकर्मा महाराणा समुदाय को दिया सम्मान

गुवाहाटी, 22 जुलाई। पुरी रथ यात्रा से अपने लंबे जुड़ाव को आगे बढ़ाते हुए, भारत के नंबर 1 पैकेज्ड आटा ब्रांड आशीर्वाद ने गुणात्मक परंपरा अभियान की शुरुआत की है। यह एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव है, जो भगवान जगन्नाथ के पवित्र रथ का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा महाराणा समुदाय की कारीगरी और वर्षों पुरानी परंपरा को सम्मान देता है। गुणात्मक परंपरा, यानी गुणवत्ता की परंपरा, एक ऐसा विचार है, जो पीढ़ियों से चली आ रही शिल्पकला और आशीर्वाद के क्वालिटी की गारंटी के वादे को एक साथ जोड़ता है। ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित यह अनुभव भगवान जगन्नाथ के रथ निर्माण की बारीकियों को करीब से दिखाता है। हर वर्ष विश्वकर्मा महाराणा समुदाय अपनी कुशल कारीगरी से इन पवित्र रथों का निर्माण करता है और इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। गुणवत्ता के प्रति समर्पण ही आशीर्वाद की पहचान है, और यही सोच इस पहल में भी झलकती है। इस अनुभव का मुख्य आकर्षण रथ के पहिये और पारंपरिक पत्थर की चक्की के बीच बनाया गया प्रतीकात्मक संबंध है। जहां रथ का पहिया भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा का प्रतीक है, वहीं चक्की भारतीय परिवारों में गुणवत्ता और पोषण की पहचान रही है। इस अनुभव का उद्घाटन प्रसिद्ध ओड़िया अभिनेत्री एलिना सामंतराय की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने विश्वकर्मा महाराणा समुदाय और श्रद्धालुओं से मुलाकात की तथा इस विशेष अनुभव का हिस्सा बनीं। एलिना सामंतराय ने कहा कि मुझे आशीर्वाद जैसे भरोसेमंद ब्रांड के साथ जुड़कर खुशी हो रही है। गुणात्मक परंपरा सिर्फ ओडिशा की समृद्ध संस्कृति का उत्सव नहीं है, बल्कि विश्वकर्मा महाराणा समुदाय की बेहतरीन कारीगरी को भी सम्मान देती है। ऐसी पहल लोगों को हमारी विरासत से जोड़ने का एक खूबसूरत माध्यम है।

टीवीएस ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व और लाभ किया दर्ज

गुवाहाटी, 22 जुलाई। टीवीएस मोटर कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए अपना अब तक का उच्चतम तिमाही वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें राजस्व में साल-दर-साल 38 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13,896 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 51 प्रतिशत के उछाल के साथ 1,174 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का राजस्व 10,081 करोड़ रुपये था, जबकि पीएटी 776 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 1,779 करोड़ रुपये का अपना अब तक का सबसे अधिक तिमाही एबिटा (ईबीआईटीडीए) भी दर्ज किया, जो एक साल पहले के 1,260 करोड़ रुपये से 41 प्रतिशत अधिक है। जिंस (कमोडिटी) की बढ़ती कीमतों और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद, जिसने इनपुट लागत को बढ़ा दिया था, इसका एबिटा मार्जिन 12.5 प्रतिशत से सुधरकर 12.8 प्रतिशत हो गया। टीवीएस मोटर ने कहा कि उसने चुनिंदा मूल्य संशोधनों, लागत अनुकूलन उपायों और पैमाने की दक्षता के माध्यम से इस प्रभाव की आंशिक रूप से भरपाई की। सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में बिक्री की गति मजबूत बनी रही, जिसमें कुल दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 16.3 लाख यूनिट हो गयी। मोटरसाइकिल की बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 7.4 लाख यूनिट हो गयी, जबकि स्कूटर की बिक्री 36 प्रतिशत बढ़कर 6.8 लाख यूनिट पर पहुंच गयी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 33 प्रतिशत बढ़कर 4.7 लाख यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 86 प्रतिशत बढ़कर 1,29,940 यूनिट हो गयी, जिससे कंपनी का ईवी ग्राहक आधार 10 लाख से अधिक हो गया, और तिपहिया वाहनों की बिक्री 48 प्रतिशत बढ़कर 66,697 यूनिट हो गयी।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बंधन बैंक के बिजनेस में 11 फीसदी की बढ़ोतरी

कोलकाता, 22 जुलाई। बंधन बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित किये। बैंक का कुल कारोबार 11 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। कुल जमा राशि में रिटेल जमा का हिस्सा अब लगभग 74 फीसदी है। वित्त वर्ष 2026-27 में कारोबार में यह बढ़ोतरी बैंक के बढ़ते डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बेहतर परिचालन दक्षता और उत्कर्षता की दिशा में निरंतर प्रयास का परिणाम है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 502 करोड़ रुपये रहा। बंधन बैंक अब भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 35 में लगभग 6,400 बैंकिंग आउटलेट्स के जरिये करीब 3.2 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं देता है। बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 74,500 से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बैंक ने अपने डिपॉजिट बेस में साल-दर-साल 7% की बढ़ोतरी दर्ज की है और अब डिपॉजिट बुक 1.65 लाख करोड़ रुपये की हो गयी है। इसी अवधि में कुल एडवांसेज 1.56 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं। करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट (कासा) का अनुपात 29.4% है। वित्तीय स्थिरता के एक अहम पैमाना माना जाने वाला बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (सीआरएआर) 18.2 प्रतिशत के मजबूत स्तर पर है और रेगुलेटरी सीमा से काफी ऊपर है। बैंक के बेहतर प्रदर्शन पर बात करते हुए, एमडी एवं सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही का हमारा प्रदर्शन बंधन बैंक की मजबूती, हमारी टीमों की प्रतिबद्धता और हमारे शेयरधारकों के हम पर निरंतर बने विश्वास को दर्शाता है। इसी गति को बनाये रखते हुए, हम ग्राहक-केंद्रित तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किये हुए हैं।

इंक. ग्रुप ने दी बड़ी चेतावनी

होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटें जारी रहती हैं तो चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है

नई दिल्ली, एजेंसी। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक. ने बड़ी चेतावनी दी है। उसका कहना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटें जारी रहती हैं तो चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। ऐसी स्थिति की उसे बहुत उम्मीद नहीं है। 20 जुलाई के एक नोट में डान स्ट्रूवेन के नेतृत्व में एनालिस्ट्स ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और फारस की खाड़ी से तेल की सप्लाई में भारी गिरावट ने एक बार फिर क्रूड की कीमतों को बढ़ा दिया है। एनालिस्ट्स ने कहा, 'मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने और फारस की खाड़ी से तेल की सप्लाई के युद्ध-पूर्व स्तर के 45% से भी कम हो जाने के कारण तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं।

टेंशन से फिर बढ़ीं तेल की कीमतें

इस महीने ग्लोबल ऑयल मार्केट पर फिर से दबाव बना है। अमेरिका-ईरान के बीच नई लड़ाई के बाद ब्रेंट की कीमत 91 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई। वहीं, यमन में ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से होने वाली शिपमेंट को रोकने की धमकी दी। चूंकि दूसरी जगहों पर रुकावटें जारी हैं। लिहाजा, फारस की खाड़ी से तेल को ग्लोबल खरीदारों तक पहुंचाने में लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 35 सेंट या 0.4% गिरकर 88.87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। सितंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यह 82.47 डॉलर प्रति बैरल पर रही।

मिडिल ईस्ट पर भारत की निर्भरता काफी ज्यादा

भारत के आर्थिक संबंध सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं हैं। यह क्षेत्र भारत के एक्सपोर्ट का लगभग 17% हिस्सा है। यहां से भारत को लगभग 55% क्रूड ऑयल मिलता है। देश में आने वाले वर्कर रेमिटेंस में इसकी हिस्सेदारी लगभग 38% है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में हर 1 डॉलर की बढ़ोतरी से भारत का सालाना इंपोर्ट बिल लगभग 2 अरब डॉलर बढ़ जाता है।

तेल की कीमतों का आउटलुक

यह चेतावनी फरवरी के अंत में ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के टकराव के कुछ महीनों बाद आई है। उस समय कई एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया था कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई में भारी रुकावट आती है तो ब्रेंट की कीमतें 150 डॉलर या 200 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। इस रास्ते से दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल गुजरता है। हालांकि, ये अनुमान पूरी तरह सच साबित नहीं हुए। ब्रेंट फ्यूचर्स की कीमत लगभग 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। यह 2008 में बने 147 डॉलर के

सोने के भाव 1600 रुपये चढ़े

नईदिल्ली, एजेंसी। सोने-चांदी के भाव में आज भी तेजी नजर आ रही है। एमसीएक्स पर बुधवार, 22 जुलाई 2026 को सोने और चांदी के दामों में जोरदार बढ़त देखी गई। एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव सुबह के कारोबार में 1% से अधिक यानी 1600 रुपये चढ़कर 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गए। वहीं, चांदी के भाव में भी 1% से ज्यादा की तेजी आई और यह 2550 रुपये महंगा होकर 2,26,350 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गया।

पिछले कारोबारी सत्र में एमसीएक्स पर अगस्त सोने के वायदा में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जबकि सितंबर चांदी के वायदा करीब 2.5% की तेजी के साथ बंद हुए थे।

क्यों बढ़ने लगे गोल्ड-सिल्वर के रेट

घरेलू सोने के भाव अमेरिकी बाजार के रुझान से प्रभावित हुए, जहां सोना करीब दो सप्ताह के हाई पर पहुंच गया। हाल ही में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण आई उथल-पुथल के बाद निवेशकों ने कम भाव पर खरीदारी की, जिससे सपोर्ट मिला।

इस संघर्ष ने इस आशंका को फिर से जन्म दिया है कि मुद्रास्फीति काफी बढ़ सकती है, जिससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में कड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सेना ने ईरान पर 11वीं रात भी हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही पिकैक्स माउंटेन के आसपास के इलाके को निशाना बनाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का यह हमला युद्ध को और व्यापक बना देगा।

सोने-चांदी में निवेश करें या दूर रहें

मास्टर कैपिटल सर्विसेज के मुख्य रिसर्च एनालिस्ट रवि सिंह के अनुसार, मजबूत अमेरिकी डॉलर और ऊंचे ट्रेजरी यील्ड के बावजूद, सोने को सपोर्ट मिला हुआ है। इसकी वजह है होर्मुज के पास नए हमले और काला सागर क्षेत्र में लगातार हमलों के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने 28-29 जुलाई की एफओएमसी बैठक से पहले मुद्रास्फीति की चिंताओं को जिंदा रखा है। इस बैठक में निवेशक फेड की नीतिगत घोषणा और चेयरमैन केविन वॉर्श की टिप्पणियों पर गौर करेंगे, ताकि ब्याज दरों की दिशा का पता चल सके।

पीबीपार्टनर्स का पीओएसपी नेटवर्क मॉनसून में परिवारों को दे रहा वित्तीय सुरक्षा का भरोसा

नई दिल्ली, 22 जुलाई। मॉनसून के दौरान बढ़ने वाली मौसमी बीमारियों और इलाज के बढ़ते खर्च के बीच पॉलिसीबाजार के पीओएसपी प्लेटफॉर्म पीबीपार्टनर्स का नेटवर्क देशभर के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूक कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है। विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में पीओएसपी सलाहकार लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य बीमा चुनने में मदद कर रहे हैं। मॉनसून के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल संक्रमण और पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अचानक आने वाले मेडिकल खर्च परिवारों के बजट पर भारी असर डाल सकते हैं। पीबीपार्टनर्स लोगों को पहले से स्वास्थ्य बीमा लेने और वित्तीय रूप से तैयार रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। कंपनी के अनुसार, उसके पीओएसपी सलाहकार स्थानीय भाषा में सरल तरीके से बीमा योजनाओं की जानकारी देते हैं, ग्राहकों की शंकाओं का समाधान करते हैं और उन्हें सही पॉलिसी चुनने में सहायता करते हैं। स्थानीय समुदाय से जुड़े होने के कारण वे लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं और भरोसेमंद मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पीबीपार्टनर्स अपने सलाहकारों को डिजिटल टूल, नियमित प्रशिक्षण और विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे वे ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बेहतर विकल्प सुझा सकें।

निकोटीन पर एफडीए के फैसले के बाद भारत में वैज्ञानिक समीक्षा की मांग तेज

नयी दिल्ली, 22 जुलाई। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) द्वारा नॉन-कंबस्टिबल निकोटीन उत्पादों के लिए मॉडिफाइड रिस्क क्लेम्स को मंजूरी दिये जाने के बाद भारत में भी इस विषय पर वैज्ञानिक मूल्यांकन की मांग तेज हो गयी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को वैश्विक शोध और उपलब्ध आंकड़ों का स्वतंत्र अध्ययन कर यह तय करना चाहिए कि भारतीय परिस्थितियों में ऐसी रणनीतियां कितनी प्रभावी हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार स्वीडन, ब्रिटेन, जापान और नॉर्वे जैसे देशों में नॉन-कंबस्टिबल निकोटीन उत्पादों के इस्तेमाल से पारंपरिक धूम्रपान में कमी दर्ज की गयी है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को किसी भी विदेशी मॉडल को सीधे अपनाने के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अपना स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। सर गंगाराम अस्पताल, नयी दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार एवं पद्मश्री सम्मानित डॉ. मोहसिन वली ने कहा कि आईसीएमआर ने कोविड-19, क्लीनिकल रिसर्च और जीन थेरेपी जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सफल मूल्यांकन किये हैं। उनका मानना है कि निकोटीन और तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में भी इसी तरह का निष्पक्ष वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। वहीं, एम्स के पूर्व प्रोफेसर एवं पद्मश्री सम्मानित डॉ. चंद्रकांत एस पांडव ने कहा कि अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि व्यस्कों के लिए मॉडिफाइड रिस्क क्लेम्स की अनुमति मिलने के बावजूद युवाओं में तंबाकू और ई-सिगरेट के उपयोग में लगातार गिरावट आयी है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समीक्षा का उद्देश्य किसी उत्पाद को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उसके प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होना चाहिए।

दुनिया इसके बारे में क्यों नहीं जान सकती', इंजीनियर ने पकड़ी करछी, कुछ ही महीनों में कमा डाले 15 लाख

नई दिल्ली, एजेंसी। यह कहानी है आदम फरीदी की। वह कश्मीर के रहने वाले हैं। उनके पास कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री है। लेकिन, नौकरी करने के बजाय उन्होंने करछी पकड़ने का फैसला किया। आदम फरीदी ने एक सफल फूड स्टार्टअप की नींव रख दी है। इसका नाम 'वाजारू फूड्स' है। यह कश्मीरी वजवान को घर-घर तक पहुंचाने में लगा है। इस डी2सी ब्रांड ने कुछ ही महीनों में 15 लाख रुपये का रेवेन्यू हासिल कर लिया है। आइए, यहां आदम फरीदी की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

आदम फरीदी श्रीनगर में पले-बढ़े। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। उनका संबंध किसी होटल या रेस्तरां बैकग्राउंड वाले परिवार से नहीं था। जब वह कश्मीर से दूर रहे तब उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि सदियों पुरानी कश्मीरी वजवान संस्कृति से बाहर के लोग अनजान हैं। बाहर मिलने वाले कश्मीरी खाने में न तो ऑथेंटिक मसाले होते थे। न ही पारंपरिक तकनीक। इस कमी और बिना सप्लाई चेन वाले बाजार को देखकर आदम फरीदी ने श्रीनगर के जाकुरा में बसकर 2025 में अपने स्टार्टअप की नींव रखी। इस सफर में उनकी फैमिली फ्रेंड नजीरा अख्तर को-फाउंडर के रूप में जुड़ीं। आदम फरीदी के लिए स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में छोटे ऑर्डर के लिए सप्लायरों को मनाना मुश्किल साबित हुआ। इसके अलावा, श्रीनगर में फ्रोजन मीट को लेकर फैली नकारात्मक खबरों के बीच ग्राहकों का विश्वास जीतना बड़ी चुनौती बनी। आदम ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। उपभोक्ताओं को सही तरीके से फ्रीज किए गए फूड आइटम्स की क्वालिटी के प्रति जागरूक किया। बिना किसी प्रिजर्वेटिव या मिलावट के हाथों से पके खाने को सीधे एयरटाइट पैक में बंद कर कोल्ड-चेन तकनीक के जरिये श्रीनगर से दिल्ली पहुंचाना शुरू किया। स्टार्टअप ने अपने मेनू की शुरुआत कश्मीरी वजवान की सबसे लोकप्रिय डिश 'रिस्ते' से की। धीरे-धीरे ग्राहकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद मेनू में और कई व्यंजन जोड़े गए। स्टार्टअप ने किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के बजाय अपनी वेबसाइट के जरिये बिक्री को प्राथमिकता दी। मकसद था- ग्राहकों को सीधे क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाना। स्टार्टअप ने एफएसएसएआई लाइसेंस जैसी प्रक्रियाओं को शुरुआत से ही अपनाया ताकि ग्राहकों के बीच भरोसा बना रहे। आदम फरीदी ने इस स्टार्टअप को बिना किसी बाहरी निवेश के अपनी बचत से शुरू किया।

बंधन बैंक में भूचाल! 1 दिन में 15% से ज्यादा टूटे शेयर, रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज ने भी घटाई रेटिंग

नईदिल्ली, एजेंसी। प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंकों में शामिल बंधन बैंक के शेयरों में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद बैंक का शेयर 22 जुलाई को कारोबार के दौरान करीब 15% से ज्यादा लुढ़क गया, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा। दिलचस्प बात यह है कि इस साल अब तक शेयर करीब 44% चढ़ चुका था, लेकिन तिमाही नतीजों और बैंक प्रबंधन की भविष्य की कमजोर कमाई ने बाजार का मूड पूरी तरह बदल दिया। ब्रोकरेज हाउसों ने भी बैंक के प्रदर्शन को लेकर सतर्क रुख अपनाया है, जिसके चलते शेयर पर दबाव और बढ़ गया। दरअसल, बैंक के तिमाही नतीजों के बाद हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रबंधन ने सबसे बड़ा झटका रिटर्न ऑन एसेट्स के अनुमान में कटौती करके दिया। पहले बैंक को उम्मीद थी कि आने वाले समय में ऋस्ट 1.6% से 1.8% के बीच रहेगा, लेकिन अब इसे घटाकर 1.2% से 1.4% कर दिया गया है, यानी बैंक खुद मान रहा है कि आने वाले समय में उसकी कमाई की क्षमता पहले की तुलना में कमजोर रह सकती है। यही कारण रहा कि निवेशकों ने शेयरों में तेजी से बिकवाली शुरू कर दी। बंधन बैंक ने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जमा जुटाने की बढ़ती लागत है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक ने सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इससे बैंक को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जिसका असर उसकी कमाई पर पड़ सकता है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मानसून की स्थिति, बढ़ती टेक्नोलॉजी लागत और सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम भी बैंक ने गिनाए हैं।

जेपी मॉर्गन की रेटिंग: दूसरी ओर ग्लोबल ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने भी बैंक पर रेटिंग बनाए रखी है और 175 का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि बैंक द्वारा ऋस्ट और लोन ग्रोथ गाइडेंस में की गई कटौती निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता है। बैंक ने अब लोन ग्रोथ का अनुमान भी 14-15% की रेंज के निचले स्तर पर रहने की बात कही है।

मोतीलाल ओसवाल का अनुमान

इन्हीं चिंताओं को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपने अनुमान घटा दिए हैं। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए बैंक की कमाई का अनुमान क्रमशः 14% और 6% कम कर दिया है। साथ ही शेयर की रेटिंग से घटाकर ' ।।न्यूट्रल ' कर दी है। हालांकि, उसने 225 का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है, जो मौजूदा स्तर से कुछ बढ़त की संभावना दिखाता है। अनिश्चित मानसून को देखते हुए उसने कर्ज वितरण की रफ्तार जानबूझकर धीमी रखने का फैसला किया है।

भारत ने पीछे खींचे हाथ, इराकी तेल उठाने का प्लान किया कैंसिल

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) ने बसरा ऑयल टर्मिनल से इराकी तेल उठाने का अपना प्लान रद्द कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर हमलों और बढ़ते जोखिम के कारण ऐसा किया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है। सरकारी कंपनी 23 जुलाई के आसपास 'लीला जामनगर' नाम के बहुत बड़े क्रूड कैरियर में 20 लाख बैरल इराकी तेल लिफ्ट करने की तैयारी कर रही थी।

सूत्रों ने बताया कि एक और सरकारी रिफाइनर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने भी भारतीय झंडे वाले अफ्रामैक्स टैंकर 'देश गौरव' में इराक से तेल उठाने का प्लान रद्द कर दिया। इन दोनों भारतीय रिफाइनरों ने रॉयटर्स के कमेंट के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया।

भारत ने जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती करने वाली कंपनियों को सलाह दी है कि वे देश के नाविकों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर तैनात न करें। कारण है कि इस इलाके में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। शिपिंग रेगुलेटर ने जहाजों के कैप्टन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि वे फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा हालात को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें। साथ ही नेविगेशन से जुड़ी चेतावनियों पर

लगातार नजर रखें। ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज स्ट्रेट संघर्ष शुरू होने से पहले दुनिया की कुल एनर्जी सप्लाई के लगभग पांचवें हिस्से के लिए मुख्य रास्ता था। जुलाई की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच हुई कमजोर युद्धविराम संधि टूट गई। इसके बाद से तनाव बढ़ गया है। इससे दोनों पक्षों के बीच हमले फिर से शुरू हो गए हैं। इस समुद्री रास्ते से होने वाली शिपिंग में और रुकावट आ रही है।

मौनी संग डेटिंग की अफवाहों पर भड़के अर्जुन

हाल ही में अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे डिनर के बाद साथ निकलते दिखे। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं। अर्जुन ने इन अफवाहों के लिए एक पपराजी पेज के भ्रामक कैप्शन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी दोस्ती को सिर्फ एक हेडलाइन के लिए गॉसिप बना दिया गया। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की कि खबर छापने से पहले फैक्ट चेक जरूर करें।

अर्जुन बिजलानी ने कहा, प्रिय क्लिकबेट पेजेज, दो लोग जो 15 साल से दोस्त हैं, वे अचानक कपल नहीं बन जाते सिर्फ इसलिए कि किसी गॉसिप पेज को हेडलाइन चाहिए। कभी-कभी लोग एक-दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उनका दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है।

हर दोस्ती को रोमांटिक एंगल देना जरूरी नहीं है, सिर्फ व्यूज के लिए। कुछ भी पब्लिश करने से पहले थोड़ा फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी बनाई कहानियों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

इसके बाद उन्होंने मीडिया पेज से सीधे तौर पर अपील भी की। हम मीडिया पेज से अनुरोध करते हैं कि भ्रामक खबरें फैलाने से पहले सच्चाई की जांच करें, जो लोगों की निजी जिंदगी में बेवजह दखल देती हैं और कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। जिम्मेदार पत्रकारिता भरोसा बनाती है, क्लिकबेट नहीं।

अर्जुन और मौनी पिछले 15 साल से एक-दूसरे को जानते हैं और कई बार अपनी दोस्ती के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। दोनों ने *नागिन* सीरियल में साथ काम किया था, जिसके बाद उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली।

फिर दस्तक देगी फिल्म 3 इडियट्स

मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के जन्मदिन के अवसर पर बीते साल आयोजित एक फेस्टिवल में फैंस को उनकी कुछ चर्चित फिल्में दोबारा देखने का मौका मिला। हालांकि, उस लिस्ट में उनकी चर्चित और हिट फिल्म *3 इडियट्स* शामिल नहीं थी। अब ऐसी खबर है कि साल 2009 में आई यह ब्लॉकबस्टर फिल्म री-रिलीज होने वाली है।

राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म *3 इडियट्स* की री-रिलीज की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर में यह सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। अपनी मूल रिलीज के करीब 17 साल बाद *3 इडियट्स* री-रिलीज हो रही है। अपनी रणनीतिक योजनाओं के तहत एनएच स्टूडियोज 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर फिल्म *3 इडियट्स* को बड़े पैमाने पर फिर से रिलीज करने जा रहा है।

देखो हंस न देना.....

शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया। एक बच्चा ये देख रहा था, *उसने अपने पिता से पूछा :* ये हाथ क्यों मिला रहे हैं?
पिता : बेटा, पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं।

डॉक्टर : जिस तरह अपने प्रेमी को देखती हो, उसी तरह देखना।
खूबसूरत लड़की : पर क्यों?
डॉक्टर : आई ड्राप डालना है।

डिमेंशिया का खतरा 45% तक कम करता है व्यायाम

आंकड़े बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ दिमागी क्षमता शिथिल पड़ने लगती है, यही से डिमेंशिया जैसे खतरों की शुरुआत होती है। एक अनुमान है कि 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके 88 लाख भारतीय डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं और भारतीय बुजुर्गों में इसकी व्यापकता 7.4 प्रतिशत तक हो चुकी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू-एचओ) के एक हालिया दिशा-निर्देश बताता है कि दिनचर्या में सुधार करने, शारीरिक सक्रियता बढ़ाने और धूमपान, डायबिटीज व उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने से डिमेंशिया के खतरों को 45 प्रतिशत तक टाला जा सकता है।

जीवनकाल का मध्यान्ह शारीरिक और मानसिक सक्रियता का ढलान होता है और यही वह समय होता है, जब ज्यादातर लोग क्षीण होती क्षमताओं को सक्रियता के जरिये थामने के बजाय उसे टालने लगते हैं।

एक हालिया अमेरिकी शोध बताता है कि अगर जीवन में फिटनेस को लेकर अनुशासन बना रहे तो दिमाग भी सेहतमंद बना रहता है। शोध की मानें तो 35 से 55 वर्ष आयु वर्ग में बढ़ाई गई शारीरिक सक्रियता आने वाले वर्षों में दिमाग की सेहत को बेहतर बनाए रखती है।

मन में डर आता है : शहनाज

शहनाज गिल ने हाल ही में लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि इसे लेकर मन में एक डर आता है।

जब शहनाज से पूछा गया कि क्या दूर रहने से प्यार बढ़ता है या कम हो जाता है? इस पर उन्होंने कहा, जब दो लोग एक-दूसरे से दूर होते हैं, तो प्यार और पार्टनर की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक डर भी मन में आता है कि सामने वाला इंसान पीठ पीछे क्या कर रहा होगा। इसलिए दूरी से शक भी बढ़ जाता है।

शहनाज ने कहा, मेरा मानना है कि अगर प्यार सच्चा हो और पार्टनर पास हो, तो रिश्ते में किसी दूरी की जरूरत नहीं होती। जब शहनाज से पूछा गया कि आज के डेटिंग ऐप्स के जमाने में क्या ऐसा सच्चा प्यार मुमकिन है?

तो उन्होंने कहा कि प्यार किसी भी तरह का हो, चाहे पुराने जमाने का या आज के दौर का बस दिल में सच्चा प्यार होना चाहिए। फिल्म *इश्कनामा* एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है। यह फिल्म *निम्मा* और *नसीमा* नाम के दो प्रेमियों की असल जिंदगी की कहानी है। इसकी कहानी 1981 से 1988 के बीच भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के आस-पास की है, जो प्यार, उनके त्याग और मजबूरी में अलग होने के दर्द को दिखाती है।

फिल्म *इश्कनामा, हिंद पाक बॉर्डरनामा* नाम की किताब पर बनी बताई जा रही है। इस फिल्म में शहनाज गिल के साथ जय रंधावा और सौरभ सचदेवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अरविंद एस. खैरा हैं। फिल्म का म्यूजिक बी प्राक ने दिया है और गाने जानी ने लिखे हैं। यह फिल्म 24 जुलाई को भारत, कनाडा और यूके समेत दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बारिश के मौसम में डेंगू-मलेरिया समेत कई बीमारियों से रहें सुरक्षित

देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं यह अपने साथ कई मौसमी बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है। इस दौरान नमी बढ़ने से बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और पेट संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में केवल बारिश का आनंद लेना ही नहीं, बल्कि अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप मानसून में होने वाली कई बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं बारिश के मौसम में किन जरूरी हेल्थ टिप्स को अपनाकर आप पूरे सीजन स्वस्थ और फिट रह सकते हैं :

-बारिश के मौसम में पानी दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं। बाहर का खुला पानी पीने से पेट के संक्रमण, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

-मानसून में बासी, खुला और स्ट्रीट फूड खाने से बचें। घर का ताजा और गर्म भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम रहता है।

-अपने आहार में विटामिन-सी से भरपूर फल, हरी सब्जियां, हल्दी, अदरक, लहसुन और दही जैसी चीजें शामिल करें। ये शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं।

-खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। इससे बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण कम होता है।

-बारिश के दौरान घर के आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरदानी, रिपेलेंट और पूरी बाजू के कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके।

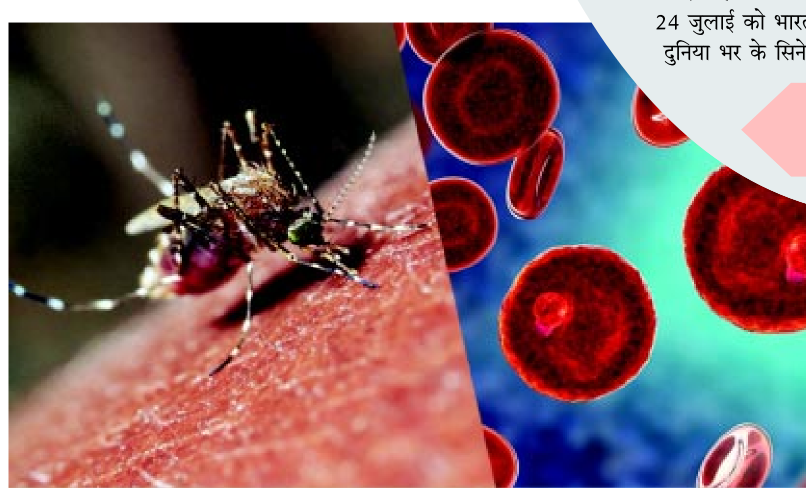

-बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े लंबे समय तक न पहनें। इससे सर्दी-जुकाम, फंगल इंफेक्शन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

-हल्की एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम शरीर को सक्रिय रखते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

-रोजाना 78 घंटे की अच्छी नींद लेने से शरीर तेजी से रिकवर होता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

-घर, रसोई और बाथरूम को साफ रखें। गंदगी और नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगस तेजी से फैल सकते हैं।

-यदि तेज बुखार, लगातार उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द या सांस लेने में परेशानी हो, तो घरेलू इलाज पर निर्भर न रहें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।

काजल ने बताया साउथ-बॉलीवुड के अंदर का सच

काजल अग्रवाल पिछले दो दशकों से साउथ से लेकर बॉलीवुड में काम कर रही हैं। उन्होंने दोनों इंडस्ट्री में कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। ऐसे में वह दोनों इंडस्ट्री के कामकाज और स्टार्स के बिहेवयर पर रिएक्ट करती हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने एक्ट्रेस के *ऑब्जेक्टिफिकेशन* और सलमान खान की लेट-लतीफी पर रिएक्ट किया।

इंटरव्यू में काजल अग्रवाल ने साउथ और बॉलीवुड के रवैये पर भी बात की। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड को दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री से समय की कीमत करना सीखना चाहिए। साउथ में समय की काफी वैल्यू है। हर काम घड़ी देखकर होता है लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है।

जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन-सा स्टार है जिन्होंने काजल अग्रवाल को सबसे ज्यादा इंतजार करवाया तो काजल अग्रवाल ने तुरंत सलमान खान का नाम लिया। सिकंदर में सलमान खान के साथ काम कर चुकीं काजल ने बताया कि सलमान खान उनके हमेशा से ही क्रश रहे हैं। वह उनके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड भी थीं।

काजल अग्रवाल ने कहा, सलमान खान ने मुझे सबसे ज्यादा इंतजार करवाया है। मैं साउथ से काम करके आई हूं। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं थी। मैं बस सेट पर बैठकर सोचा करती थी आखिर अब क्या होगा। वह कभी दिन में आते तो कभी शाम में। ऐसे में मैं जिम में जाकर एक्सरसाइज किया करती थी। मैं साउथ सिनेमा की अनुशासन और समय की पाबंद हूं।

काजल अग्रवाल ने साउथ सिनेमा में बदले दौर की बात की। उन्होंने बताया कि अब वहां कामकाज के तौर तरीके में बदलाव हो रहा है। नाभि वाली दौर खत्म हो चुका है। महिला आधारित फिल्में भी बन रही हैं। मैंने हमेशा ही ऐसे काम के लिए साफ मना किया है। मैंने खुद कहा था कि मेरी नाभि पर फल मत फेंको बॉस।

काजल अग्रवाल ने हाल में ही बोल्ड सीन्स पर भी रिएक्ट किया था। एक पॉडकास्ट में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह अक्सर बोल्ड सीन से दूर रहती है, जिस चीज में वह कंफर्टेबल नहीं होती, वह नहीं करतीं।

काजल अग्रवाल के एक्टिंग डेब्यू की बात करें तो साल 2004 में उन्होंने *क्यों...! हो गया ना* से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था लेकिन बॉलीवुड में उन्हें उस कद्र सफलता नहीं मिली लेकिन साउथ में उन्होंने अपना नाम बनाया।

नमस्कार अपर असम

प्रातः खबर

गुरुवार, 23 जुलाई 2026

मौसम स्थान	अधिकतम	न्यूनतम
जोरहाट	30°	19°
डिब्रूगढ़	29°	17°
तिनसुकिया	30°	18°
शिवसागर	30°	19°

मार्घेरिटा राजस्व सर्किल में जनगणना शुरु

संवाददाता

जागुन, 22 जुलाई। जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत मार्घेरिटा राजस्व सर्किल में 22 जुलाई से प्रगणकों (एन्यूमरेटर) और पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) का प्रशिक्षण शुरू होगा। सर्किल अधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित यह प्रशिक्षण 4 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर तैनात कर्मियों को जनगणना की प्रक्रिया, आंकड़ा संग्रहण और डिजिटल प्रणाली के संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर आगामी जनगणना को त्रुटिरहित एवं प्रभावी बनाना है। प्रशासन के अनुसार, कुल 922 प्रशिक्षुओं को 19 बैचों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

Ph. : 2548109 2730431
L. GOPAL JEWELLERS
9-11-14, Kuber A.C. Market
Guwahati - 781001
शुद्ध चांदी के बर्तनों एवं शुद्ध चांदी की सिल्ली व चांदी के सिक्कों का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान
22/22 KDM Gold Jewellery, Hallmark Gold Jewellery Branded Diamond Jewellery, Platinum & Silver Utensils & Articles

0361-2601385
9678211156
D. M. Jeweller's
(As You Like We are)
7/8 (L) Akram's Business Fancy Bazar, Guwahati-1
शुद्ध सील चांदी के बर्तन एवं असली सिक्कों का प्रतिष्ठित स्थान
We also deal in 22/22 KDM hallmark Jewelleries

जोरहाट में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने लिया बाढ़ का जायजा

खबर संवाददाता

जोरहाट, 22 जुलाई। जोरहाट सहित कई जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा आज बुधवार को ऊपरी असम पहुंचे। उन्होंने सुबह चराईदेव, नाजिरा और शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद दोपहर में जोरहाट जिले का दौरा किया। जोरहाट पहुंचकर मुख्यमंत्री सबसे पहले मरियानी विधानसभा क्षेत्र के नामसेसु जनता हाई स्कूल में स्थापित अस्थायी राहत शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रशासन को राहत शिविरों तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिविर में रह रहे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री जोरहाट विधानसभा क्षेत्र के बोरीगांव पहुंचे और भोगदोई नदी के तटबंध के क्षतिग्रस्त हिस्सों तथा बाढ़ से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। यहां मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश पुल का जायजा लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री टियोक विधानसभा क्षेत्र के शालमरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की और भोगदोई नदी से हुए नुकसान का निरीक्षण कर शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊपरी असम में आई यह बाढ़ अभूतपूर्व है और इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों का हाल जानने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए वे स्वयं क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार संकट की इस घड़ी में जनता के साथ है और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन निर्माण के दौरान जल निकासी व्यवस्था में खामियों को बाढ़ का प्रमुख कारण बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग से जल्द चर्चा कर जल निकासी व्यवस्था को वैज्ञानिक ढंग से सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे। बाढ़ से प्रभावित किसानों के सामने धान के पौधों की कमी की आशंका पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बाढ़ से अप्रभावित क्षेत्रों से धान का पौधा लाकर किसानों में वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जिन क्षेत्रों में सामान्यत: बाढ़ आती है, वहां बाढ़ नहीं आई, जबकि अन्य क्षेत्रों में अप्रत्याशित स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की रोकथाम के लिए पहले समस्या के वास्तविक कारणों का पता लगाना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने में कुछ समय लगेगा और मृतकों की सही संख्या भी कुछ दिनों बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को सरकार की ओर से पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राजस्व मंत्री केशव महंत, महिला व बाल कल्याण मंत्री मंत्री अजंता नेउग, मरियानी के विधायक रूपज्योति कुर्मी, टियोक के विधायक विकास सैकिया, जिला आयुक्त जय शिवानी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बूढ़ीदिहिंग का रौद्र रूप, कटाव की जद में कथा काखरनी गांव

संवाददाता

जागुन, 22 जुलाई। तिनसुकिया जिले के 83 नंबर मार्घेरिटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जागुन के कथा काखरनी गांव में बूढ़ीदिहिंग नदी का भीषण कटाव अब ग्रामीणों के लिए भय का पर्याय बन गया है। नदी का लगातार बढ़ता कटाव गांव की सड़कों, कृषि भूमि, आजीविका के साधनों तथा कथा काखरनी आरक्षित वन क्षेत्र की हजारों बीघा भूमि और बहुमूल्य वृक्षों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। सबसे अधिक खतरा गांव की करीब दो किलोमीटर लंबी मुख्य संपर्क सड़क पर मंडरा रहा है। सड़क के कई हिस्सों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और किसी भी समय इसका बड़ा भाग नदी में समा सकता है। यही मार्ग गांव के सैकड़ों परिवारों के आवागमन का एकमात्र सहारा है। यदि यह सड़क कटाव की भेंट चढ़ती है, तो पूरा गांव बाहरी दुनिया से कट सकता है। कटाव के कारण स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों, गर्भवती महिलाओं, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एंबुलेंस, किसानों और व्यापारियों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और हर बारिश के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से बूढ़ीदिहिंग नदी का कटाव गांव के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है, लेकिन अब तक न तो स्थायी तटबंध का निर्माण किया गया और न ही कोई प्रभावी कटाव-रोधी योजना लागू की गई। सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से केवल आश्वासन ही मिले हैं। ग्रामीणों के अनुसार, कटाव की वजह से कई हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि पहले ही नदी में समा चुकी है, जिससे अनेक परिवारों की आजीविका पर संकट गहरा गया है। अब लोगों को डर है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो मुख्य सड़क के साथ-साथ गांव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। गांववासियों ने असम सरकार, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल स्थायी तटबंध का निर्माण कर प्रभावी कटाव-रोधी उपाय शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बूढ़ीदिहिंग नदी का यह रौद्र रूप आने वाले दिनों में और बड़ी तबाही का कारण बन सकता है।

डिब्रूगढ़ में शिवाया एलीट बस पर कथित पथराव से दहशत

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 22 जुलाई। डिब्रूगढ़ में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब शिवाया एलीट स्लीपर बस पर कथित रूप से पथराव किया गया। प्रत्यक्षदर्शी यात्री के अनुसार, रात करीब 10:35 बजे चाउलखोवा बाइपास के पास चलती बस पर पत्थरों और बोल्डरों से हमला किया गया, जिससे बस की कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि, देर रात तक किसी यात्री या बस कर्मी के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, पूरे घटनाक्रम की शुरुआत डिब्रूगढ़ के मुरलीधर जालान बस टर्मिनल (एमजेबीटी) परिसर में हुई। बताया गया कि बस टर्मिनल के भीतर मुड़ रही थी, तभी एक ई-रिक्शा से उसकी टक्कर हो गई। इसके बाद ई-रिक्शा चालक और बस कर्मचारियों के बीच तीखी कहासुनी हुई। इसके पश्चात बस अपने निर्धारित मार्ग पर रवाना हो गई। यात्री का दावा है कि जैसे ही बस डिब्रूगढ़ के एमजेबीटी से चाउलखोवा बाइपास की ओर बढ़ी, कुछ स्थानीय लोगों ने रास्ते में बस को रोकने का प्रयास किया और उस पर पथराव शुरू कर दिया। चलती बस पर लगातार पत्थर फेंके जाने से कई खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। बस के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए सीटों के नीचे झुक गए। प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद कुछ युवक मोटरसाइकिलों पर बस का पीछा करते रहे, जिससे यात्रियों में भय और बढ़ गया। यात्रियों द्वारा साझा की गई तस्वीरों में बस के भीतर टूटे हुए कांच बिखरे दिखाई दे रहे हैं, जो कथित पथराव से हुए नुकसान की ओर इशारा करते हैं।

दुमदुमा आंचलिक छात्र संस्था का विशेष अभिनंदन समारोह, 600 से ज्यादा छात्रों को किया गया सम्मानित

संवाददाता

दुमदुमा, 22 जुलाई। अखिल असम छात्र संस्था की दुमदुमा आंचलिक समिति के सौजन्य से दुमदुमा में उच्च और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। दुमदुमा नगर खेल मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में आसू के अध्यक्ष उत्पल शर्मा सहित जिला छात्र संस्था के पदाधिकारियों के साथ-साथ अंचल के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अंचल के लगभग छह सौ से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उत्तीर्ण प्रत्येक छात्र-छात्राओं को एक-एक अभिनन्दन पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपने वक्तव्य में उत्पल शर्मा ने राज्य में बाढ़ की विभीषिका के बीच भी विधानसभा सत्र जारी रखने पर आलोचना की। पत्रकारों के साथ बातचीत में आसू अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने राज्य की हालिया बाढ़ स्थिति पर अपनी टिप्पणी की। उत्पल शर्मा ने सरकार से बचाव अभियान और राहत सामग्री वितरण में तेजी लाने की मांग की। राज्य में बाढ़ की विभीषिका के बीच भी विधानसभा सत्र जारी रखने के कदम की उत्पल शर्मा ने आलोचना की।

तिनसुकिया में 55 अनुसूचित जाति स्वयं सहायता समूहों और 3 व्यक्तिगत लाभार्थियों को पीएम-अजय योजना के तहत अनुदान वित्तिय सहायता का वितरित

खबर संवाददाता

तिनसुकिया, 22 जुलाई। असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तिनसुकिया ने जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तिनसुकिया के सहयोग से बुधवार को तिनसुकिया कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुदान वित्तिय सहायता वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर 55 अनुसूचित जाति (एससी) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा 3 व्यक्तिगत अनुसूचित जाति लाभार्थियों को आजीविका एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए अनुदान सहायता के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य अनुसूचित जाति परिवारों में उद्यमिता को बढ़ावा देना, सतत आजीविका को सशक्त बनाना तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त, तिनसुकिया, स्थानीय विधायकों के प्रतिनिधि, जिला परिषद तिनसुकिया के अध्यक्ष, विभिन्न आंचलिक पंचायतों के अध्यक्ष, उपखंड समाज कल्याण कार्यालय, कृषि विभाग, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, सिंचाई विभाग, एपीडीसीएल, डीआईपीआरओ तथा एएसआरएलएम के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा मीडिया प्रतिनिधियों तथा लाभार्थी स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने लाभार्थियों से अपील की कि वे अनुदान राशि का उपयोग केवल स्वीकृत आजीविका गतिविधियों के लिए ही करें, ताकि इससे स्थायी आय सृजित हो और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत हो। उन्होंने लाभार्थियों को व्यवहारिक एवं सफल उद्यम स्थापित करने तथा दीर्घकालिक आजीविका संवर्धन के लिए इस सहायता का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में एएसआरएलएम ने जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे पात्र परिवारों तक पीएम-अजय योजना की जानकारी पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक योग्य लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। बताया गया कि वे अनुसूचित जाति सदस्य, जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं, बैंक ऋण प्राप्त कर चुके हैं तथा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, इस योजना के तहत अनुदान सहायता के पात्र हैं। जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता से योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंच सकेगा। एएसआरएलएम के जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) ने बताया कि अनुदान राशि के उपयोग की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हो। एएसआरएलएम के सामुदायिक कार्यकर्ता लाभार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तथा उनके उद्यमों की प्रगति पर नजर रखेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयूए) के अंतर्गत मासिक निगरानी के दौरान घर-घर जाकर भी अनुदान के उपयोग का सत्यापन किया जाएगा। यह समन्वित निगरानी व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ लाभार्थियों को सफल एवं स्थायी आजीविका स्थापित करने में सहायता करेगी। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर एएसआरएलएम एवं जिला अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, तिनसुकिया ने पीएम-अजय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के समावेशी विकास, सतत आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

निर्माण कार्य के दौरान नाले की खुदाई के दौरान शनि मंदिर की दीवार गिरी

मन्दिर के पुजारी ने मंदिर के दीवार के शीघ्र पुनर्निर्माण की मांग

खबर संवाददाता

तिनसुकिया, 22 जुलाई। तिनसुकिया शहर के लॉ कॉलेज रोड स्थित श्रीश्री सार्वजनिक शनि मंदिर से सटे नाले के निर्माण कार्य के दौरान बुधवार को मंदिर की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई श्रद्धालु या राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मंदिर के पुजारी एवं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंदिर के समीप नाले के निर्माण कार्य हेतु जेसीबी से नाले की खुदाई का कार्य चल रहा था। खुदाई के दौरान अचानक मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त होकर ढह गई। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई और स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य के तरीको पर नाराजगी जताई। मंदिर के पुजारी के अनुसार नाले की खुदाई के दौरान सावधानी नही बरतने तथा सुरक्षा मानकों का समुचित पालन नहीं किए जाने के कारण यह घटना हुई। उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य आवश्यक सावधानी और तकनीकी मानकों के अनुरूप किया जाता, तो मंदिर की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचता। उन्होंने क्षतिग्रस्त दीवार का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो मंदिर की अन्य संरचनाओं को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन एवं संबंधित विभाग से धार्मिक स्थलों के आसपास निर्माण कार्य करते समय विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

शांतिपाड़ा, खलिहामारी, जेल रोड समेत डिब्रूगढ़ के निचले इलाकों में जलभराव

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ 22 जुलाई। लगातार बारिश के बीच डिब्रूगढ़ शहर के शांतिपाड़ा, खलिहामारी, जेल रोड तथा अन्य निचले इलाकों में कृत्रिम जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न होने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस एवं डिब्रूगढ़ नगर निगम (डीएमसी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर जमा पानी, जलनिकासी व्यवस्था तथा राहत उपायों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि शहर के कई निचले इलाकों में भारी मात्रा में पानी जमा होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई सड़कों पर आवागमन बाधित रहा, जबकि स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने जलभराव वाले स्थानों से पानी की शीघ्र निकासी के लिए पंपिंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संयुक्त निरीक्षण में डिब्रूगढ़ नगर निगम के महापौर सैकत पात्रा, नगर आयुक्त नवास दास, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा जलभराव के कारणों का आकलन किया। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी जलनिकासी व्यवस्था विकसित करने पर भी चर्चा की गई। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में जलनिकासी तंत्र को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से खलिहामारी और जेल रोड क्षेत्र में पुराने ड्रेनेज ढांचे के उन्नयन की प्रक्रिया जारी है, जिससे बरसात के दौरान पानी का बहाव बेहतर हो सके। जिला प्रशासन ने कहा कि डिब्रूगढ़ के सभी प्रभावित निचले क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलभराव वाले मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचें, प्रशासन द्वारा जारी यातायात सलाह का पालन करें तथा राहत एवं जलनिकासी कार्यों में सहयोग करें।

जिला में जनगणना 2027 के प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्रारंभ

संवाददाता

मार्घेरिटा, 22 जुलाई। मार्घेरिटा राजस्व सर्किल के सर्किल अधिकारी कार्यालय के तत्वावधान में जनगणना 2027 के प्रगणकों () एवं पर्यवेक्षकों () के प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम दिवस आज मार्घेरिटा कॉलेज में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन अनुभवी फील्ड प्रशिक्षकों की टीम द्वारा किया गया, जिसमें श्री प्रदीप चंद्र दास, डॉ. कनाई दास, श्री सूरज हाजोंग, डॉ. अभिजीत महंता, डॉ. बिनोद चेत्री, डॉ. कौस्तव मणि नाथ, श्री नोबल किशोर बरूआगोहाईं, श्री लाटुमोनी गोगोई, श्री प्रवीरज्योति बोरा तथा श्री मृदुल दोहुतिया शामिल थे। प्रशिक्षण के दौरान प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को जनगणना की मूल अवधारणाओं, क्षेत्रीय कार्य-प्रक्रियाओं, डेटा संग्रहण की कार्यप्रणाली तथा सटीक, व्यापक और उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़ों के संकलन के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग से परिचित कराया गया। प्रतिभागियों को उनकी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों, नैतिक मानकों तथा जनगणना प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के महत्व के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, ताकि प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को जनगणना 2027 के सुचारु, सटीक एवं प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित किया जा सके।

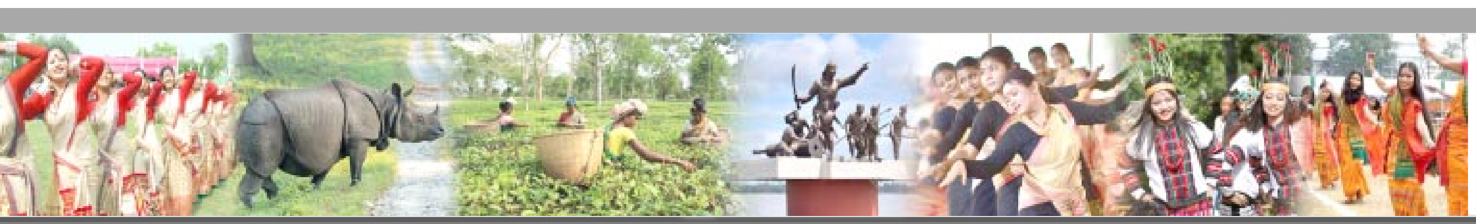

प्रातः खबर
गुरुवार, 23 जुलाई 2026

बाढ़ संकट के बीच डिब्रूगढ़ की हवाई यात्रा महंगी
गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ उड़ान का किराया 17 हजार के पार

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 22 जुलाई। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच डिब्रूगढ़ आने-जाने वाले यात्रियों को अब हवाई यात्रा के लिए भी भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। सड़क और रेल संपर्क कई स्थानों पर प्रभावित होने के कारण बड़ी संख्या में लोग हवाई यात्रा का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर साझा किए गए स्क्रीनशॉट और यात्रियों के दावों के अनुसार, गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ मार्ग पर कुछ उड़ानों का किराया बढ़कर 17 हजार से अधिक पहुंच गया है, जिससे यात्रियों में व्यापक नाराजगी देखी जा रही है। यात्रियों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के समय, जब लोगों के पास यात्रा के सीमित विकल्प रह जाते हैं, तब हवाई किराए में इतनी अधिक वृद्धि उचित नहीं है। विशेष रूप से मरीजों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए इतनी महंगी हवाई यात्रा करना कठिन हो गया है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि संकट की इस घड़ी में एयरलाइंस यात्रियों की मजबूरी का लाभ उठा रही हैं। हालांकि, एयरलाइंस कंपनियों की ओर से किराया बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। विमानन क्षेत्र में डायनेमिक प्राइसिंग प्रणाली लागू होती है, जिसके तहत मांग बढ़ने और सीटों की उपलब्धता कम होने पर किराए स्वतः बढ़ जाते हैं। फिर भी आपदा की स्थिति में इतनी अधिक कीमत वसूले जाने को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।डिब्रूगढ़ के विभिन्न सामाजिक संगठनों और यात्रियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, महानिदेशालय नागरिक उड्डयन तथा संबंधित एयरलाइंस से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत किराया लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि आपदा के समय आवश्यक यात्रा को आम लोगों की पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए।

डिब्रूगढ़ के डीसी विक्रम कोइरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया व्यापक दौरा, राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 22 जुलाई। डिब्रूगढ़ के जिला आयुक्त विक्रम कोइरी ने बुधवार को जिले के बाढ़ प्रभावित भोगामुर ब्लॉक, कुटोहा तथा आसपास के प्रभावित गांवों का व्यापक दौरा कर बाढ़ की मौजूदा स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों तथा प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान डीसी विक्रम कोइरी के साथ डिब्रूगढ़ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अधिकारी, खोवांग सम जिला आयुक्त जयंत चारण तथा अतिरिक्त जिला आयुक्त देव नारायण हजारिका भी मौजूद रहे। अधिकारियों की टीम ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया तथा राहत एवं बचाव अभियानों की प्रगति का स्थल पर मूल्यांकन किया। डीसी ने स्थानीय ग्रामीणों एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा राहत वितरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्य सामग्री, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षित आश्रय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हर प्रभावित परिवार तक समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए।निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम ने राहत शिविरों, बचाव व्यवस्था तथा संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को सहायता के लिए इंतजार न करना पड़े।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाढ़ की स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है तथा राहत एवं बचाव कार्य पूरी गंभीरता से जारी हैं। प्रशासन का उद्देश्य प्रभावित लोगों की सुरक्षा, राहत और कल्याण सुनिश्चित करना है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों से संपर्क करें।

लाहोवालमोहनबाड़ी मार्ग पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग
मोटरसाइकिल सवार रंटू गोगोई के पैरों में लगी गोलियां; दो वाहनों में सवार हमलावर फरार

कार्यालय संवाददाता

डिब्रूगढ़, 22 जुलाई। डिब्रूगढ़ जिले के लाहोवाल क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लाहोवाल मोहनबाड़ी मार्ग पर अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल सवार चाबुआ के टेंगाखात निवासी रंटू गोगोई को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। हमले में रंटू गोगोई गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर दो वाहनों में सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा- तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में भय व्याप्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रंटू गोगोई अपनी मोटरसाइकिल से लाहोवालमोहनबाड़ी मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें रोकने या उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद अचानक उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमला बेहद सुनियोजित प्रतीत होता है और हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से दो अलग-अलग वाहनों में बैठकर फरार हो गए। घटना में रंटू गोगोई के दोनों पैरों में गोलियां लगीं, जिससे वह सड़क पर ही गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, हालांकि वे अभी भी चिकित्सकीय निगरानी में हैं। घटना के दौरान उन्हें अन्य मामूली चोटें भी आई हैं।सूचना मिलते ही लाहोवाल पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है ताकि हमलावरों की पहचान और उनके भागने के मार्ग का पता लगाया जा सके। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पुलिस ने अभी तक गोलीबारी के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। जांच में आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी, आपराधिक विवाद, सुपारी किलिंग अथवा अन्य संभावित कारणों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा तथा घटना में प्रयुक्त वाहनों का भी पता लगाया जा रहा है।

तामुलपुर में जिला आयुक्त ने की समीक्षा बैठक

कोकराझाड़, 22 जुलाई (ख.सं)। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर आज तामुलपुर जिला आयुक्त कार्यालय के सभागार में जिला आयुक्त सिमी करण (आईएएस) की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और समारोह को भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने की रूपरेखा तय की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह तामुलपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गयी। बैठक में वृक्षारोपण अभियान, राष्ट्रीय गान, मार्चपास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, मैत्री फुटबॉल मैच, विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी, विशिष्ट व्यक्तियों एवं प्रतिभाओं के सम्मान समारोह सहित अनेक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गयी। इसके अलावा जनगणना-2027 के तहत एक विशेष प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। जिला आयुक्त सिमी करण ने नागरिकों से पोर्टल के माध्यम से

सेल्फ एन्यूमरेशन (स्व-गणना) प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुमन चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार फहराने, सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसकी जानकारी महकमा सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विजय बेजबरुवा ने मीडिया को दी।

स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर कसा गया शिकंजा

लमडिंग, 22 जुलाई (ख.सं)। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने कल लंका क्षेत्र में विशेष निरीक्षण एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क किनारे भोजन बेचने वाले विक्रेताओं, होटलों, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की गहन जांच की गयी। अधिकारियों ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। निरीक्षण अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिष्ठा चेतिया ने किया। उनके साथ फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला की टीम मौजूद रही, जिसका संचालन प्रयोगशाला तकनीशियन सौरव मोदक कर रहे थे। निरीक्षण दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का दौरा कर वहां की स्वच्छता व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा

कानूनी मानकों के अनुपालन का आकलन किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भोजन तैयार करने, संग्रहित करने और ग्राहकों को परोसने की पूरी प्रक्रिया में साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि खाद्य पदार्थों के दूषित होने की संभावना को रोका जा सके। अभियान के दौरान व्यवसायियों को यह भी बताया गया कि एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य है। जिन प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक अनुमति नहीं थी, उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गयी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने समाचार पत्र या अन्य मुद्रित कागज में भोजन परोसने की प्रथा पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग इंक में मौजूद रासायनिक तत्व भोजन में मिलकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए सभी प्रतिष्ठानों को केवल खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही टीम ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच संख्या और अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हों, ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी प्राप्त हो सके। निरीक्षण के दौरान फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला में उपलब्ध ऑयल टेस्टर की सहायता से खाद्य तेल की गुणवत्ता की मौके पर जांच की गयी। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल किया जा रहा खाद्य तेल निर्धारित सुरक्षा मानकों से अधिक खराब पाया गया।

तालाब में डूबने से बच्चे की मौत

कोकराझाड़, 22 जुलाई (ख.सं)। कोकराझाड़ जिले के ढोलमारा स्थित काठलगुरी में के फ्लाई ऐश (अवशिष्ट पदार्थ) वाले विशाल तालाब में डूबने से एक 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गयी। मृतक बच्चे की पहचान स्थानीय निवासी जीवन राय के पुत्र चंदन राय (8) के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार खेलते समय बच्चे की चप्पल तालाब में गिर गयी थी। उस चप्पल को उठाने के दौरान पैर फिसल जाने से बच्चा तालाब के गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। इस अकाल मृत्यु से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गयी है। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने तालाब पर तैनात जवानों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जमकर रोष व्यक्त किया और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि इतने बड़े और खतरनाक फ्लाई ऐश तालाब के चारों ओर सुरक्षा के लिए कोई बैरिकेडिंग या दीवार नहीं बनायी गयी है, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

अवैध यूरिया खाद के साथ चार गिरफ्तार

सिलचर, 22 जुलाई (ख.सं)। गुप्त सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने लैलापुर में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान दो ट्रकों को रोककर तलाशी ली गयी। इस दौरान बिना वैध दस्तावेज के ले जाये जा रहे दो ट्रकों से भारत यूरिया के 1,050 बोरे जब्त किये गये। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच कर रही है।

कछार में 1.2 करोड़ की हेरोइन जब्त, एक बंदी

सिलचर, 22 जुलाई (ख.सं)। कछार जिले के जिरीघाट में आज दोपहर एंटी-नारकोटिक्स ऑपरेशन में बदल गयी, जब असम रायफल्स के सतर्क जवानों ने संदिग्ध ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की। चलाये गये अभियान के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया और लगभग 234 ग्राम हेरोइन वाले 20 साबुन के डिब्बे बरामद किये गये, जिनकी कीमत 1.2 करोड़ रुपये आंकी गयी है। इस ऑपरेशन में एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक मोबाइल हैंडसेट भी जब्त किया गया, माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल तस्करी के सामान को लाने-ले जाने में किया गया था। पकड़े गये व्यक्ति को बरामद नशीले पदार्थों के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया।

सुरंग निर्माण हादसे में गोहपुर के व्यक्ति की मृत्यु

गोहपुर, 22 जुलाई (ख.सं)। सिक्किम में एनएचपीसी के लिए सुरंग निर्माण कार्य में तैनात गोहपुर के एक युवक की हादसे में मौत हो गयी। मृतक की पहचान गोहपुर उप-मंडल के बाकरी दलनी गांव पंचायत के अंतर्गत बेकिजान निवासी बाबुल बरदलै (37) के रूप में हुई है। बाबुल अपने पीछे आठ वर्षीय बेटे, चार महीने की गर्भवती पत्नी जुलीमणि कटकी, माता-पिता और एक भाई को छोड़ गये हैं। उनकी असामयिक मौत की खबर से पूरे गोहपुर में शोक की लहर है। बताया गया है कि बाबुल बरदलै वर्ष 2005 से सिक्किम में काम कर रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए उन्होंने करीब 21 वर्षों तक सिक्किम में काम किया। शुरुआत में मजदूर के रूप में काम करने वाले बाबुल बाद में सुपरवाइजर के पद तक पहुंचे थे।

सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

सिलचर, 22 जुलाई (ख.सं)। सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी ने कछार जिला आयुक्त को आठ सूत्री मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विभिन्न लंबित नागरिक मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग की गयी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सजल आचार्य के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि सिलचर को हाल ही में नगर निगम का दर्जा दिया गया है, लेकिन अप्रैल 2020 में नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से निगम चुनाव नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की कमी के कारण नागरिक सेवाओं, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में बाधा आ रही है। इस ज्ञापन में शहर

की कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर किया गया है। इनमें थोड़ी सी बारिश के बाद भी विभिन्न वार्डों में जलभराव, शुद्ध पेयजल की अनियमित आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि, जर्जर सड़कें और खराब जल निकासी व्यवस्था, निर्वाचित बोर्ड के बिना नगरपालिका कर में वृद्धि के आरोप, नगरपालिका निधि के व्यय में पारदर्शिता की कमी, बढ़ता यातायात जाम और युवाओं में नशीली दवाओं की लत और असामाजिक गतिविधियों का प्रसार शामिल हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन से 8 सूत्री मांगें रखी गयी। इन मांगों में नालियों की सफाई और स्थायी जलभराव की समस्या के समाधान के लिए योजना अपनाना, सभी वार्डों में शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति, बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी निगरानी, क्षतिग्रस्त सड़कों और नागरिक बुनियादी ढांचे का शीघ्र जीर्णोद्धार, 2020 से मार्च 2026 तक नगरपालिका के व्यय खाते का प्रकाशन, यातायात जाम के समाधान के लिए प्रभावी यातायात योजना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, नशा-विरोधी अभियान को मजबूत करना और जन जागरूकता बढ़ाना, और सिलचर नगर निगम का शीघ्र चुनाव कराकर लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन को बहाल करना शामिल है। ज्ञापन के अंत में जिला कांग्रेस ने आशा व्यक्त की कि जिला आयुक्त राहुल कुमार गुप्ता इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जनहित में शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएंगे।

बाल विवाह करने पर वार्ड सदस्य ने गंवायी सदस्यता

नगांव, 22 जुलाई (ख.सं)। बाल विवाह में शामिल होने के कारण नगांव जिले के महेरीपार ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य आजिजुर रहमान को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। जिले के बगरीगुरी विकास खंड के अंतर्गत महेरीपार ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 से निर्वाचित सदस्य पर चुनाव के दौरान दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप लगा था। जिला आयुक्त के निर्देश पर की गयी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह नाबालिग अवस्था में ही एक संतान के पिता बन गये थे। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उनका जन्म 31 जनवरी 1999 को हुआ था जबकि उनकी पहली संतान का जन्म 7 अगस्त 2016 को हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि पहला संतान के जन्म के समय उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट तथा सहायक आयुक्त की जांच में भी इस तथ्य की पुष्टि होने के बाद जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार आजिजुर रहमान की ग्राम पंचायत सदस्यता रद्द कर दी गयी।

तेजपुर राउंड टेबल 351 की 5वीं वार्षिक आम सभा संपन्न

तेजपुर, 22 जुलाई (ख.सं)। तेजपुर राउंड टेबल 351 ने वर्ष 2025-26 की अपनी 5वीं वार्षिक आम सभा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। निवर्तमान चेयरमैन विशाल बोरा ने वर्षभर के दौरान टेबल द्वारा किये गये विभिन्न सेवा प्रकल्पों, उपलब्धियों एवं गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पुरस्कार वितरण समारोह में शिवम चंदक को बेस्ट फ्लोर टैबलर अवॉर्ड तथा पुनीत जैन को बेस्ट डेब्यूटेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। आशीष सोनी, जयंत टिबड़ेवाला, कार्तिक दुग्गड़ एवं चेतन सराफ को फोर पिलर्स ऑफ द टेबल के रूप में सम्मानित किया गया। स्क्वॉयर लेग वरुण अग्रवाल को जुलाई 2026 स सक्रिय टैबलिंग से सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में लेजेंडरी अवॉर्ड एवं रिटायरमेंट प्लाक प्रदान किया गया। एजीएम के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए नयी हेड बोर्ड का भी विधिवत स्थापना समारोह आयोजित किया गया। जयंत टिबड़ेवाल ने टेबल चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। तीर्थ राज भूतोड़िया को टेबल सेक्रेटरी, पुनीत जैन को वाइस चेयरमैन, विशाल बोरा को इमीडिएट पास्ट चेयरमैन तथा यश झाबक को

ट्रेजरर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों को विभिन्न दायित्वों एवं समितियों का संयोजक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर एरिया 14 के एरिया चेयरमैन चंद्रकांत वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गुवाहाटी से देवांशु स्वामी एरिया ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुए जबकि तिनसुकिया से सिद्धांत लोहिया एवं एरिया 14 के एरिया चेयरमैन-इलेक्ट ट्. चेतन सराफ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एजीएम में जयंत टिबड़ेवाल, आशीष सोनी, विशाल बोरा, तीर्थ राज भूटोरिया, पुनीत जैन, चेतन सराफ, अंकित सेठिया, शिवम चंदक, स्क्वॉयर लेग वरुण अग्रवाल एवं यश झाबक सहित नगांव, गुवाहाटी एवं डिब्रुगढ़ से आये अनेक टैबलर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन गणमान्य अतिथियों के प्रेरणादायक संबोधनों के साथ हुआ। सभी अतिथियों ने उत्कृष्ट आयोजन एवं आतिथ्य की सराहना की। एरिया ऑब्जर्वर एलएमएफ देवांशु स्वामी ने वार्षिक आम सभा को आधिकारिक रूप से वैध घोषित करते हुए तेजपुर राउंड टेबल 351 को एक और सफल एवं यादगार टैबलिंग वर्ष पूर्ण करने पर बधाई दी।

नलबाड़ी में पीएम अजय योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरित

नलबाड़ी, 22 जुलाई (ख.सं)। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति पीएम अजय योजना के तहत आज नलबाड़ी जिले की अनुसूचित जाति की महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय अनुदान के स्वीकृति पत्र वितरित किये गये। स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम आज नलबाड़ी जिला पुस्तकालय सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में निम्नलिखित विशिष्ट जन उपस्थित रहे । नलबाड़ी के जिला आयुक्त निवेदन दास पटवारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव सह अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की निदेशक डॉ. कुलश्री नाथ, नलबाड़ी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ध्रुवज्योति हजारिका, जिला कृषि अधिकारी समाजसेवी जयंत बुजरबरुवा, जिला

परिषद अध्यक्ष गीतुमणि वैश्य, असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला योजना प्रबंधक शिवालिका मेधी उपस्थित थे। कार्यक्रम में 147 अनुसूचित जाति महिला स्वयं सहायता समूहों और 15 महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से सब्सिडी (अनुदान) के स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये। इनमें से आज औपचारिक रूप से 6 स्वयं सहायता समूहों और 1 महिला को स्वीकृति पत्र सौंपे गये। कार्यक्रम में जिला आयुक्त निवेदन दास पटवारी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि महिलाएं आज कमजोर नहीं हैं, बस उन्हें खुद को सशक्त समझना होगा। आज नलबाड़ी की महिलाएं केंचुआ खाद बेचकर न केवल खुद स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं बल्कि दस अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। इसलिए महिलाओं को खुद को कमजोर न मानकर आगे आना चाहिए। मुख्य अतिथि डॉ. कुलश्री नाथ ने कहा कि जिन महिलाओं को यह 50000 की सब्सिडी मिली है, वे इस राशि का उपयोग अपने व्यावसायिक कार्यों में करें। डॉ. नाथ ने यह भी कहा कि जब वे इस पैसे का सही और उत्पादन-उन्मुख कार्यों में उपयोग करेंगी, तभी पीएम अजय योजना वास्तव में सफल होगी और पैसे का मिलना सार्थक होगा। कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवी जयंत बुजरबरुवा और जिला परिषद अध्यक्ष गीतुमणि वैश्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

नीट परीक्षा में सफल मेधावी छात्र का अभिनंदन

कोकराझाड़, 22 जुलाई (ख.सं)। नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने वाले दीप कुमार नाथ के आवास पर आज अखिल असम बंगाली छात्र फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और उन्हें सम्मानित किया। दीप कुमार नाथ पान किष्णो देबनाथ और सुप्रिया देबनाथ के पुत्र हैं। संगठन के सदस्यों ने मेधावी छात्र दीप कुमार नाथ को जातीय गामोछा और मानपत्र भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अखिल असम बंगाली छात्र फेडरेशन की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष गोपाल घोष, महासचिव इंद्रजीत देबनाथ, कोकराझाड़ जिला समिति के महासचिव देब सरकार और बंगाली टाइगर फोर्स के कोकराझाड़ जिला समिति के सचिव अरबिंद देबनाथ सहित कई अन्य संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।